SikhMuseum.com

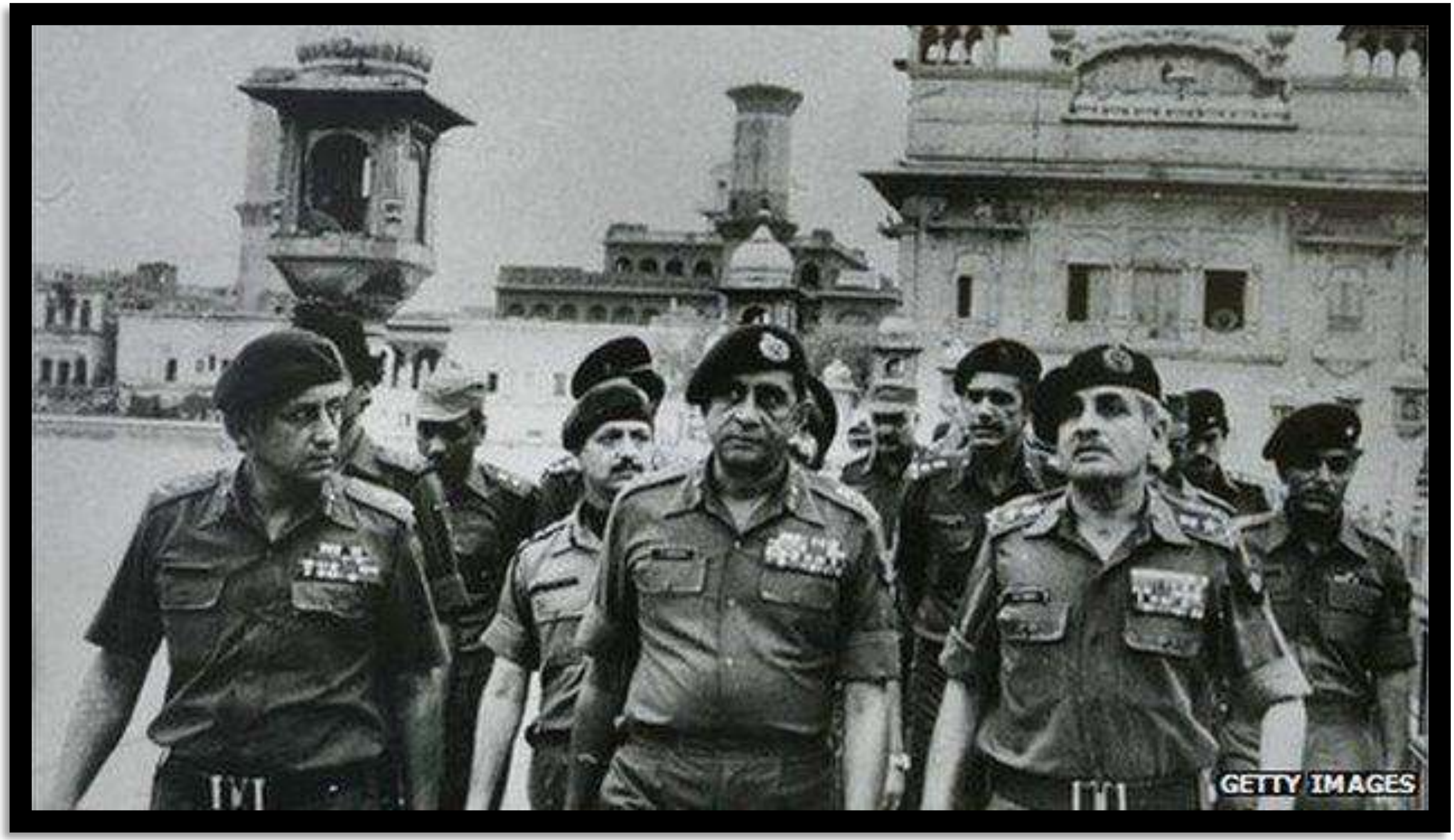
GETTY IMAGES

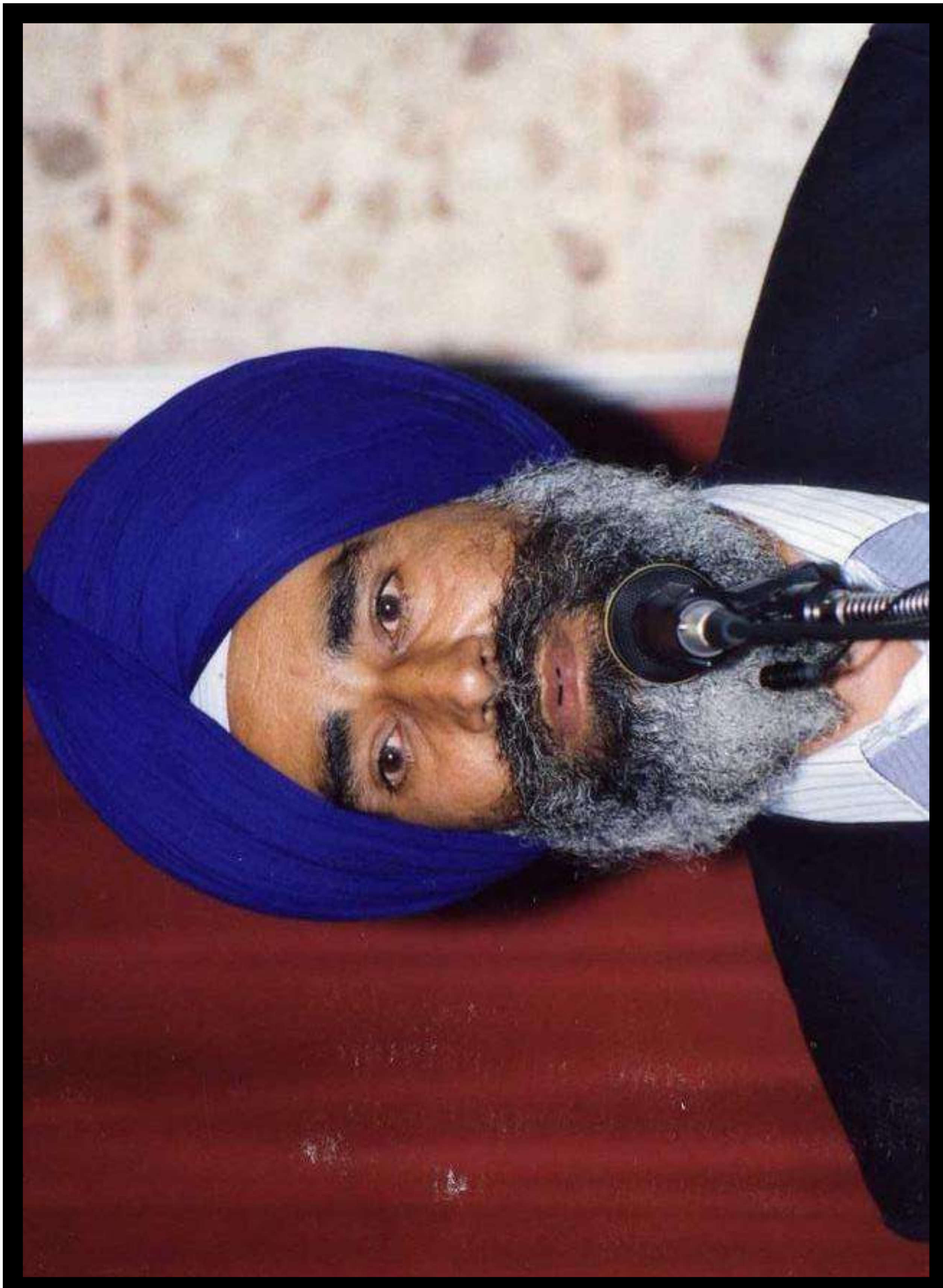

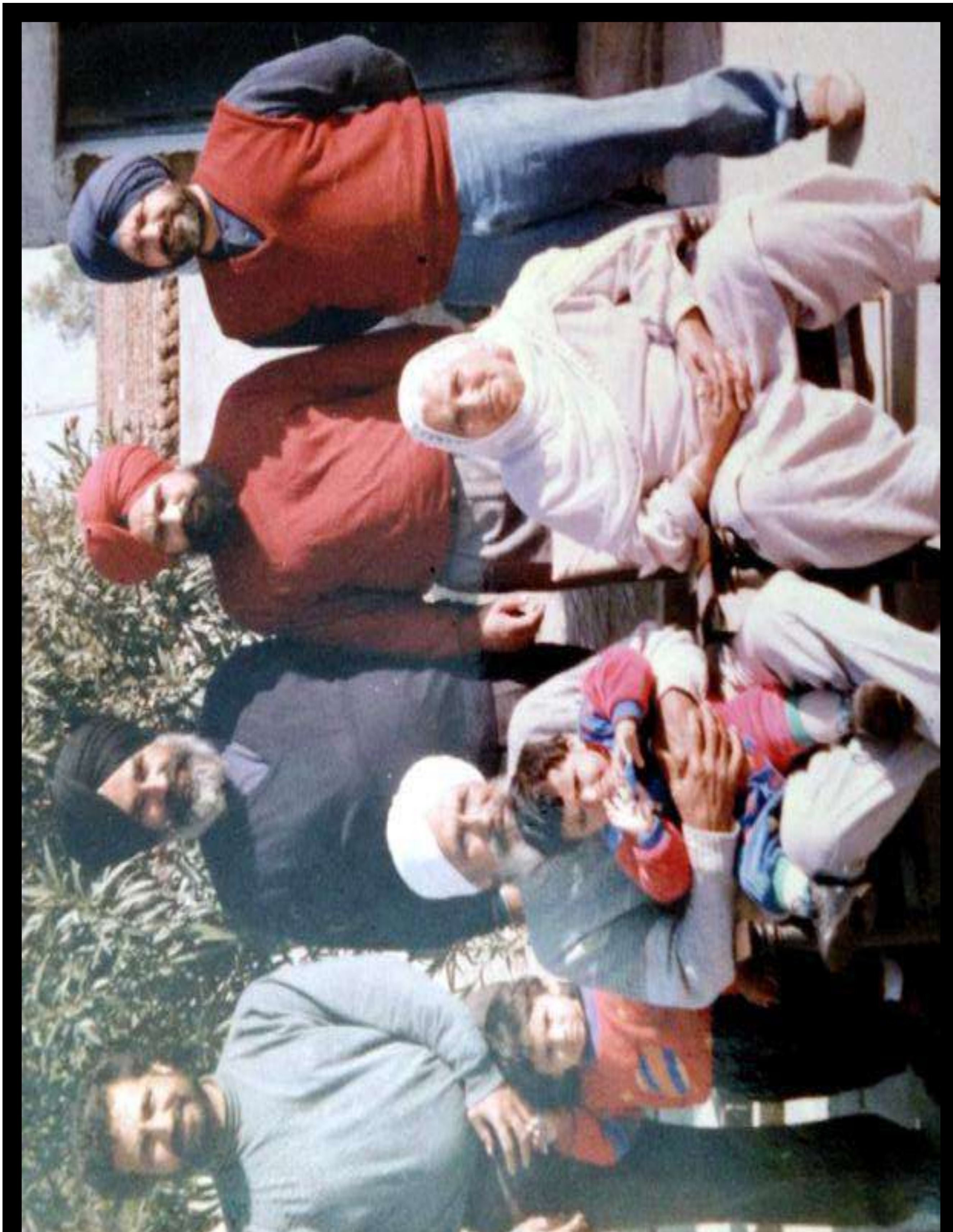

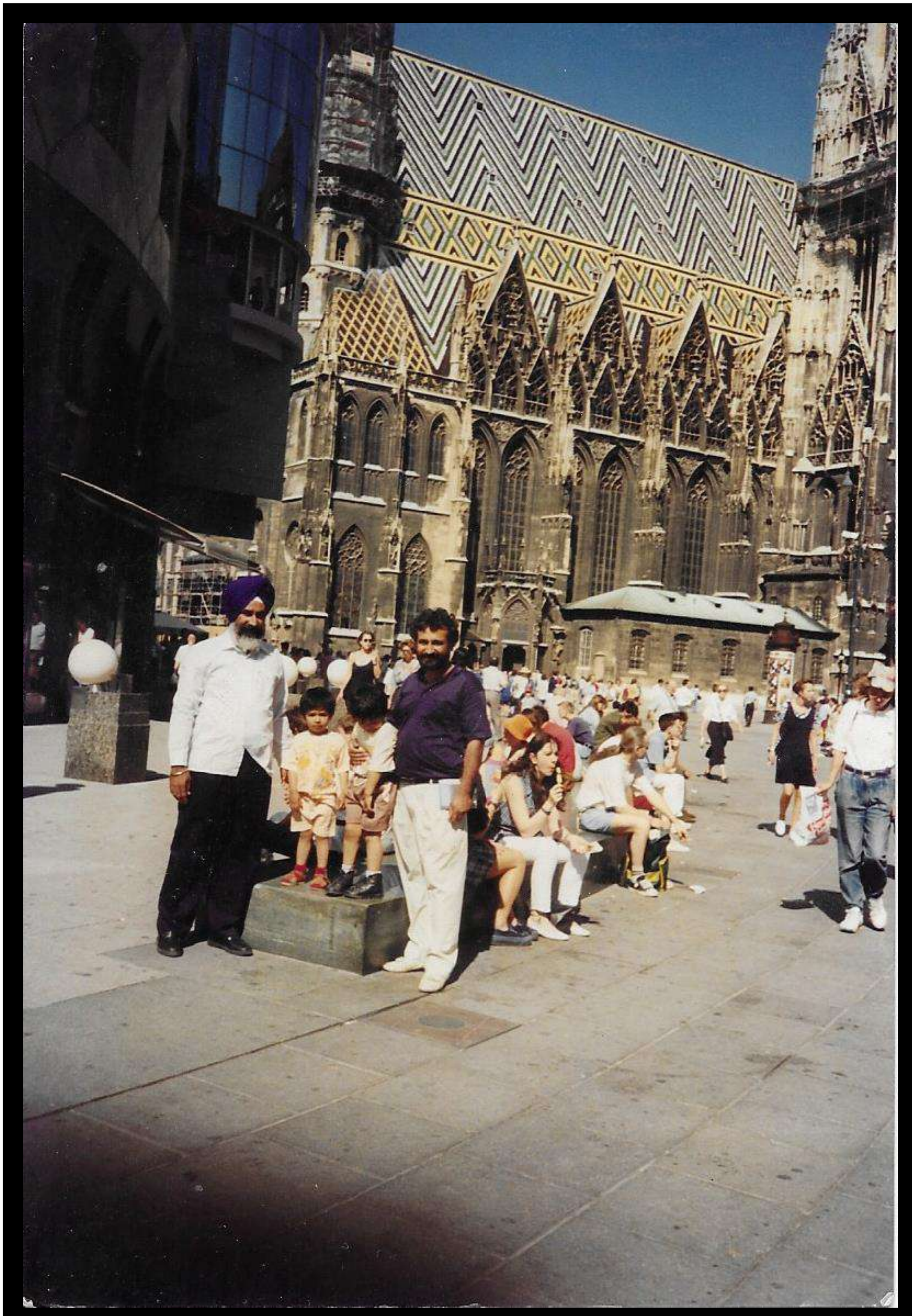

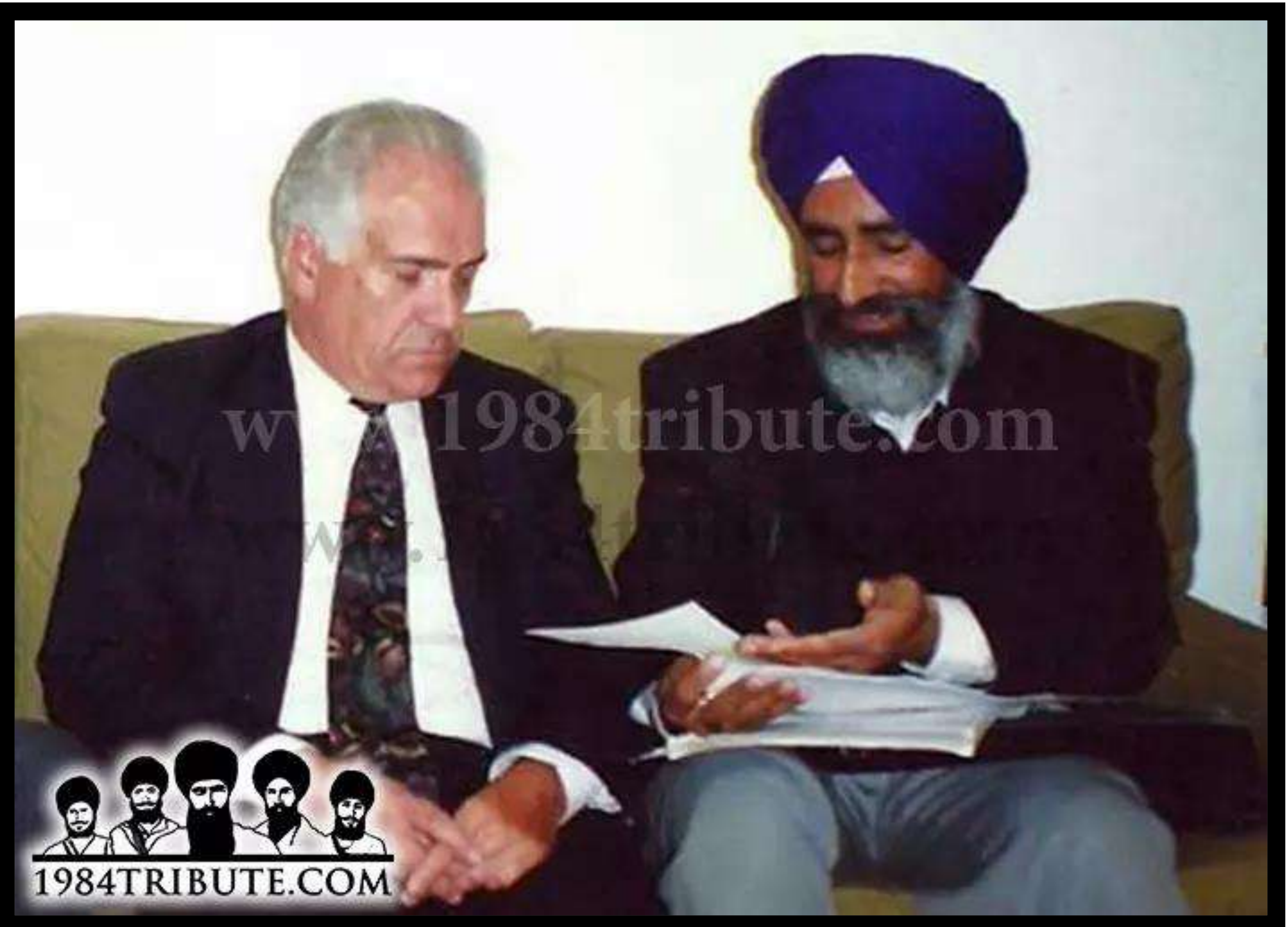
www.1984tribute.com
1984TRIBUTE.COM

1984TRIBUTE.COM
ਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ

1984TRIBUTE.COM

SIKHS

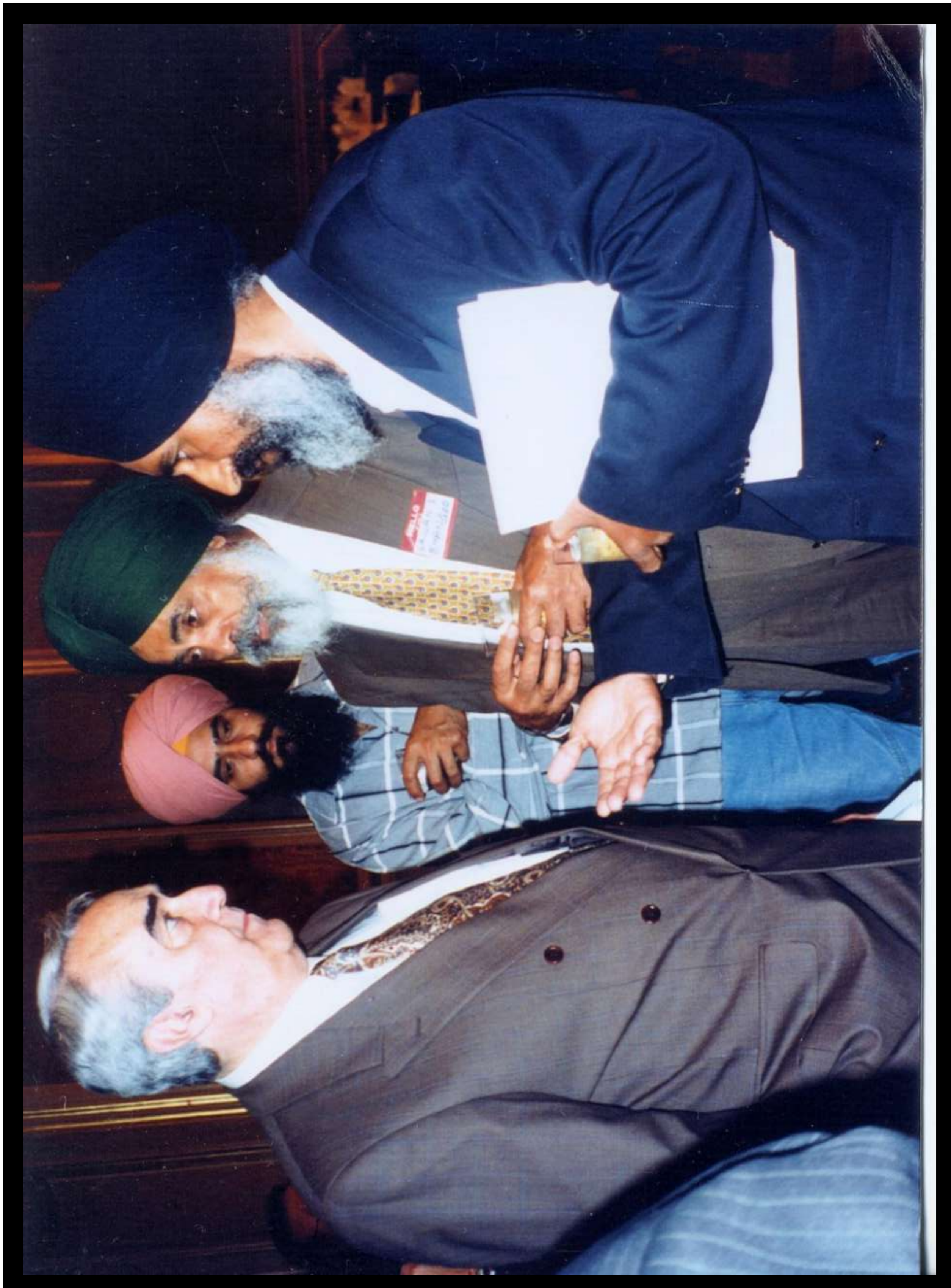

CBI INQ
OF ADV
HUM

NO ENTRY
FOR GENERAL
PUBLIC

"Disappeared"

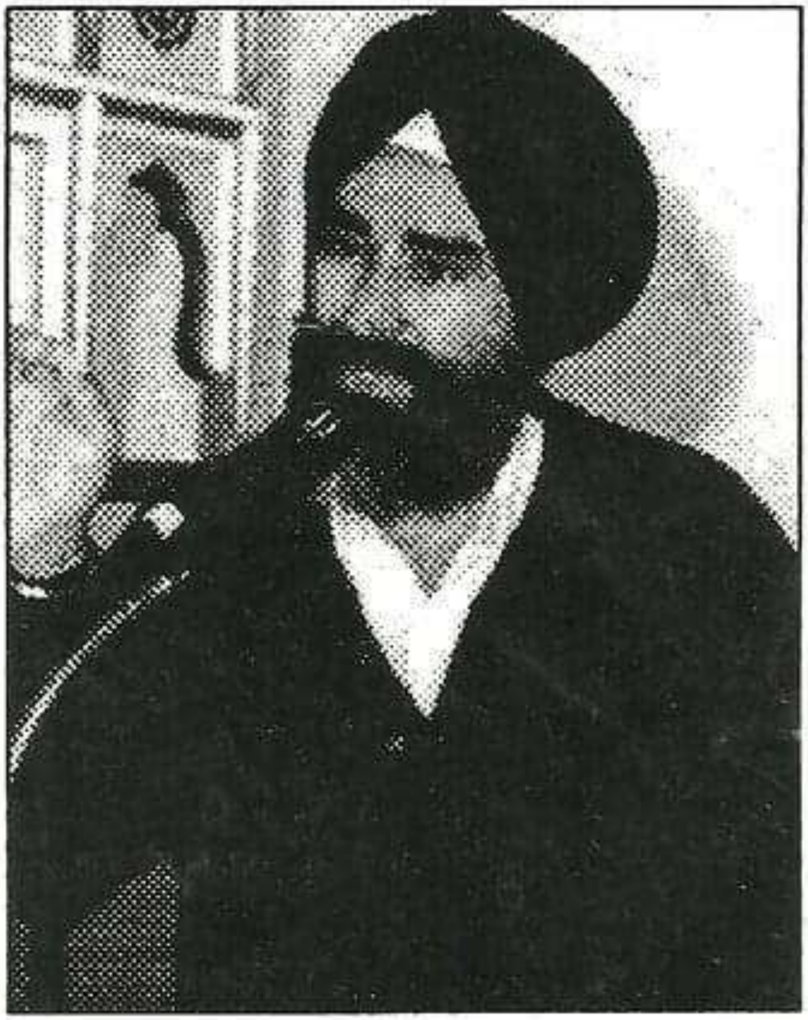

Jaswant Singh Khalra

has not been seen since September 6, 1995
when he was picked up by Punjab police at
home in Kabir Park, Amritsar.

4 July 1992

मिलिटैंटों से दोस्ती का परिणाम कितना विनाशकारी होताहै—बैहला कांड से सबक सीखें

जतिन्द्र पन्नू लिखते हैं

1967 के चुनाव में तरनतारन से चुने गए अकाली उम्मीदवार सरदार हरजिंदर सिंह बैहला की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। उनके बाद हुए उप-चुनावों में अकाली दल ने उनके सबसे छोटे भाई मनजिंदर सिंह को ला खड़ा किया। जो अकाली तो क्या सिख भी नहीं लगता था, पर यह नया-नया बना अकाली अपने अकाली दल के बजाए अपने परिवार के प्रभाव (या दबदबे) के कारण यह सीट जीत गए।

1977 में जनता व अकाली लहर चल रही थी। तरनतारन से कांग्रेस ने पूर्व परिवहन मंत्री श्री दिलबाग सिंह को खड़ा किया था और अकाली दल की ओर से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान सरदार प्रेम सिंह लालपुरा उम्मीदवार थे। सरदार मनजिंदर सिंह बैहला आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में आ कूदे और कुछ वोटों से दोनों उम्मीदवारों को हरा कर विधानसभा में पहुंच गए। इतने प्रभावशाली व दबदबे वाले परिवार की आज क्या हालत है ?

सरदार मनजिंदर सिंह पिछले 3-4 साल से अपने गांव जाने की हिम्मत नहीं कर सके। चीनी कहावत है कि किसी लड़के को डराने के लिए उसके सामने मुर्गे को मार दो। सरदार मनजिंदर सिंह को डराने के लिए मिलिटैंटों ने पहले तो गांव में उनके अस्तबल से निकाल कर उनका बढ़िया नस्ल का घोड़ा मार दिया और फिर उस घोड़े की देखरेख करने वाले डाक्टर को। सरदार मनजिंदर सिंह इस इशारे को किस प्रकार नहीं समझते ?

उनके भाई सरदार गुरमहेन्द्र सिंह ने भाई के साथ हुए अपने झगड़े में जाकर मदद मांगी अपने ही गांव के एक मिलिटैंट सरगने से। इसके कारण वह आज दुखद स्थिति में पहुंच चुके हैं। पिछले दिनों वह तरनतारन में जब इस लेखक से मिले तो उन्होंने आंखों में आंसू भरे हुए अपनी बात यहां पर आकर समाप्त की कि सुरजीत (बैहले) का पिता तिरलोक सिंह हमारा ड्राइवर होता था और उसी ड्राइवर का बेटा हमारे घर में क्या बन कर रहता रहा, यह मुख से नहीं कहा जा सकता।" यह शब्द उस गुरमहेन्द्र सिंह के थे, जिसका किसी ने कभी नाम नहीं लिया था और जिन्हें सिर्फ गुरु जी या गुरु कह कर पुकारा जाता था।

इस दुखांत स्थिति से पर्दा तब उठा जब पिछले महीने गांव बैहला में स्थित उनकी कोठी में बंकर बना कर बैठे हुए मिलिटैंटों में से 8 मिलिटैंट 28 घंटे के मुकाबले के बाद मारे गए।

इस घटना के बाद मिलिटैंटों का समर्थन करने के लिए हर समय तैयार रहने वाले कुछ क्षेत्रों ने झूठे किस्से उछालने शुरू किए और ऐसा वातावरण बनाया जिससे ऐसा लगे कि मरने वाले दोनों मिलिटैंट बड़े बहादुर थे तथा उन्होंने 28 घंटे पुलिस का मुकाबला किया और दूसरी ओर ऐसा लगे कि पुलिस व सुरक्षा बल इतने घटिया स्तर पर उतर आए थे कि उन्होंने 6 निर्दोष लोग अपनी जान बचाने के लिए ढाल बना कर मरवा दिए।

बैहला कांड में मरने वालों में सुरजीत सिंह बैहला जो भिंडरांवाला टाइगर्स फोर्स के मानोचाहल ग्रुप का 'डिप्टी चीफ' था तथा उसके साथ मदनजीत सिंह उर्फ मट्टी उर्फ छोटा बैहला के बारे में लिखने की कुछ जरूरत नहीं रह जाती है। उनके बारे में कहीं गई बातों को मिलिटैंटों के समर्थक शुरू से ही मानते हैं। बाकी जिनको बेगुनाह बताया जा रहा है, उनमें हरजस सिंह सरहाली के बारे में भी कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती, जब मानोचाहल द्वारा उसके भोग के सम्बन्ध में जारी किए गए इश्तहारों आदि में ही उसका मिलिटैंट होना स्वीकार कर लिया गया था।

जहां तक औरों का सम्बन्ध है, उनमें से हरेश के बारे में पुलिस का रिकार्ड बोलता है। जिस निरंजन सिंह और उसके पुत्र सकत्तर सिंह के बारे में कहा गया कि वह कोठा ठीक कर रहे थे जब पुलिस ने पकड़ कर उन्हें आगे कर लिया था। पुलिस के रिकार्ड के अनुसार यह दोनों पहले ही हत्याओं तथा अन्य अपराधों के मामलों में पहले से ही अभियुक्त घोषित थे। पुत्र सकत्तर सिंह की नामजदगी हत्या व लूटपाट के 22 मामलों में थी और पिता निरंजन सिंह ऐसे ही 20 मामलों में संलिप्त था। इसी प्रकार रेहड़ेवाला अजीत सिंह भी कई हत्याओं सहित 20 मामलों में पुलिस को वांछित था।

गांव बनवाली (बरपाल) का लखविंदर सिंह और बरपाल गांव का करतार सिंह भी पुलिस को अपराधों के कई मामलों में वांछित था लेकिन दुख की बात है कि इन मिलिटैंटों की 'बहादुरी' के गीत गाने वालों ने उस परिवार की दुखद हालत के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जिनके घर में यह मिलिटैंट अपने दरबार सजाते थे, कैदखाना भी बनाए हुए थे तथा हत्या स्थल भी।

तरनतारन के तहसील कार्यालय का रिकार्ड बताता है कि घरेलू झगड़ों के कारण मिलिटैंटों की मदद मांगने वाले गुरमहेन्द्र सिंह की जायदाद इन मिलिटैंटों ने अपने नाम या अपने लोगों के नाम करवाने के हुक्म किस तरह लागू करवाए।

मिलिटैंट ग्रुप के एक बड़े 'जरनैल' सुरजीत सिंह बैहला के परिवार ने एक पैसा भी दिए बिना गुरमहेन्द्र सिंह से कितनी जमीन हड़पी, इसका विवरण देना तो मुश्किल है लेकिन आखिरी रजिस्ट्री सुरजीत सिंह बैहला के पिता तिरलोक सिंह के नाम गुरमहेन्द्र सिंह ने बैहला कांड से सिर्फ 10 दिन पहले 27.5.92 को करवाई थी और उसी दिन कुछ और जमीन बैहला गांव के ही एक और आदमी जोगेन्द्र सिंह के नाम पर सुरजीत सिंह बैहला के कहने पर की गई। तिरलोक सिंह के नाम की रजिस्ट्री में गवाही जोगेन्द्र सिंह की है और जोगेन्द्र सिंह की रजिस्ट्री में गवाही तिरलोक सिंह की है। इनमें से एक रजिस्ट्री नम्बर 904 तथा दूसरी 905 में दर्ज है।

मदनजीत मट्टी उर्फ छोटा बैहला का असली नाम सुखदेव सिंह (पुत्र संतोख सिंह) था। उसके और उसके 2 भाइयों कुलदीप सिंह और कुलबीर सिंह के नाम 30 कनाल जमीन की एक रजिस्ट्री 27.12.91 को हुई थी। जिस पर मट्टी के भगौड़ा होने के कारण उसके पिता संतोख सिंह ने दस्तखत किए थे।

31 कनाल 11 मरले भूमि की एक और रजिस्ट्री इन तीनों भाइयों के नाम गुरमहेन्द्र सिंह ने 14.2.92 को की थी। इस पर दस्तखत मट्टी के भाई कुलबीर सिंह ने अंग्रेजी में किए थे।

जिस सकत्तर सिंह और निरंजन सिंह को निर्दोष बताया जा रहा है, उनके बारे में भी विवरण पढ़ लें।

30.9.91 को बैहला खानदान की जायदाद के 16 कनाल के एक भूखंड को गुरमहेन्द्र सिंह ने सकत्तर सिंह, सुखचैन सिंह (जो मुकाबले में जख्मी हुआ था) और बिरबैर सिंह (यह सभी निरंजन सिंह के पुत्र हैं) के नाम गुरमहेन्द्र सिंह ने रजिस्ट्री करवाई थी। इस भूमि की कीमत 80 हजार रुपए दिखाई गई।

उसके बाद 29.10.91 को एक और रजिस्ट्री की गई तथा इसके बाद तीसरी रजिस्ट्री 13.12.91 को 1.18 लाख रुपए की की गई। इन तीनों ही रजिस्ट्रियों में गुरमुखी में ही दस्तखत किए गए थे। अब इस बात का कोई जवाब मिल सकता है कि एक गरीब दोधी सकत्तर सिंह के परिवार के पास इतना रुपया अचानक कहां से आ गया कि वह दो-ढाई महीने के अंदर-अंदर ढाई लाख रुपए की जमीन खरीद ले।

गुरमहेन्द्र सिंह का 24 किले जमीन में फैला हुआ बाग, आढ़तों व नीचियों के बाग को भी सुरजीत बैहला के परिवार ने अपने कब्जे में ले लिया था, भले ही उसका स्वामित्व अभी गुरमहेन्द्र सिंह के पास ही है।

आखिरी बचा हुआ ढाई किले जमीन का टुकड़ा भी अजीत सिंह रेहड़ेवाले के नाम करने का हुक्म सुरजीत बैहला की ओर से जारी हो गया तो गुरमहेन्द्र सिंह ने विवश होकर पुलिस को इस गिरोह के बारे में जानकारी दी। जिसके परिणामस्वरूप मिलिटैंटों का यह टोला मारा गया। यह कहानी केवल इसी परिवार की नहीं बल्कि माझे के गांव-गांव की कहानी है।

चाहे कुछ अखबारों में कहानियां कुछ भी छपती हों लेकिन स्थानीय लोग वास्तविकताओं से अनभिज्ञ नहीं हैं और यही कारण है कि बैहला कांड पर रोष प्रकट करने के लिए किए गए आह्वान पर किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। छब्बे व डीम के भोग के समय यह रिपोर्ट छपी थी कि लोग सड़कों पर धरने मार कर बैठे थे। (हालांकि वे खुद नहीं आए थे बल्कि लाए गए थे।) बैहला कांड के विरोध में किसी ट्राली या ट्रक के बैहला गांव की ओर जाने या लोगों द्वारा पुलिस के विरुद्ध रोष प्रकट करने की खबर किसी भी अखबार में नहीं छपी। उलटे स्थानीय निवासियों ने कम से कम तीन स्थानों पर इस नाटक में शामिल होने के लिए आ रहे अकाली नेताओं के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करने की दिलेरी दिखाई। 6 पंथक संगठनों की ओर से पंजाब भर से 'बैहला पहुंचने' के आह्वान का यह हाल था कि एक भी ट्रक बैहला में किसी ओर से भी नहीं आया।

जो अकाली नेता आए भी, उनमें से सिमरनजीत सिंह मान तो एक दिन पहले गिरफ्तार होकर बल्टोहा के रैस्ट हाउस में जा बैठे। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर तो तरनतारन में एक अधिकारी के दफ्तर से ही बाहर नहीं निकले पर जत्थेदार मोहन सिंह भटिया तरनतारन पहुंचे तो वह नारे लगाते हुए घुस कर जोश में आ गए। कार में से निकल कर वह 'मुर्दाबाद' के नारे लगाने वालों के बीच में जा फंसे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि नारे लगा रहे लोग पुलिस के विरुद्ध नहीं बल्कि अकाली नेताओं के विरुद्ध नारे लगा रहे थे और रोष प्रकट कर रहे लोगों से अपनी जान बचाने के लिए उन्हें उसी पुलिस की मदद लेनी पड़ी जिसके विरुद्ध वे रोष प्रकट करने आए थे।

पंजाब के मौजूदा हालात में बहुत कुछ हैरान करने वाली घटनाएं घट रही हैं। शंका की गुंजाइश तो हर मामले में कुछ न कुछ रह ही जाती है और ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो कि इस मौके की ताक में रहते हैं कि कब झूठ को सच और सच को झूठ बना कर लोगों के सामने पेश किया जाए।

पिछले दिनों तरनतारन तहसील के डोडिया गांव का एक युवक पुलिस के साथ मुकाबले में मारा गया। अमृतसर जिले के जिस दुरस्थ स्थान पर वह मुकाबले में मारा गया था, वहां न तो उसकी कोई रिश्तेदारी थी और न ही कोई कामकाज था। उसके मारे जाने का भी उसके गांव वालों को पता नहीं था। उसके भोग के बारे में छपे एक भोग के इश्तहार और उसी दिन छपे एक समाचार से गांव के लोगों को पता चला कि वह मिलिटैंट था और कुछ मिलिटैंटों के साथ जम्मू-कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान जा रहा था और पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। यदि वह युवक अपने गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा जाता तो शायद उसे भी निर्दोष करार देने का प्रयास किया जाता और उसके गांव वाले भी यह मानने को तैयार नहीं होते कि वह मिलिटैंट था।

पीलीभीत में 10 मिलिटैंटों के मारे जाने पर कुछ क्षेत्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया था और यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि मरने वाले तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। इस सम्बन्ध में गुरदासपुर के पुलिस प्रमुख ने स्पष्टीकरण जारी किया था कि उन मृतकों में से 8 पंजाब में विभिन्न गम्भीर अपराधों में पुलिस को वांछित थे तथा दो के सिर पर तो इनाम भी था। यह बात भी अनदेखी कर दी गई थी कि इनमें से कुछ के नाम से तो मिलिटैंट संगठनों के प्रैस नोट व भोग के इश्तहार भी छपते रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके मिलिटैंट संगठन द्वारा कही गई इस बात को भी अनदेखा कर दिया गया कि यह मिलिटैंट तराई में किसी विशेष लक्ष्य की हत्या करने के लिए गए थे और उनकी मौत का बदला अगले ही दिन पीलीभीत के निकटवर्ती जिले में उनके संगठन ने 8 पुलिस वालों की हत्या करके ले लिया है।

मिलिटैंटों से चाहे कोई कितनी भी भाई बंदी दिखाए, इनकी भाई बंदी व दोस्ती किसी को भी और कभी भी महंगी पड़ सकती है। दूसरों के घर को उजड़ते देख कर खुश होने वाले स्वयं इस आग में जल चुके हैं। दूसरों को इससे सबक सीखना चाहिए।

औरों से अगर कुछ भी नहीं सीखें तो गुरमहेन्द्र सिंह के उदाहरण से सबक सीखा जा सकता है।

(जग बाणी से साभार)

ਅਜੀਤ

20 JUNE 1992

ਬਹਿਲਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਬੰਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਮਿਸਤਰੀ ਫੜੇ-ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.

ਤਰਨ ਤਾਰਨ 19 ਜੂਨ-(ਅ ਬ.) ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੁਰਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਮੈਂ ਸਰਹਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਬਕ ਸਰਪੰਚ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 25-30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ 10 ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੱਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਲੁਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿਸਤਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਲਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਬੰਕਰ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਖੰਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਦਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਜੂਨ-(ਵਿ. ਪ੍ਰ.) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੇ. ਸੋਢੀ ਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਖਾਨਖਾਨਾ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਨਖਾਨਾ ਤੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿੱਡਾ ਜ਼ਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Ajit 14 June 1992.

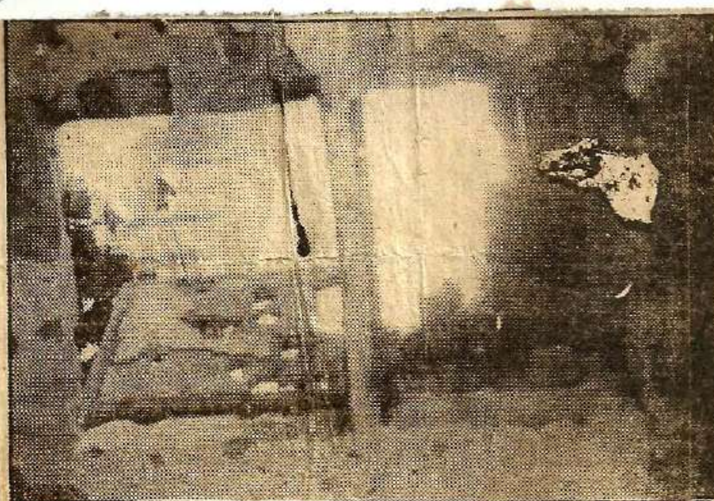

ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਉਸ ਕੋਠੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬੀ. ਟੀ. ਐਫ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਸ... ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਵਿਚ ਬਣੇ ਬੰਕਰ ਦਾ ਓਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੋ ਆਉਣ ...ਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਵਾਰਦਾਤਾਂ (ਸਫਾ 3 ਦੀ ਬਾਕੀ)

ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ (ਹਵੇਲੀ) ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਬੰਕਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।

ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸ: ਬਹਿਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ: ਬਹਿਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਕੇਵਲ ਉਥੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਲੁਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਜਿਹਾ ਬੰਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ 3 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਖਾੜਕੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਖਾੜਕੂ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦੋਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਨਿਗਲਣ ਕਾਰਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਬੰਕਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮਿਸਤਰੀ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਅਣਪ... ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ
ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਦ... ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ
ਕਰ ਲਿਆ ਅ... ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਕ ਦਰਖਤ
ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਦੇ... ਮਾਰ ਦਿਤਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਰਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਜੋੜ ਸਿ... ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ
ਕਤਲ ਦੀ ਸੂ... ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱ...

ਨਹਿਰ ਤੋੜ...
(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰ...
ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁਖ...
ਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ...
ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰ...
ਮੁਕਤਸਰ...
ਉਸ ਵਿਚ...
ਆਪਣੇ ਸਿ...
ਗੁਰਜੰਟ ਸਿ...
ਬਿਆਨ ਰ...
ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਅੰਮ੍ਰਿ...
ਮੀਟਿੰਗ ਫੋਰ...
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇ...
ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ...
ਚੰਡ, ਭਾਈ...
ਗੋਰਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼...
ਪੁਰੀਆਂ, ਭਾ...
ਏ,. ਭਾਈ...
ਖਾੜਕੂਆਂ...
ਪੀ.) ਦੇ...
ਮਾਰਨ ਦੀ...

ਅੰ...
ਮੀਟਿੰਗ...
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ...

Ajit 11 June 1992.

ਬਹਿਲਾ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਪੱਖ

ਹਰਕੰਵਲ ਕੋਰਪਾਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਜੂਨ-ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲਾ ਵਿਚ 28 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀ. ਟੀ. ਐਫ. (ਮਾਨੋਚਾਹਲ) ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਮੱਦੀ, ਉਰਫ ਛੋਟਾ ਬਹਿਲਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 4 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਵੇਲੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 'ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਲਾਜ' ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 'ਅਜੀਤ' ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਵਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇਧੀ ਪੁੱਤਰ ਬੂੜਾ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਜੰਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇਧੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਰੋਕਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਫਰਲਾਂਗ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਧ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੱਬੀ ਦਾ ਕੋਠਾ ਛੱਤ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਘੁਮਿਆਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਰਿਹੜੇ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੀਪ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਪਰਤ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰਹ ਸੀ। ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਭਾਰੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 6 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਗਊਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਰ. ਐਮ. ਪੀ. ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਧੀਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਰੇਹੜੀ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟਣ ਗਿਆ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਦੀ ਭੈਣ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਬਾਏਂ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਚੁਬਾਰੇ ਸੀ ਸਭ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਅਧਸੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ, ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿਚ ਖਿੰਡਿਆ ਸਮਾਨ, ਕੰਧਾਂ ਵਿਚ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦੋ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ 36 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਰੱਖਿਆ। ਛੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਮਘੋਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਡੋਗਰਾ ਰੈਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕਟੋਚ ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਥੇ ਦਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ

(ਬਾਕੀ ਸਫਾ 9 ਕਾਲਮ 3)

ਬਹਿਲਾ ਕਾਂਡ : ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਾਰੰਗ।

ਅਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1986 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ, ਜੋ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਕਰ ਬਣਵਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਛੇ ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅੱਠ ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਮੱਦੀ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਕਿਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਤਿਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਤਰੇ, ਆੜੂ ਅਲੀਚੀ, ਅਮਰੂਦ ਆਦਿ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਦਾ ਸਿਰਫ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਠੇਕਾ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, "1986 ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ 1989 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ [illegible]। ਉਥੇ ਉਹ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਦੇ। ਲਗਭਗ 30 ਵਿਅਕਤੀ 4-4, 5-5 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਥੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਐੱਫ ਸੀ. ਆਈ. ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਵੀ ਉਥੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ।"

ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ, "ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁਟਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਸੌਂ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਹੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਲ ਇਸ ਘਰ ਵਿਚ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ, "ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਜੋ ਬੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ, ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਦੋ ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਹੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਹੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਥਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਫੜ ਸਕੀਏ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਗਿਰੋਹ ਨੇ 1.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹਨ, 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ [illegible]। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲਾ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਹਿਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਜੂਨ-(ਯੂ. ਐਨ. ਆਈ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ: ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸੰਤ ਐਵੇਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ [illegible] ਗਿਆ ਹੈ। ਸ: ਬਹਿਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਉਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਸਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਬਹਿਲਾ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸ: ਬਹਿਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਬਹਿਲਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲਾ ਸਥਿਤ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬੀ. ਟੀ. ਐਫ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਸਮੇਤ 9 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

THE POINEER FRIDAY MARCH 27, 1992.

Evidence surfaces against police

Watery grave for Punjab militants

Naveen S Garewal

Chandigarh

PUNJAB'S IRRIGATION canals have become a dumping ground for bodies of suspected militants and their sympathisers killed in custody by the police.

Evidence of this surfaced in January when a dozen-odd bodies, some with hands and feet tied together, were fished out of the Sirhind Canal after water inflow to the canal was stopped to facilitate repair work.

The recovery of these bodies lends some credence to the hitherto unsubstantiated allegation that security personnel are killing the unlawfully arrested persons involved in the movement for 'Khalistan'.

There appears to have been a spurt in killings of this nature, just prior to the Punjab elections. The whereabouts of hundreds of such persons remain unknown. Several of them may have met with the same tragic fate, while their families continue to believe they would return one day. The recovery of bodies, invariably of Sikh youth, from the canals was brought to the notice of Prime Minister P V Narasimha Rao by three human rights organisations, the Movement Against State Repression (MASR), Punjab Human Rights Organisation (PHRO) and the Peoples' Union of Civil Liberties (PUCL), in a letter to him in January.

Independent enquiries by *The Pioneer* have yielded some horrifying facts. This correspondent travelled along the Kotla branch of the Sirhind Canal from the Moharana bridge on the Nabha-Malerkotla road to the Babanpur bridge on the Dhuri-Malerkotla road, a distance of about eight to 10 kilometres. The revelations were startling. Eyewitnesses reported that at least seven bodies were pulled out from the canal in this short stretch. To further authenticate the findings, the Buthinda branch of the same canal was checked out. The facts were similar. Both these canals pass through the Ropar, Ludhiana and Sangrur districts, which have become the main militancy-affected districts, even more than Amritsar and Gurdaspur.

According to the *baildars* of the canals and the farmers whose fields adjoin the canal, sighting of dead bodies has become common.

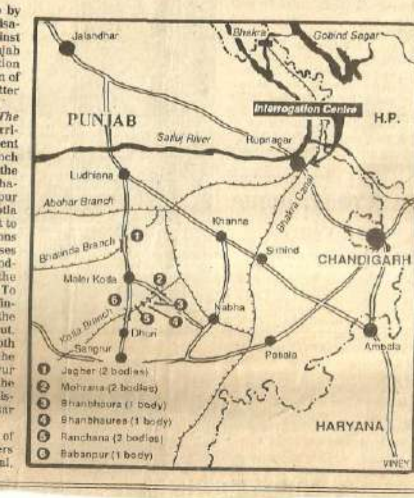

Several of them pass downstream frequently. But since the flow of the water is very fast, they rarely get entangled with the bridges en route. It is only when the flow of water in the canal is regulated for repair work that the bodies surface. In the second week of January 1992, when water releases into the canal were stopped for a few days, people saw at least dozen bodies floating.

When the bodies surfaced, the local police had no choice but to fish them out. Normally when a body is seen, the police let it float by, passing on the responsibility to the next police station. It is learnt that many bodies thrown into various branches of the canal finally reach other states. Senior Punjab Government officials admit that the Rajasthan Government has complained to the Punjab Government and expressed serious concern over the increase in the number of bodies flowing into that state through the Rajasthan and the Abohar Canals.

Mr Dev Raj, who has run a small tea shop at the Mohrana bridge for the last 20 years admits that "the bodies are a familiar sight, but they don't stop due to the fast flow of the water. But during the *bandhi* (water stoppage) two bodies surfaced at this bridge".

Mr Parmessar Dass, a *baildar* of the Irrigation Department who took out the bodies along with Mr Atma Singh, a Special Police Officer (SPO), after the bodies had floated in the water for four days, says "they were Sikh youth, aged about 30, with beards and long hair. The hands of one of them was tied at the back with a belt, but it is difficult to say if there were any gun wounds on their bodies since they were severely decomposed and bloated". Although the Amargarh police took away the bodies, they could not identify them and reportedly burnt them after photographing them, it is learnt.

When contacted, the Amargarh police station duty officer confirmed recovery of the bodies in January, but gave no any direct answers. "The postmortem report has not been received as yet", he said, but soon changed his statement to

See Fake encounters Page 4

THE POINEER MARCH 27, 1992

Evidence surfaces against police

Illegally detained men throw[n]

From Page 1

reveal that "the postmortem was conducted at the Civil Hospital, Malerkotla, and the findings revealed that it was death due to drowning". He claimed "there was nothing unusual about the bodies," whereas those who fished out the bodies from the canal said that hands of some were tied at the back with a belt.

The policeman, however, confirmed that these bodies had remained unidentified and unclaimed. According to him, a case under section 174 of the CrPC had been registered in his police station, but he would not disclose the FIR number or its contents.

About a kilometre ahead of the Mohrana bridge, some men at a tyre puncture shop adjacent to the Bhanbhaura bridge said that during the same period, the body of a middle-aged man had surfaced. The body remained there for several days before the villagers pulled it out and handed it over to the police. No one knows what happened to it.

Similarly, a farmer watering his fields near the Bhanbhauree bridge said that the body of a youth aged between 18 and 20 was recovered by the police.

Mr Bhupinder Singh, a resident of village Ranchana confirmed that he had personally seen four bodies. He confirmed the two at Mohrana bridge mentioned earlier, while the other two were that of a youth and a woman. The hands of the youth were tied with a red nylon rope at the back, while the neck of the woman, aged about 22, was slit. "The bodies were smelling very badly and could not be recognised". These bodies were taken out at the instance of the police by *baildar* Hari Singh on January 14. After the bodies were taken out, they were left on the bank of the canal for the eagles and vultures, he disclosed. A few tattered pieces of cloth are still lying at the site.

Further down the canal is the Babanpur bridge. Mr Jagta Singh, a guardsman in the nearby Forest Corporation Depot of village Kaheru divided from Babanpur by the canal, saw the body of a youth aged about 20 years. "The body remained here for three or four days. It first got stuck to the Kaheru railway bridge, but then came to float on the side of the bank of the canal. It was beyond recognition as quite a bit of it had been eaten up by vultures", he remarked.

Some of the people this correspondent spoke to said that many bodies do not surface because they have weights tied to them. Many confirmed that the bodies continue to flow in the canals even now, but they are not recovered and allowed to flow on. Sighting of one dead body each was also reported from the Salar and Hussainpur bridges on the same canal.

After these revelations, it was necessary to see the state of affairs in some other canal too. The Bhatinda branch of the Sirhind canal was checked out. At the Jagher bridge on the Malerkotla-Ludhiana stretch, a tea stall owner said that he had seen two bodies floating in the canal about two months ago, when the inflow of water was stopped. The bodies remained there for two days, but he does not know what happened to them later. This canal too passes through the Ropar, Ludhiana districts and enters the Sangrur district at this point.

Mr Hardip Singh, a lawyer, saw the body of a teenaged youth at the Kaind bridge on January 13, while on his way to Ludhiana. This bridge too is situated on the Malerkotla - Ludhiana road and falls under the Dehlon police station.

"The hands and feet of the boy were tied with a pajama and he was wearing only a vest and an underwear", he remarked.

Since, the Punjab police is seldom forthcoming with information, one has to rely on eyewitness accounts rather than concrete evidence. Due to the limitations under which this investigation was carried out, there are several "if's and but's" that may arise.

Several important questions could be raised about the validity of these findings. These can broadly be divided into two parts. (1) Who killed these people? and (2) How did they die? Answering the second part first, frensic experts at the Post Graduate Institute of Medical Science (PGI) here say that there is no way to find out by a casual glance whether the person died due to drowning or was killed and thrown into the water. The sure way of determining this is by a test know as the "Diatoms test" where extracted bone marrow is treated with Nitric Acid. If Diatoms are seen under the microscope then the death was due to drowning, otherwise not. It is a difficult test and findings are rarely accurate.

To ascertain whether it was murder or suicide, its important to know whether the person was killed and thrown into water or died due to drowning. Forensic experts rule out the suicide theory because the hands and feet of many victims were tied up. "This is unheard of", says an expert. It is very difficult for a person to tie up his feet and hands at the back and then go to the bank of the canal to jump in. Besides those

cases were weights hav
reported to be tied to th
rule out the possibility of s
The next question that
is: Who could have co
these murders? Is it part
mal crime? The probabilit
being a normal crime is al
out because it is too mu
coincidence that at all the
were more or less of the sa
group and definitely Sik
long hair and beards.
Only two options remai
these could be abducted
or rival gang members k
the terrorists or that they w
tims of state repression. I
words, they were killed by t
ce. Anyone having the s
knowledge about guerilla
re would not, repeat, not,
be to the theory of the te
killing these people. Blam
terrorists for the murders
suggest that they first co
the crime at some place a
carried the bodies all the w
canal. In all the massacr
have taken place in Punjab
the terrorists have vanish
after the crime.
The needle of suspicion th
re points ominously to the s
ty forces, whose involvem
extra judicial killings is
known. Dumping the bodies
canal is the safest way of pr
ing identification. If the b

...road tax structu-
...ct on April 1, for
...stered in the
...ctor of Trans-
...ven after the
...u tax in Delhi
...n lower than that in
...ghbouring States.

"Delhi's rates are at least one-and-half times less than UP and

Supply of water not in Delhi: [...]

UNI

New Delhi

HEALTH AND Family Welfare Minister M L Fotedar on Wednesday admitted in the Rajya Sabha that steps taken so far by the Delhi Administration to check water-borne diseases and to ensure adequate supply of potable drinking water had been ineffective and that people, particularly those living in villages, were still consuming unsafe water from wells and handpumps.

The number of mobile testing vans would be increased so that these could cover all parts of the Capital, he said during Question Hour. He said that Delhi needed 70 gallons of treated water per capita per day whereas the Delhi Administration was able to supply

1993

Jalandhar police pulled up for connivance with murder accused

KAMAL KISHORE

JALANDHAR

THE additional judge of the designated court here, Mr H. P. Handa, has passed strictures against the Jalandhar police, for their "active connivance with the murder accused and failure to produce the challan in the court."

In a letter written to Mr K. P. S. Gill, Director General of Punjab police, on July 14, the judge has asked him to hold an inquiry into why the police had not presented the challans with regard to Sanjiv Kumar, resident of Sant Nagar, Narinder Singh and Jaswant Singh, both residents of Sarihn village, who were charged with the murder of Jasbir Singh and against whom a case under the IPC, the Arms Act and TADA, was registered at the Nakodar police station, on December 12, 1992.

The judge, while turning down the application of the police while seeking the discharge of the accused on February 2, 1994, had directed the police to furnish the challan within one month but, in spite of forwarding a copy of that order to the district police chief, the police instead tendered a fresh application for the discharge of the accused on August 22, 1994. This was also rejected.

While rejecting the second application for discharge on October 8, 1994, the judge expressed concern over the sorry state of affairs in the police department for keeping aside the directions of the court.

Doubting the two affidavits of Mohan Singh and Malkiat Singh, both residents of Hussainabad in Jalandhar district, which were filed with the second application, the judge challenged the jurisdiction of the police to entertain such affidavits and observed that these could not be relied upon for want of witnesses who could identify the deponent.

Moreover, the police had "usurped the power of the court and were acting in a quasi judicial manner, which they are not supposed to do," the judge observed.

Criticising the stand taken by the police to get the accused discharged, the judge further observed that since one of the accused had filed an application in the Punjab and Haryana High Court for getting the FIR quashed, then what can be the intention of the police in filing another application for their discharge?

The judge in his previous order, the extract of which was mentioned in the letter written to the DGP, had warned that if the police failed to submit the challan in one month, the matter would be brought to the notice of the Supreme Court regarding the conduct of the police in dealing with such cases where there is sufficient evidence to get the accused convicted. ◆

SAT, 8 OCT 1994

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ-(ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਖਾਲੜਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਲਿਮ: ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਸਹਿਕਾਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਸ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਬੀਤੀ 26 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੀ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,: 'ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੰ: ਆਰ. ਕੇ. 1/ਸ: ਰ ਪੱਟੀ/3335-36 ਮਿਤੀ 18.7.94 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੰ: 6922-32/4. ਏ/ਡੀ. ਆਰ. ਏ. ਮਿਤੀ 12.8.94 ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਖਾਲੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।'

ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, 'ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।' ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 26 ਅਗਸਤ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

10-DEC-1995

ਖਾਲੜਾ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ)- 'ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ' ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ. ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹੀ । ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆ ਸ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।

ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੋਲੀ, ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ । ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ)- ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ. ਸ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸ੍ਰ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ੍ਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੇਮਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ।

28-Nov- 1995

ਜਾਏ।

10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਮੇਤਾ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਨਵੰਬਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ(ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ.ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮੀਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਸ.ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ(ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ) ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਵਿੰਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਲੋਚਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਹਮਖਾਹ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਅਰਜ਼ੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰੇਮੰਡਚਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਆਲਮ ਖਾਨ ਨਾਲ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਆਸਵੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕਰ

(ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 6 'ਤੇ)

Tarn Taran SSP shifted

EXPRESS NEWS SERVICE

CHANDIGARH, Nov 27: The Punjab Government has transferred Mr. Ajit Singh Sandhu, Senior Superintendent of Police, Tarn Taran.

He has been transferred on the orders of the Supreme Court in the case relating to the disappearance of Akali Dal human rights wing leader, Mr. Jaswant Singh Khalra. The apex court has directed the CBI to investigate the case.

Mr. Sandhu has been transferred to Sangrur in place of Mr. Anil Kumar Sharma, who has been posted as SSP, Tarn Taran.

26, 28 · Nov - 1995

SAD plea to Sikhs in Khalra case

Tribune News Service

AMRITSAR, Nov 27 – The human rights wing of the Shiromani Akali Dal (SAD) has decided to take the case of the alleged kidnapping of its general secretary, Mr Jaswant Singh Khalra, to the people's court and called upon all human rights organisations and Sikhs to raise their voice to demand his release on International Human Rights Day on December 10.

A spokesman for the party, Mr Satnam Singh, said here today that an emergency meeting of the human rights wing adopted a resolution saying that the Chief Minister, Mr Harcharan Singh Brar, had 'no moral right' to stay in office in view of the 'excesses' being committed by the Punjab police despite severe strictures by the Supreme Court against it.

The meeting thanked Amnesty International and US President Bill Clinton for taking up the case of Mr Khalra's alleged kidnapping by the Tarn Taran police with the Government of India and the Punjab Government.

Mr Raymond Chair, Minister of Asian Affairs, Canada, held detailed discussions with Mr Salman Khursheed, Union Minister of State for External Affairs, and the latter assured him that Mr Khalra was "safe" and would return home shortly.

Dharnas to seek Khalra's release

EXPRESS NEWS SERVICE

AMRITSAR, Oct 25: The Human Rights wing of the Shriomani Akali Dal will hold dharnas at all the district headquarters in the state from November 15 onwards to demand the release of their general secretary, Mr Jaswant Singh Khalra, from the alleged illegal custody of the Tarn Taran police chief, Mr Ajit Singh Sandhu.

This decision was taken at an emergency meeting of the representatives of the human rights wing, the Punjab human rights organisations, the Sikh Students Ffederation, the Punjab Majdoor Dal and the Association for Democratic Rights here today.

The meeting chaired by Mr Kirpal Singh Randhawa of the human rights wing decided that during the dharnas, memorandums will be given to the respective deputy commissioners demanding the release of Mr Khalra.

ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ 'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ' ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 65 ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।

17 Nov 1995

Indian Express

FRIDAY, NOVEMBER 17, 1995

From under the ashes

THE twin probe by the Central Bureau of Investigation ordered by the Supreme Court into the disappearance of an Akali Dal human rights activist, Mr Jaswant Singh Khalra from Amritsar, and the allegation of "liquidation and cremation of thousands of innocents" between 1984 and 1994 is likely to bring out many unpleasant aspects of police functioning in Punjab. Mr Khalra's "disappearance" in September last led to allegations that he was picked up by the men of the Tarn Taran police district. The SC order on Wednesday follows a candid submission earlier by the Punjab Advocate General that since the Punjab Police had been unable to trace him, the matter may be probed by the CBI. The second inquiry by the apex court is a natural corollary to Mr Khalra's "disappearance" since he had been actively pursuing the case of the "unceremonious cremation" by the police of a large number of terrorist suspects. While the allegation that at least 25,000 people had been cremated between 1984 and 1994 appears to be an exaggeration, Mr Khalra's disappearance was perhaps seen by the Supreme Court as an attempt by the police to subvert the due process of law. The Court observed that if the allegations of the Akali Dal of mass cremations were true, it would constitute "a most gory tale of human rights violations."

The fact that in order to instill confidence in the minds of the people, the Court should deem it necessary to have the charges inquired into by a CBI team, reflects on the dwindling credibility of the Punjab Police, which had earned the nation's appreciation earlier for putting up a sustained fight against terrorism. The Court, besides stating that the probe into Mr Khalra's disappearance should be completed in three months, also gave directions to the CBI to file interim reports every three months on the inquiry into the cremations. Moreover, the Court has directed the Punjab Government to transfer the controversial SSP, Mr Ajit Singh Sandhu from Tarn Taran till the completion of the twin probe. The judicial intercession should be an eye-opener for the Punjab Government, particularly its DGP, Mr K. P. S. Gill, who has all along shown a curious indifference to charges against erring policemen. Even generally, it should compel the police in the other States, too, to behave with a greater sense of responsibility and in conformity with the requirements of law. In effect, the Court's directive should act as a check on arbitrary police behaviour all over India.

17 Nov 1995

ਖਾਲੜਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ

ਆਵਾਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਨਵੰਬਰ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸਰੀਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਲਾਪਤਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਸਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।'' ਸ੍ਰੀ ਸਰੀਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਭ ਸਕੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ''ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਆਖਰ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।''

ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਛਾਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕਵਾਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ.

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੇਤਾ ਸਿੰਘ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ; ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮੀਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ 11 ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਂਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁਪ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੂੰਹੋ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 65 ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯਸ਼ਪਾਲ ਝਬਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀਪੁਰ , ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮੀਸ਼ਾਹ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਘਰਿਆਲਾ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਖਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰਗਿਜ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ।

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 5 ਮਰੇ 4 ਜ਼ਖਮੀ

ਕੋਲਾਪੁਰ, 26 ਅਕਤੂਬਰ

17 Nov 1995

ਅਜੀਤ

ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਵਾਹ

ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। *-ਪ੍ਰਿੰ: ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ*

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਅਗਵਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਥਹੁ-ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਅਹੁੜਦਾ। ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਸਗੀਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ

16 Nov 1995

Times of India

SC orders probe in Punjab cremations

By Our Legal Correspondent

NEW DELHI, November 15. Calling it "a most gory violation of human rights", the Supreme Court today ordered a probe by the Central Bureau of Investigation (CBI) into allegations that bodies of more than 25,000 persons lying unclaimed and unidentified had been "unceremoniously" cremated by the Punjab police between 1984 and '94.

It also ordered a CBI probe into alleged abduction and eventual disappearance of Shiromani Akali Dal leader and human rights activist Jaswanth Singh Khalra from Amritsar on September 6 this year. Mr Khalra's wife Paramjit Kaur suspects the involvement of Tarn Taran district superintendent of police Ajit Singh Sandhu in the mysterious disappearance and likely liquidation of her husband.

The judges observed that "horrendous as the charges were, they needed to be investigated by a CBI high-power team".

A division bench comprising Mr Justice Kuldip Singh and Mr Justice S Saghir Ahmad also directed the CBI to appoint a special team of investigators to look into the allegations by the human rights wing of the Shiromani Akali Dal that at least 25,000 "innocent persons had been liquidated and unceremoniously cremated in complete disregard to the human dignity by the state police between 1984 and '94".

The judges said the allegations against senior police officials of the state were of a serious nature it would be in the interests of justice to get the matter probed by an independent authority to "instil confidence in the minds of the public".

The court ordered the withdrawal of the case from the Punjab police and handed it over to the CBI. The investigating agency should file its report on the disappearance of Mr Khalra within three months, the court said.

As regards the allegations of mass cremation of unclaimed bodies, the court observed: "This was an equally serious matter to which it could not close its eyes." The judges told the CBI to file interim reports every three months on the progress of investigations.

Referring to a January 16 press release by the Shiroman Akali Dal human rights wing, the judges observed if the matter was true it would constitute "a most gory tale of human right violations".

Expressing concern over what had happened in Punjab, the court observed "nothing of this kind should ever be allowed to happen in the country".

Petitioner's counsel R S Sodhi submitted that Mr Khalra had been abducted by the Punjab police as he had prepared a report on the mass cremation of unidentified bodies allegedly carried out at the behest of Mr Sandhu.

The court directed the Punjab chief secretary as also state police chief K P S Gill to immediately transfer Mr Sandhu from Tarn Taran till the completion of the twin probe.

Nov 10-1995

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ-(ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਆਈ. ਬੀ. ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ: ਆਰ. ਐਸ. ਸੋਢੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ: ਸੋਢੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਤਾਂ 'ਬੁਰੀ' ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਕਿਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਅਹਿਮਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵੱਜ ਕੇ 20 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 8 ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਐਸ. ਪੀ. ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਸਰਹਾਲੀ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਝਬਾਲ, ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸ: ਆਰ. ਐਸ. ਸੋਢੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰੀਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਅਹਿਮਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ

11 Nov 1995

ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ -(ਅ.ਬ) - ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਸਹਿਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਗਵਾਹ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਮਕਸਦ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਸ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐੱਸ.ਪੀ.ਸਿਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ।

11 Nov - 1995

Khalra case: AG seeks CBI probe

EXPRESS NEWS SERVICE

NEW DELHI, Nov 10: The Khalra case took a curious turn today with the Punjab Advocate General, Mr M L Sareen, himself asking the Supreme Court to have the matter investigated by the CBI, as the state police had been unable to trace the missing Akali leader.

The Supreme Court bench, comprising Justice Kuldip Singh and Justice Sagir Ahmed, has for the moment reserved its judgment on the matter. The names of five policemen suspected to have been involved in the abduction were also forwarded to the apex court today by the complainants.

Mr Sareen took everyone by surprise when he himself pleaded before the Supreme Court bench that the investigation of the case should be handed over to the "CBI or any other independent agency."

Admitting that the Punjab police had been unable to trace the missing leader, Mr Sareen said, "We ourselves are very keen to know about what has happened to Mr Jaswant Singh Khalra."

A stunned Mr R S Sodhi, counsel for Mr Khalra's wife, said that either the learned Advocate General was being "very fair or he does not realise what he is saying."

Mr Sodhi argued that when the State government itself admits that it cannot maintain law and order, or, it has no power over its police force the situation reflects a Constitutional breakdown. Clearly the government is unfit to carry out its foremost Constitutional function of ensuring the safety of its citizens, he added.

Mr Sareen was on the defensive and said that he had asked for the CBI investigation because the complainants harboured so much distrust against the State government.

Justice Kuldip Singh quipped that it was not their fault and the state appeared to be in the grip of police terror.

Defence counsel submitted that there was "direct rivalry" between Mr Khalra and the controversial Tarn Taran police chief, Mr Ajit Singh Sandhu, as the former had been instrumental in collecting evidence

Contd. on p 9 col 1

Probe sought into Khalra case

Contd. from p 1 col 8

regarding the killing of youths in police custody. These youths had been later cremated as "unclaimed" at municipal expense.

Mr Khalra a human rights activist had also enabled several victims of police atrocities to move the High Court for redress and this had put Mr Sandhu in a tight spot. Mr Sandhu had then managed to wangle a second unprecedented posting to the Tarn Taran police district, even as court cases and a CBI enquiry were pending against him for his alleged excesses.

Mr Sodhi pleaded that a fair investigation could not be conducted into the case as long as Mr Sandhu continued to be posted as the SSP of Tarn Taran. The witnesses were too scared to come forward and testify, he added.

The Amritsar police who were also looking into the matter, as Mr Khalra had been picked up from the city, had earlier submitted an affidavit saying that the complainants were not co-operating with them.

Defence counsel said that the police had been informed about the abduction and names of five of the suspects had been given to them. "What else can we do to co-operate ? He questioned.

HINDUSTAN TIMES FRIDAY - NOV 10, 1995

NHRC probe into activists' abduction

HT Correspondent

CHANDIGARH, Nov. 9

The National Human Rights Commission has begun a formal inquiry into the alleged abduction of Human Right activist Jaswant Singh Khalra from Amritsar on Sept. 6. This is in addition to the Supreme Court probe already ordered into the case. Senior NHRC officials are in Amritsar making inquiries, reports here said.

The alleged abduction of the Human Right activist by the police has become an embarrassing issue for the Punjab Government.

The Chief Minister, Mr Harcharan Singh Brar who has declared that he would not only try to restore order but impose rule of law, finds no answer to this. This is indeed a test-case in which both the Supreme Court and the National Human Rights Committee Commission have shown keen interest.

In addition, over 70 world organisations including Amnesty International and Asia Watch have written to the Chief Minister protesting against the alleged abduction by a police party.

In fact, the international ramification of the case are now becoming too evident to the State Government. The United States Ambassador in India, Frank Wisner, during his visit to Amritsar made anxious inquiries from the police and civil officers. "We are deeply concerned by Mr Khalra's disappearance", he repeatedly told these officers. The Chief Minister's office is unable to send any satisfactory reply in this case to anyone.

Mr Khalra perhaps single handedly investigated the disappearance of over 3,000 persons during the past some years, particularly in Amritsar area.

After detailing the records of the cremation grounds in Amritsar, Tarn Taran and other places, he convincingly pointed out that the records bear no names and all these were just unindentified youngmen and women whom the police thought to be the militants.

After eliminating them in cold blood, they were cremated here. These revelations not only attracted wide attention in India but was reported in other countries too. Some police officers never liked Mr Khalra.

Admitting a writ petition, the Supreme Court directed the Punjab Government to trace and present Mr Khalra. The advocate general M. L. Sarin who personally appeared and promised the Supreme Court to supervise the search also added to the importance of the case.

But the Government is struck here. Punjab Police chief K. P. S. Gill denied that any police party abducted the Human Rights champion. Mr Khalra's wife, his friends and senior Akali leaders assert that he was picked up from his Kabir Park house by men in Khaki in a Maruti van which was followed by a police Gypsy.

The family and an eye witness, Rajiv Singh have provided complete details including the names of the five police officials to the highest court. But Mrs Paramjit Kaur, Mr Khalra's wife has refused to give these names to the police. Mr Sarin alleged that she was not cooperating in the investigation.

On the other hand, Mrs Paramjit Kaur Khalra asserted that she could not reveal all this to the Punjab Police who is otherwise charged with abduction. Those concerned with the case fear police reprisals.

Senior police officers here maintain that Mr Khalra was not picked up by the police from Amritsar or Tarn Taran but may be from some other district. This has been happening in Punjab too often.

A police party from one district raids and picks up people without informing anyone in that district. This leads to several problems and seniors here have to intervene to sort out.

Three brothers of Mrs Racchpal Kaur and widow of the late aide of Jarnail Singh Bhindranwale were picked up from Gurdaspur. While Supreme Court is taking to task the police in that district, they were essentially picked by a police party from another district. "Same could be true in this case", a senior officer said.

HINDUSTAN TIMES
10 Nov - 1995.

NHRC probe into activists' abduction

HT Correspondent

CHANDIGARH, Nov. 9
The National Human Rights Commission has begun a formal inquiry into the alleged abduction of Human Right activist Jaswant Singh Khalra from Amritsar on Sept. 6. This is in addition to the Supreme Court probe already ordered into the case. Senior NHRC officials are in Amritsar making inquiries, reports here said.

The alleged abduction of the Human Right activist by the police has become an embarrassing issue for the Punjab Government.

The Chief Minister, Mr Harcharan Singh Brar who has declared that he would not only try to restore order but impose rule of law, finds no answer to this. This is indeed a test-case in which both the Supreme Court and the National Human Rights Committee Commission have shown keen interest.

In addition, over 70 world organisations including Amnesty International and Asia Watch have written to the Chief Minister protesting against the alleged abduction by a police party.

In fact, the international ramification of the case are now becoming too evident to the State Government. The United States Ambassador in India, Frank Wisner, during his visit to Amritsar made anxious inquiries from the police and civil officers. "We are deeply concerned by Mr Khalra's disappearance", he repeatedly told these officers. The Chief Minister's office is unable to send any satisfactory reply in this case to anyone.

Mr Khalra perhaps single handedly investigated the disappearance of over 3,000 persons during the past some years, particularly in Amritsar area.

After detailing the records of the cremation grounds in Amritsar, Tarn Taran and other places, he convincingly pointed out that the records bear no names and all these were just unindentified youngmen and women whom the police thought to be the militants.

After eliminating them in cold blood, they were cremated here. These revelations not only attracted wide attention in India but was reported in other countries too. Some police officers never liked Mr Khalra.

Admitting a writ petition, the Supreme Court directed the Punjab Government to trace and present Mr Khalra. The advocate general M. L. Sarin who personally appeared and promised the Supreme Court to supervise the search also added to the importance of the case.

But the Government is struck here. Punjab Police chief K. P. S. Gill denied that any police party abducted the Human Rights champion. Mr Khalra's wife, his friends and senior Akali leaders assert that he was picked up from his Kabir Park house by men in Khaki in a Maruti van which was followed by a police Gypsy.

The family and an eye witness, Rajiv Singh have provided complete details including the names of the five police officials to the highest court. But Mrs Paramjit Kaur, Mr Khalra's wife has refused to give these names to the police. Mr Sarin alleged that she was not cooperating in the investigation.

On the other hand, Mrs Paramjit Kaur Khalra asserted that she could not reveal all this to the Punjab Police who is otherwise charged with abduction. Those concerned with the case fear police reprisals.

Senior police officers here maintain that Mr Khalra was not picked up by the police from Amritsar or Tarn Taran but may be from some other district. This has been happening in Punjab too often.

A police party from one district raids and picks up people without informing anyone in that district. This leads to several problems and seniors here have to intervene to sort out.

Three brothers of Mrs Racchp[illegible] Kaur and widow of the late aide[illegible] Jarnail Singh Bhindranwale [illegible] picked up from Gurdaspur. [illegible] Supreme Court is taking to [illegible] police in that district, th[illegible] essentially picked by a p[illegible] from another district. "[illegible] be true in this case", a[illegible] said.

5 Nov 1995

ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ-(ਵਿ.ਪ੍ਰ.) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਐਮ. ਐਲ. ਸਰੀਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ।' ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਬਰੀ

ਜਲੰਧਰ, 4 ਨਵੰਬਰ-(ਅ. ਬ.) ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਐਸ. ਕੌਲਧਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਕੋਟ ਸਦੀਕ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਚਰਨ ਦਾਸ ਵਾਸੀ ਕੋਟ ਸਦੀਕ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤਗਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਚਰਨ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਰਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਰੰਗ ਮੇਲਾ ਅੱਜ

ਭੁਲੱਥ, 4 ਨਵੰਬਰ-(ਅ.ਬ.) 28ਵਾਂ ਸਲਾਨਾ, ਖੁਸ਼ਰੰਗ ਮੇਲਾ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਤਵਾਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ 1.00 ਤੋਂ 4.00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

Khalra's whereabouts not known, SC told

EXPRESS NEWS SERVICE

4 Nov 1995
INDIAN EXPRESS.

CHANDIGARH, Nov 3: The Punjab Government has filed an affidavit before the Supreme Court stating that the whereabouts of Mr Jaswant Singh Khalra, general secretary of the human rights wing of the Shiromani Akali Dal who is missing since September, were not yet known.

The affidavit was filed by the government yesterday following an earlier directive by the Supreme Court, it was learnt here today.

The counsel on behalf of Mr Khalra had named five police personnel, who were on leave, for their alleged role in "abducting" Mr Khalra. The state government, in its affidavit, has said that it has inquired into the matter and have found that all of them were present at their place of posting at different places on the day of his "abduction".

The affidavit has also stated that the wife of Mr Khalra was not cooperating with the investigating agencies.

'Punjab cops hand in custodial deaths'

Staff Reporter

New Delhi

THE HUMAN Rights wing of the Shiromani Akali Dal (SAD) on Monday charged the Punjab Police with "extra-judicial killings" and said this can be proved by the fact that there was a connection between the disappearance of a large number of people and the cremation of thousands of supposedly "unidentified and unclaimed" bodies.

Addressing a Press conference here, SAD's human rights wing secretary Jaspal Singh Dhillon said a study of the official records such as birth and death registers, municipal corporation cremation ground records and firewood purchase registers maintained at three cremation grounds in Amritsar revealed that the police had cremated about 3,000 bodies between 1992-94.

"That the conduct of the Punjab police is malafide and wilful is evident from the fact that they have violated the elementary procedures to be observed under law to notify persons and authorities and to make detailed descriptions before dealing with dead bodies that are stated to be unidentified", said their lawyer Ashok Aggarwal.

According to him, a dead body can be said to be 'unidentified and unclaimed' only after following detailed procedures and "not by just a bland statement in the obscurity of a register in a cremation ground", he said.

"Many of the bodies listed as 'unidentified and unclaimed' have the name of the person or sometimes the name of his father or even the name of his village written against it. Then how could the body have been unidentified or unclaimed," asks Mr Agarwal.

"When the cremations were done the police used to cordone off the cremation grounds not giving anyone a chance to see the bodies. The workers at the cremation ground had said that more than one body was burnt on a pyre," said Mr Dhillon.

Mr Amrik Singh Muktsar, vice chairman of the wing said that the general secretary of the wing Mr Jaswant Singh Khalra who was closely associated with the investigations into these mass cremations had been picked up by the Punjab Police as a retaliatory tactic against human rights' activists. "This has caused panic and loss of confidence in those who had earlier come forward to file affidavits on the disappearance of their family members," he claimed.

A case was filed in the Supreme Court regarding these disappearances and mass cremations by the Committee for Information and Initiative on Punjab, constituted by the Dal's human rights' wing which resulted in the serving of notices to the State of Punjab, Mr K P S Gill and the SSPs of the three police districts of Amritsar and the CBI was ordered to carry out an enquiry, said Mr Dhillon.

"Those who gave evidence to CBI started disappearing and so we appealed for protection of the witnesses and the court had passed an order for their protection," he said.

Four relatives of the disappeared who have joined the Committee were present at the Press conference and the members of the human rights wing expressed concern for their safety.

Baldev Singh is one of the four relatives, whose son, Pargat Singh, the police is said to have taken into illegal detention on September 19, 1990, and cremated as unidentified and unclaimed.

Baldev Singh was a soldier in 9 Punjab Regiment and was forced to retire after being injured in the 1965 war against Pakistan. His daughter had been India's star weight-lifter.

3 FEB 1995

17 OCT 1995

17-OCT-1995

Punjab cops 'silence rights activists'

Tribune News Service

NEW DELHI, Oct 16 – The Delhi-based Committee for Information and Initiative on Punjab today alleged that the Punjab police had unleashed atrocities by sliencing human rights workers and the independent witnesses. It was also behind the disappearance of a large number of people and the cremation of 'supposedly' unidentified bodies, the committee alleged.

Talking to newsmen here, members of the secretariat of the body, including Mr Tapan Bose and Mr Jaspal Singh Dhillon, chairman of the human rights wing of the then Shiromani Akali Dal in 1994, alleged that about 3,000 bodies had been cremated in Amritsar district alone during 1992-94.

The official records – Births and Deaths registers, municipal corporation cremation records and the firewood purchase registers – maintained that a large number of people had been cremated as unidentified and unclaimed bodies, they added.

The members produced some relatives of the persons cremated. The relatives alleged that they were not given the bodies in spite of their petition to the police authorities for the same.

The members also levelled charges of retaliatory tactics adopted by the Punjab police against human rights activists who had made investigations and sought to expose the misdeeds in the matter.

Citing an example, they said Mr Jaswant Singh Khalra, a prominent Akali leader and human rights activist was picked up on September 6, 1995, by uniformed commandos of the Punjab police. They said Mr Khalra was abducted and held illegally and tortured by the Tarn Taran police district till September 22.

Rights body flays Punjab Police

NEW DELHI, Oct. 16 (HTC)
In a scathing attack on the Punjab police, the Committee for Information and Initiative on Punjab, a human rights organisation, has alleged that the police in the State was responsible for the "abduction and disappearance" of a large number of people.

According to a statement of the committee, the Punjab police was also trying to "silence human rights workers and independent witnesses" who could give vital evidence into the mysterious disappearances.

As an example, it said that Mr Jaswant Singh Khalra, general secretary of Shiromani Akali Dal's human rights wing who had been closely associated with investigations in various "crimes" of the police, was "picked up" on Sept. 6 by "uniformed commandos of the Punjab police".

The committee also alleged that in Amritsar district alone, thousands of "unclaimed/unidentified" bodies had been cremated by the police.

The committee said the "abduction" of Mr Khalra was led by Tarn Taran SP Surinder Pal Singh along with SHO of Manochahal police station Jasbir Singh and SHO of Chahal police station Satnam Singh who "enjoy notoriety in the area".

TRIBUNE
Oct 17 1995

Punjab cops 'silence rights activists'

Tribune News Service

NEW DELHI, Oct 16 – The Delhi-based Committee for Information and Initiative on Punjab today alleged that the Punjab police had unleashed atrocities by sliencing human rights workers and the independent witnesses. It was also behind the disappearance of a large number of people and the cremation of 'supposedly' unidentified bodies, the committee alleged.

Talking to newsmen here, members of the secretariat of the body, including Mr Tapan Bose and Mr Jaspal Singh Dhillon, chairman of the human rights wing of the then Shiromani Akali Dal in 1994, alleged that about 3,000 bodies had been cremated in Amritsar district alone during 1992-94.

The official records – Births and Deaths registers, municipal corporation cremation records and the firewood purchase registers – maintained that a large number of people had been cremated as unidentified and unclaimed bodies, they added.

The members produced some relatives of the persons cremated. The relatives alleged that they were not given the bodies in spite of their petition to the police authorities for the same.

The members also levelled charges of retaliatory tactics adopted by the Punjab police against human rights activists who had made investigations and sought to expose the misdeeds in the matter.

Citing an example, they said Mr Jaswant Singh Khalra, a prominent Akali leader and human rights activist was picked up on September 6, 1995, by uniformed commandos of the Punjab police. They said Mr Khalra was abducted and held illegally and tortured by the Tarn Taran police district till September 22.

ਐਮਨੈਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਲੰਡਨ, 17 ਅਕਤੂਬਰ-(ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ 'ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਲਾਪਤਾ' ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 1993 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

HINDU

Oct -16- 1995

Voluntary organisation indicts Punjab police

From Our Staff Reporter

NEW DELHI, Oct. 16.

Hundreds of people from the Amritsar district were cremated by the Punjab police between 1992 and 1994 as unidentified bodies, the Committee for Information and Initiative on Punjab has charged.

The police, the Committee alleged, had been systematically picking up people, destroying them and disposing of their bodies without even intimating their relatives. This, it said, was borne out by official records — birth and death registers, municipal corporation cremation records and the firewood purchase register maintained at cremation grounds.

At a press conference here today, Mr. Ram Narain Kumar — a social worker and committee member — said the local police had adopted retaliatory tactics against the human rights activists investigating the cases and seeking to expose their misdeeds. Citing one instance, he said the Shiromani Akali Dal's Human Rights' Wing's General Secretary, Mr. Jaswant Singh Khalra, who had been closely associated with the investigations, was taken away by Punjab police commandos on September 6 and his whereabouts till date are not known.

The authorities have neither formally acknowledged Khalra's abduction, nor have his relatives received authentic information on his whereabouts, Mr. Kumar said.

Mr. Jaspal Singh, member of the Human Rights Wing of the Shiromani Akali Dal, said the committee's findings were based on the information gathered from only three cremation grounds in Amritsar district. The current findings, he said, was only the tip of the iceberg. The Government should order an enquiry into the sordid episode, he added.

Sixtyfive-year-old Mr. Baldev Singh, who was present at the press conference, alleged that his son, Pragat Singh, was taken into custody by the police on September 19, 1990, and subsequently killed in a "fake" encounter. Mr. Singh said he managed to reach the cremation ground where the police were cremating his son's body as that of an unidentified person.

Similarly, Ms. Lakhvinder Kaur's son, Hardev Singh, was picked up by Punjab police commandos on September 22, 1992, when he was on his way to the house of Surinder Pal Singh Cheema, a Parliamentary candidate for the aborted elections of May 1991. Ms. Kaur fears that her son has been killed and cremated as an unidentified person.

Two others, whose family members had met with a similar fate, had come from Amritsar for the press conference here at "great personal risk".

SUNDAY STATESMAN
OCT-15,1995

S.C. notice to Gill on killings

NEW DELHI, Oct. 13. — The Supreme Court today issued notices on a petition, seeking an inquiry into "unlawful killings" and disposal of bodies as "unclaimed" in Punjab from June, 1984 to June 1994, reports UNI.

The notices, returable within four weeks, were issued by a division bench comprising Mr Justice G.N. Ray and Mr Justice G.T. Nanavati to Director General of Punjab Police, K.P.S. Gill and senior superintendents of police of Taran Taran, Amrisar and Majitha districts.

The petitioner, Committee for Information and Initiative on Punjab had alleged that more than 3,000 bodies had been cremated by the Punjab Police after declaring them as unidentified during this period.

The petitioner submitted that the police in the State did not follow the procedure prescribed under the law for the disposal of unclaimed bodies.

The organisation also prayed for an inquiry into the matter and compensation to the next of kin of the deceased, who were allegedly killed in fake encounters.

14 OCT. 1995

ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਯੂ. ਐਨ. ਆਈ.) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਜੂਨ 1994 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ "ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ" ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਲਾਵਾਰਸ' ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐਨ. ਰੇਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਟੀ: ਨਾਨਾਵਟੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਕਤ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

14 OCT 1995
HINDUSTAN TIMES

SC notice to Punjab cops

NEW DELHI: The Supreme Court today issued notices on a petition seeking an inquiry into "unlawful killings" and disposal of over 3,000 dead bodies as "unclaimed" in Punjab by State police from June 1984 to June 1994, reports HTC.

The notices, returnable within four weeks, were issued by a division bench comprising Mr Justice G. N. Ray and Mr Justice G. T. Nanavati to Director-General of Punjab Police, Mr K. P. S. Gill and Senior Superintendents of Police of Tarn Taran, Amritsar and Majitha districts.

The petitioner, the Committee for Information and Initiative on Punjab, had alleged that more than 3,000 bodies had been cremated by the Punjab police after declaring them as unidentified during the past one decade.

14, 16, 17 Sept 1995.

ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਸਤੰਬਰ-(ਸ. ਰ.) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ: ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਰੇਬ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Khalra's wife seeks help of PM

Tribune News Service

AMRITSAR, Sept 16 – Mrs Paramjit Kaur, wife of Mr Jaswant Singh Khalra, general secretary, human rights wing of the Shiromani Akali Dal, has sought the intervention of the Prime Minister, Mr P.V. Narasimha Rao for the "safe release" of her husband, who according to her was abducted by the Tarn Taran police on September 6.

In a communication, which was released to the press here today, she stated that she had approached local police officers to locate the whereabouts of her husband, but to no avail. He has been abducted by the Tarn Taran police because he had been "exposing" police excesses and telling about the cremation of 25,000 Sikh youth described as "unclaimed" bodies during the disturbed conditions in Punjab, she added.

ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ)- ਸ਼੍ਰੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਛਾਪਾ, ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਰਤੀ ਦਲਿਤ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਰਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੋਹਣ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋ. ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

13 SEPT 1995

Amnesty demands Khalra's release

NEW DELHI, Sept 12 (UNI) – Amnesty International has sought the intervention of Home Minister S.B. Chavan and Punjab Chief Minister Harcharan Singh Brar for the release of Akali Dal Human Rights Wing General Secretary Jaswant Singh Khalra.

Mr Khalra was taken into police custody in Amritsar on September 6.

In an appeal to them, Amnesty International expressed fears about Mr Khalra's safety, saying: "He has not been produced before a magistrate so far and his relatives have not been officially informed about his whereabouts."

According to the human rights body, Mr Khalra had been "picked up" by the police as he had filed a petition against the state police in the Punjab and Haryana High Court in January, alleging that some individuals described as "disappeared" were actually cremated in Amritsar district as "unclaimed bodies".

Meanwhile the National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognizance of the "disappearance" of Mrs Gurmej Kaur (70), mother of slain Bhindranwale Tigers Force of Khalistan (BTFK) chief Gurbachan Singh Manochahal, two years ago and asked the Punjab Government to submit a detailed report in this regard within a month.

The NHRC sent a communication to the Punjab Chief Secretary last week in this regard along with a letter from Amnesty International, appearing in the Letters to Editor column of an Indian newspaper, the commission sources said here today.

Amnesty International, in its letter, said Mrs Gurmej Kaur and members of her family, including her husband, were taken in custody in June, 1992, when Manochahal and his accomplices were still operating in the Amritsar area.

Manochahal was killed in an encounter with the police on February 28, 1993, at Rataul village in Amritsar district.

Amnesty International said Mrs Gurmej Kaur's family was held in detention at Verowal police station till she was separated from her family on March 17, 1993, and since then her "whereabouts have been unknown".

In another case, the commission has decided to intervene in the pending proceedings in the Punjab and Haryana High Court relating to the disappearance of Mr Harjit Singh, an employee of the Punjab State Electricity Board. He was alleged to have been arrested by the police on April 29, 1992.

In this case too, Amnesty International had expressed concern over slow legal proceedings initiated in October, 1992, to clarify his whereabouts after his alleged arrest.

The commission sources said it had appointed a senior advocate of Chandigarh to move the court with a request to fix a date by which the report should be submitted by the Sessions Judge, Chandigarh.

INDIAN EXPRESS

12 SEPT 1995

SC notice to Punjab police on Khalra issue

EXPRESS NEWS SERVICE

NEW DELHI, Sept 11: The Supreme Court has issued notice to the Punjab police and the Home Secretary in connection with the alleged kidnapping of the General Secretary of the Akali Dal Human Rights Wing, Mr Jaswant Singh Khalra, by the police.

Treating the telegram sent by the SGPC president, Mr Gurcharan Singh Tohra, as a habeas corpus petition, the Division Bench headed by Justice Kuldip Singh said: "Issue notice to Home Secretary, Punjab, Director General of Police and SSP Amritsar. Returnable within one week."

The judges further stated: '-'Mr R.S. Sodhi, who is present in the court, states he has also filed a petition in this court in this respect". Mr Sodhi is the counsel for Mr Khalra's wife, Mrs Paramjit Kaur, who has moved the habeas corpus in the Apex Court.

It has been alleged that the Taran Tarn police had picked up Mr Khalra from Amritsar using the assassination of Beant Singh as an excuse.

However, the Taran Taran police wanted to settle scores with Mr Khalra as he had enabled several victims of police excesses to file cases in the Punjab and Haryana High Court which had put the SSP, Mr Sandhu, in a tight spot.

Mr Khalra had also been instrumental in gathering documentary evidence of deaths in police custody which had proved that most of the missing youths in Punjab had actually been killed.

It is alleged that since this had disproved Mr K.P.S. Gill's theory that these youths had illegally migrated abroad, the police wanted to get back at Mr Khalra.

Yesterday, an Akali Dal delegation led by the SGPC president had met the Punjab Governor, Lt Gen B.K.N. Chibber, and requested him to intervene in the matter and have Mr Khalra released from police custody.

Mrs Khalra has alleged in her petition that her husband was picked up by the Taran Tarn police on September 6 in a van (DNB 5969) accompanied by policemen.

(Sept- Oct)- 1995

Babbar Khalsa warns Govt, demands release of prisoners

Staff Reporter

New Delhi

THE BABBAR Khalsa International (BKI) on Wednesday warned the Union Government that it should immediately release two persons arrested by the Punjab Police failing which they would have to face the consequences.

In a fax message to newspaper offices here from Germany, BKI's Germany branch General Secretary Bhupender Singh Pehelwan said the two persons — Onkar Singh and Jaswant Singh Kalra — were picked up by the Punjab Police. He added that Kalra had "disappeared after being picked up by the police".

The statement also referred to the recent World Sikh Conference in Amritsar on September 29 where the BKI's views were publicly read out. Its views pertained to the suppression of the Sikh community by the "secular Indian state" — particularly those of a section of the community that desired independence for the Sikhs from India.

The statement said these views were aired as any person was free to express his opinion. Earlier, conference convenor Jathedar Bhai Manjeet Singh had requested that those who wanted their views to be expressed at the gathering were to send their representatives or send their views to be read out.

The BKI categorically said that no duress was applied for the purpose and noone was threatened to have their (BKI's) views aired.

Since many persons wanted to express their opinions, there was not sufficient time for their statements to be read out at the conference, the message said.

So, copies of the statement were distributed among the participants. It was later, when the organisers realised that there was sufficient time, that one of the participants, Prof Onkar Singh, read the statement on request.

The BKI claimed that airing of their views had "irked the Indian Government. Therefore, Prof Onkar Singh has been picked up by the Punjab Police and his family was being harassed." It added that "Mr Jaswant Singh Kalra has disappeared after he was picked up by the police".

It claimed that "whatever we are doing is in accordance with the Babbar Khalsa'a constitution and the German Constitution. We have the support of persons like Mr F W d'Klerk, who had fought against apartheid, and Mr Yitzhak Rabin. India needs people like them to end the discrimination against the Sikhs." The organisation denied involvement in the assassination of former Punjab Chief Minister Beant Singh. "The Indian Government is thrusting the blame for the killing on BKI," it added.

11 SEPT-1995

ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਸੋਮਵਾਰ 11 ਸਤੰਬਰ, 1995

ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫਾਸਿਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ: ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਸ: ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸ: ਗਿੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ । ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕਿ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ । ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ । ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਭਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਖਾੜਕੂ ਦੱਸਿਆ । ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ । ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਸ: ਖਾਲੜਾ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਆਗੂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸ: ਬਰਾੜ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਸੁਧਰੇਗਾ । ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ । ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਕੜਾ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ । ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫਾਸਿਸਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ । ਸ: ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਰਿਬੀਰੋ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸ: ਗਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਫਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬੀ.ਕੇ.ਐਨ. ਛਿੱਬਰ (ਰਿਟਾ.) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਤਿਆਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਯੁਵਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਯੁਵਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਮੁੜ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਯੁਵਕ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਢਾਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁੜ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਫਦ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ (ਰਿਟਾ.), ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਘੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਜਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ।

ਅਜੀਤ

Mon 11 Sept 1995

ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ-(ਵਿ. ਪ੍ਰ.) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਕ ਵਫਦ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਫਦ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਛਿੱਬਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ।

ਵਫਦ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜਥੇ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ 9.10 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਰਨਲ ਬਾਲਾ ਨੇ 'ਅਜੀਤ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲੁੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-(ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਮਹਿਤਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਭਾਈ ਸਾਜਨ ਸਿੰਘ, ਸ: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ ਅਤੇ ਸ: ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉਕਤ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਆਗੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੋਂਦ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।

10-Sept-1995 ਅਜੀਤ

ਟੌਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ

ਮਾਨਸਾ, ੯ ਸਤੰਬਰ-(ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਤਵਾ) ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਬ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ-ਭਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ: ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਪਰ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪੱਖੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਾਈ ਮਤ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਸੰਚਾਲਕਾਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੂਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣਾਂ, ਫੌਜੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਸਿੱਖ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਣਨੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨਾ ਕਦੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਯੂਥ ਨੇਤਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

10 - SEPT 1995 INDIAN EXPRESS

Mann, Badal flay largescale arrests

KULVINDER KULAR Sept 10

CHHAPAR (Ludhiana), Sept 9: The Akali leaders of all hues, today, criticised the Centre and the Punjab Government for resorting to largescale arrests in the state, following the assassination of the Chief Minister, Mr Beant Singh.

Mr Parkash Singh Badal and Mr Simranjit Singh Mann, speaking at two different conferences organised by the Akali Dal (Badal) and Akali Dal (Mann) respectively warned that this repression would prove counterproductive.

They appealed to the government to change its perception of the Punjab problem in the light of the August 31 blast, treating it purely as a law and order issue and find a political solution in order to establish lasting peace in the border state.

Only two political conferences were held at this famous fair of the Malwa at Chhapar, for the first time, in the absence of the Congress and the Communists.

Both conferences by rival Akali factions drew equally large crowds though neither took the services of Dhadis to attract people.

Both the factions made scathing attacks on each other, while claiming themselves to be champions of Panthic unity. Almost all speakers at the Akali Dal (Badal) conference, seeing the good turn-out at the rival meet, made a fervent appeal to Mr Mann to give up this obstinacy and join hands with them in the interest of the people and the state.

The president of the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, Mr Gurcharan Singh Tohra, Mr Jagdev Singh Talwandi and Mr Kuldip Singh Wadala were forthright in claiming that they had not abandoned the Amritsar Declaration. Mr Wadala and Mr Talwandi, said this declaration could be adopted as a long term party goal, if Mr Mann joined them.

Mr Mann regretted yesterday's statements of the Union Home Minister, Mr S. B. Chavan and the Punjab Chief Minister, Mr Harcharan Singh Brar, asserting that terrorism would be dealt with an iron hand.

He said there was no terrorism in the state, but it was a problem of the Sikhs. This problem had been there right from the days of the British and that Mahatama Gandhi and Pandit Jawahar Lal Nehru made promises to Sikh leaders but later backed out.

Flaying the arrest of human rights' activist, Mr Jaswant Singh Khalra, and others during the last one week, he said the government was again trying to revive the atmosphere of terrorism in the state. Urging the government to stop this `witch-hunt', he asserted that his party would strongly oppose it.

Talking to media persons, he refused to condemn the killing of Mr Beant Singh, saying the matter was still under investigation.

He criticised Mr Badal and Mr Tohra for their opportunism. Mr Mann said, Mr Badal by attending Mr Beant Singh's cremation, had shown that he was steering the party towards the Congress. He dubbed such leaders as well as the Congress and the BJP as 'anti-Sikh.' ◆ENS

Sep 10 Indian Express

TRIBUNE - SEPT- 10 -1995

SEPT 10 TRIBUNE

PM urged to hold talks with Akalis

From Sarbjit Singh
Tribune News Service

CHAPAR (Ludhiana), Sept 9 — While Mr Simranjit Singh Mann, addressing a political conference here today, urged the Prime Minister, Mr P.V. Narasimha Rao, to initiate a political dialogue with his party in the light of the Amritsar declaration to solve the Punjab problem, the leadership of the Akali Dal headed by Mr Parkash Singh Badal said that the party's struggle against the central and state governments would continue until a federal structure was set up in the country in letter and in spirit.

Mr Mann said the happenings in the past two weeks had once again proved the point that Punjab was a political problem. He was indirectly referring to the Chandigarh bomb blast.

He said that the Centre should find a political solution to the Punjab issue in the light of the Amritsar declaration and should not resort to counter-terrorism by starting the process of arresting Sikh youths and torturing them in police stations. He said that by solving the Punjab issue at the political level both Punjab and India could live in peace.

Launching an attack on the leadership of the Akali Dal (Badal), especially Mr Gurcharan Singh Tohra and Mr Parkash Singh Badal, Mr Mann said that they were cowards and "fake" representatives of the Sikhs. He said that by turning their backs towards the Amritsar declaration, Mr Tohra and Mr Badal had stabbed the Sikh Panth in the back.

Mr Mann also took to task the acting Jathedar of Akal Takht and said that Prof Manjit Singh had failed to live up to the expectations of the Panth. He said that Professor Manjit Singh did not stand by the Amritsar declaration as he was fearing that the Centre would cancel his passport. He criticised the Akal Takht Jathedar for rousing a colony at Anandpur Sahib to sell plots.

Mr Mann said Mr Badal and other Akali leaders who went to attend the cremation of Beant Singh had proved that they had a "soft" corner for the Congress. They were earlier hobnobbing with the BJP, Mr Mann said. He said both Mr Badal and Mr Barnala should apologise for attending the cremation ceremony of Beant Singh otherwise they should be gheraoed in rural areas. He also demanded the release of Mr Jaswant Singh Khalra, a human rights activist, within 15 days lest he should start a morcha to get him released.

Mr Mann said if his party formed the government, it would get the money of all Hindus returned within a month which was allegedly extorted by Congress MLAs and ministers during the past three years. His government would provide a clean administration and the police would be put under the civil administration.

Other significant issue raised by Mr Mann was regarding liquor vends. He said Punjabi youths were being destroyed by liquor and his party would start a campaign for getting liquor vends closed.

Both the Akali Dal headed by Mr Mann and the Akali Dal headed by Mr Badal had organised their conferences separately but adjacently at the fair. No other party had organised the conference. A mere 20 km from here, the Congress party had today organised a bhog ceremony of the late Punjab Chief Minister, Mr Beant Singh, at Payal.

While Mr Mann made a sharp attack on the rival Akali Dal headed by Mr Badal, the entire leadership of the Akali Dal (Badal), including Mr Kuldeep Singh Wadala, Mr Jagdev Singh Talwandi, Mr Surjit Singh Barnala and Mr Tohra, at the conference made passionate appeals to Mr Mann to join hands with them to set up an Akali government in the state by winning the next elections.

Almost the entire top leadership of the Akali Dal headed by Mr Badal tried to explain that with the death of Beant Singh, their struggle in the state had not ended. They said they were fighting against the Congress for the past three or four decades. And as Beant Singh also represented the programmes and policies of the Congress party in the state, they had been fighting to dethrone him from the seat of power but had not fighting against him as an individual.

Making things clear for the new Chief Minister, Mr Harcharan Singh Brar, the Akali leaders said all those who had been representing the Congress as Chief Minister in the state were a handle of the axe of the Congress party which it was using against Punjab and Punjabis.

Addressing the conference Mr Tohra said that he was ready to leave Punjab and settle in some other state if Mr Mann and Mr Badal can run the party together. He was saying this while replying to Mr Mann's allegations that Mr Tohra had created rift between him (Mr Mann) and Mr Badal. Mr Tohra said that all what was being said against him by Mr Mann was untrue.

He said that the Congress party was responsible for crushing the minorities in all states. He said that trouble in Jammu and Kashmir, Punjab and other states like Assam had been created by the Congress party by following anti-minorities policies. He said that the Union Home Minister, Mr S.B. Chavan, was "issuing" threats to police chiefs of punjab and union territory Chandigarh because the Centre wanted to launch a campaign against Sikh youths under the pretext of the Chandigarh bomb blast incident.

Mr Tohra said that hundreds of Sikh youths had been arrested. He demanded the immediate release of Mr Jaswant Singh Khalra. He warned the government that if it did not stop torturing and arresting the Sikh youths, it would generate great resentment in the state.

Mr Badal said that within a short period the campaign "Punjab bachao - Congress bhajao" would become a big storm which would mark the end of Congress rule in the state. He called upon the party rank and file to not to make hot speeches and slogans as these things were of no use. Mr Badal said that struggle should be run with a true spirit and wisdom for achieving the ultimate victory. There was no use of giving "hot" political programmes as such programmes failed to achieve anything.

Attacking the Prime Minister in his speech Mr Badal said that Mr Rao was a "coward" as was clear from his recent visit to Chandigarh. He said that he had never visited Punjab to solve the Punjab issue. Nobody should expect anything from him, Mr Badal said. He added that the Akali Dal had won all its earlier struggles against the Centre and would also won the present one. He said that the Akali Dal wanted that entire system should be changed and powers to dismiss the state governments with the Union Government should be deleted from the Constitution.

He said that Akali rank and file should work for forming the government in the state and with this all problems of the Punjab, Punjabis and Sikhs would be solved. Mr Surjit Singh Barnala, former Chief Minister said that Mr Brar, Chief Minister, was also a puppet of the Centre and he would not be allowed to compromise on the rights of the state.

Mr Kuldeep Singh Wadala, Mr Jagdev Singh Talwandi, Mr Prem Singh Chandumajra, Capt Kanwaljit Singh, Mr Amrik Singh Aliwal and Mr Surjan Singh Thekedar also spoke.

9 Sept 1995

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) -ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਕੋ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਆਰ. ਭੱਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿੰਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੈਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਐਨ ਬੀ 5969 ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਜਿਪਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ [illegible] ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੰਗ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੋਂ ਕੇਵਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

9 Sept - 1995.

ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਸਤੰਬਰ-(ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 'ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ' ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨਜਾਣਪੁਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਆਈ. ਜੀ. (ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ) ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਚਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਧਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵਿੰਗ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਸਤੰਬਰ-(ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 365 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਨੇ 'ਅਜੀਤ' ਫੋਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ।

ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਫਗਵਾੜਾ, 8 ਸਤੰਬਰ-(ਪ. ਪ.) ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਚਾਚੋਕੀ ਦੇ ਇਕ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਫਗਵਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦਿਤੀ।

INDIAN EXPRESS

9 SEPT, 1995

Missing worker abducted by police: SAD

AMRITSAR, Sept 8: The human rights wing of the Shiromani Akali Dal has alleged that its general secretary, Mr Jaswant Singh Khalra, has been abducted by the Tarn Taran police at the instance of the Senior Superintendent of Police, Mr Ajit Singh Sandhu.

Addressing a press conference here today, the chairman of the wing, Mr Jaspal Singh Dhillon, said that Mr Khalra's whereabouts were not known since he was picked up on Wednesday evening.

He said there was a deep-rooted conspiracy to eliminate him, adding that all efforts to persuade the senior officers of the Border Range to try and locate Mr Khalra have proved futile.

Mr Dhillon alleged that the SSP and other officers had repeatedly threatened Mr Khalra with dire consequences and an attack on his life. He said Mr Khalra had consistently exposed the Tarn Taran police and that was why he had been abducted to "settle scores".

The Amritsar police chief, Mr Sumant Kumar Goyal, when contacted, said a case had been ragistered on a complaint filed by the wife of Mr Khalra under Section 365 of the IPC at the Islamabad police station and the matter was under investigation. ♦ENS

ਅਜੀਤ

8 Sept - 1995.

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ

ਜਲੰਧਰ, 7 ਸਤੰਬਰ-(ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰੜਕ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਪਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸ: ਖਾਲੜਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸ: ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਸਮੇਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜੇ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ: ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਜਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ: ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਸ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ, ਸ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

THE TRIBUNE
9 SEPT, 1995

SGPC demands Khalra's release

Tribune News Service

AMRITSAR, Sept 8 – The SGPC has strongly condemned the "kidnapping" of Mr Jaswant Singh Khalra, general secretary, human right wing of the Shiromani Akali Dal from his residence in Kabir Park here on Wednesday by the police and demanded his immediate release.

In a joint statement, the SGPC chief, Mr Gurcharan Singh Tohra, and the secretary, Mr Manjit Singh Calcutta, said here yesterday that Mr Khalra had been lifted by the police because he had exposed the elimination of Sikh youths and apprised the world of 25,000 unclaimed bodies.

They sought the intervention of the Punjab Chief Minister, the Chief Justice of the Supreme Court, the Punjab and Haryana High Court and the DGP, Punjab, to save the life of Mr Khalra and appealed for his immediate and unconditional release from "illegal" police custody.

The human rights wing today alleged that Mr Khalra had been "kidnapped" by the Tarn Taran police because he had been exposing police excesses.

Addressing a joint press conference here, Mr Amrik Singh Muktsar and few others alleged that Mr Khalra was "kidnapped" from his residence in Kabir Park area in a sky blue Maruti van (DHB 5969) and a white police Gypsy. Mr Ajit Singh Sandhu, SSP, Tarn Taran, had threatened him with dire consequences. They had met the IGP (Border), Mr D.R. Bhatti, but nothing had been done to trace Mr Khalra.

When contacted, Mr Bhatti said that a case had been registered at the instance of the wife of Mr Khalra for his kidnapping by "some unidentified" persons.

7 Sept - 1995

ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,7 ਸਤੰਬਰ (ਮੇਤਾ ਸਿੰਘ) - ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ: ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀਪੁਰ, ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 25000 ਹਜ਼ਾਰ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਖਿਲਾਫ ਚਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਿਆ।

ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਦਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ -**ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ** :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਵਿਚਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਵਰਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੱਲੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਸ: ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਸਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਸ: ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

- ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਿੰਗ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਉਚ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

7 Sept – 1995.

ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਸਤੰਬਰ–(ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਵੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 9 ਵੱਜ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਮਾਰੂਤੀ ਵੈਨ (ਨੰਬਰ ਡੀ. ਐਨ. ਵੀ. 5969) ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਮਾਰੂਤੀ ਵੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਜਿਪਸੀ ਵੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵ. ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ: ਖਾਲੜਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ?

Notice issued to SSP

By Our Legal Correspondent

CHANDIGARH, Aug 27 –

A Division Bench of the Punjab and Haryana High Court, comprising of Mr Justice G.S. Singhvi and Mr Justice T.H.B. Chalapati, on Friday issued notice to the Amritsar S.S.P., and S.H.O. Vijay Nagar police station, Amritsar for August 30, 1995 in a writ petition filed by Mala and Menu two women of Amritsar seeking the registration of a criminal case against Mr Om Parkash Gabbar, Municipal Commissioner, Amritsar and others.

In the petition filed through Mr Har Naresh Singh Gill, it was alleged by Mala and Menu that they were dragged from their house and kept in illegal custody by Mr Balkar Singh, S.H.O. of the Vijay Nagar police station. When the petitioners were produced before the executive magistrate they submitted an affidavit stating that Mr Gabbar wanted to entice them for illicit relations to which they objected. On coming to know about it, Mr Gabbar became agitated and at his instance the faces of both petitioners were blackened. They were also paraded in the market with a garland of shoes around their neck. The petitioners were beaten up in the presence of the SHO. Efforts of the petitioners to have a criminal case registered against Mr Gabbar and his supporters failed as he had the support of ruling Congress party.

Mr Gill further submitted that suchlike actions in a democracy like ours was unheard of. As such the Punjab government should be directed to register a criminal case against Mr Gabbar and others and adequate compensation be given to the petitioners.

Migration plea dismissed

The Punjab and Haryana High Court yesterday rejected the petition of Sarabjit Kaur who claimed migration from Budha Dental Institute, Magadh University to Government Dental College, Patiala. Migration was sought on the ground that the petitioner had to seek admission out of the State in 1990 because her father who was a police officer, faced threats from militants at that time.

It was stated in the petition that Surjit Singh who remained posted as SP (Zonal CID Patiala) played a considerable role in curbing terrorism and due to this the family came under extreme threat. In fact, her two maternal uncles, Gurdip Singh and Nachhattar Singh were killed by the BTFK on June 21, 1992 in Fatehgarh Sahib district.

The petitioner also claimed discrimination against her as another candidate Neelu Chhabra was allowed to migrate from Patna to Punjabi University, Patiala.

Mr Rajan Gupta with Mr Arvind Thakur, counsel who represented Punjabi University contented that the petitioner had obtained admission to Budha Dental Institute and now wanted to join a prestigious institute through the back door. Moreover no discrimination could be claimed as Neelu Chhabra fulfilled all conditions prescribed by the university. There was no legal right available to the petitioner to claim migration.

After hearing, a bench comprising Mr Justice R.P. Sethi and Mr Justice N.K. Sodhi dismissed the petition.

The petitioner was represented by Mr S.K. Sharma.

Notice issued

Mr Justice Swatantar Kumar issued a notice of motion to the SSP, Hoshiarpur, Jagtar Singh, Additional SHO and Manmohan Singh, son of Mrs Surjit Kaur Kalkat, Parliamentary Secretary in the Ministry of Beant Singh, Chief Minister, Punjab on a criminal writ petition filed by Sohan Lal seeking the registration of a case.

Mr K.S. Dadwal, along with Mr

26 Aug 1995

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,25 ਅਗਸਤ-(ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਮਾਵਰਿਸ ਡੀ. ਹਿਨਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੀ ਇਕ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ) ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਇਸ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਮੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀਂ 7 ਵਜੇ ਹੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨਗਿਊਟ ਲਿੰਡਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡ-ਬੀਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਠੱਟਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਠੰਢੀ ਖੂਹੀ ਲਾਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਘ-ਸੁੱਘ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ, 1995 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ: ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗੇਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਚ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੇਟ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਾਨੀਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਲਾਪਤਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਟਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ 20-20 ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਨ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 26 Aug 1995

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਅਗਸਤ (ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਮਾਵਰਿਸ ਡੀ. ਹਿਨਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਿਆ। ਸ਼੍ਰ. ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਿੰਡਾ ਅਤੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕੁੱਜ ਉਦਾਰਣਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਠੱਟਾ ਤੋਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਠੰਡੀ ਖੂਹੀ ਲਾਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ 22 ਅਗਸਤ 1995 ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਚਲੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਚੁਕ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗੇਟ ਜਬਰੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵਫਦ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ. ਸਕੱਤਰ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਲਾਨੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਹਜਾਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ)-ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ''ਇੰਟਰ ਰਿਲੀਜਨ ਫੇਥ ਫਾਰ ਵਰਡ ਪੀਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ'' ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਰੀਆ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।

Aug 26, 1995

US team visits Amritsar

Tribune News Service

AMRITSAR, Aug 25 – A nine-member US Human Rights team led by Mr Maurice D. Hinchey, US Congressman, today visited this border district to study the situation.

The team visited DAV Police Public School, where the children of militant victims' families are studying. The team also visited the Golden Temple to pay their obeisance, as also the Jallianwala Bagh. The team met various deputations, including the human rights wing of the Shiromani Akali Dal and supporters of the Akali leader, Mr Simranjit Singh Mann.

The team also met a number of victims of militants and listened to their woes.

The General Secretary of the human rights wing of the Shiromani Akali Dal, Mr Jaswant Singh Khalra, alleged that the state administration and the police had kept the visit of the US team a "secret". But he came to know about the visit from the US Embassy in New Delhi. In his 4-page memorandum submitted to the team, Mr Khalra dwelt upon state terrorism.

The information officer of the Golden Temple, Mr Amarjit Singh Grewal, apprised the visiting team about the alleged discriminations against the minorities in this country since Independence in August, 1947.

Mr Daljit Singh Sandhu, a supporter of Mr Simranjit Singh, thanked the US Congressmen for writing a letter to the Indian Prime Minister denouncing his detention in various cases under TADA on alleged flimsy grounds and seeking his release. He impressed upon the visiting team to prevail upon the Indian government to accept all the genuine demands of Sikhs and to restore their constitutional and democratic rights.

The visiting team was bestowed the "siropa" by the SGPC authorities.

Later the team visited the Wagah border to witness the retreat ceremony.

22 Aug 1995

ਬਡੂੰਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਅਗਸਤ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) –ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼, ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਹਵਾਲਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਕ 137 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੰਗ ਦਾ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੈਲ ਲਾਪਤਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਵਾਲਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਨੰਬਰ 177/ਡਬਲਿਊ) 30 ਦਸੰਬਰ 1992 ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਸ੍ਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ, ਹਵਾਲਦਾਰ ਰਛਪਾਲ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸ. ਪੀ. ਓ. ਕਿਰਪਾਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ 3 ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ 5 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਜ਼ੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ

(ਬਾਕੀ ਸਫਾ 5 ਕਾਲਮ 6)

ਅਤੇ
ਮਾਰ
ਦਿੱ
ਸ੍ਰੀ
ਅਗ
ਦਾ
ਜਨ
ਨਾਲ
ਵਿਚ
ਅਤੇ
ਇਕੱ
ਨੂੰ
ਵਿਧਾ

22 Aug 1995

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਅਗਸਤ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼, ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਹਵਾਲਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਕ 137 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੰਗ ਦਾ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੈਲ 'ਲਾਪਤਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਵਾਲਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਨੰਬਰ 177/ਡਬਲਿਊ) 30 ਦਸੰਬਰ 1992 ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਸ੍ਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ, ਹਵਾਲਦਾਰ ਰਣਪਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸ. ਪੀ. ਓ. ਕਿਰਪਾਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ 3 ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ 5 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਜੁਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ

(ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 5 ਕਾਲਮ 6)

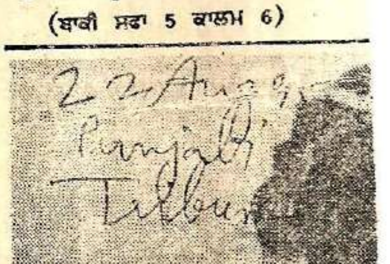

7 Aug 1995

ਨਿੰਮੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ...

ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਿੰਮਾ

ਹਰਕੰਵਲ ਕੋਰਪਾਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਅਗਸਤ -'ਚੰਦਰਾ! ਨਿੰਮਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਖੇ ਬੇਬੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ 'ਡਿੱਕੀ' (ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਐਲ. ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿਓਰ ਦਾ 13 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਨ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਡਿੱਕੀ ਮੁੰਝਾਲ) ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਟੀਆ ਸਾਬ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਗੋ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੱਤੜੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਭੋਲੇ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਲ ਪੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੇ ਪੁਤਰਾ! ਸੀਹਾਂ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ 'ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕਮਲਾ ਤਾਂ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਭਾਟੀਏ ਦੀ ਕੋਠੀਓਂ ਹੀ ਨਾ ਮੁੜਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਐ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਟੀਆ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿੰਮੇ ਨੇ ਲੋਪੋਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ.....ਤੇ ਫੇਰ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਟੱਪਿਆ ਹੋਣੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਨਿੰਮੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਦ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਫੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੰਮੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਮੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੱਫਰ ਨਹੀਂ ਜਾਲੇ ਪਰ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।'

ਮਮਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹੂਕ-ਛੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਇਹ ਬੋਲ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇ. ਐਲ. ਐਫ. (ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) ਦੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨਿਰੰਜਣ ਕੌਰ (55) ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਕਾਵੇਂ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਘਾਗ ਇੱਕਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀ ਨਿਰੰਜਣ ਕੌਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਗ਼ਮ ਨਾ ਝਲਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿੰਮਾ ਜਦੋਂ 1992 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ ਉੱਘੇ ਇੱਕਾ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਐਲ. ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਡ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਦੀ ਖਜ਼ਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ-ਬੋਲੀ ਭੂਆ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰੇ ਠਹਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਨਾਲ ਨਿੰਮੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਡੂੰਘਾ ਸਨੇਹ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੰਮਾ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਜਾਣੂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ, 1992 ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿਓਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੇਵਲ ਮੁੰਝਾਲ ਉਰਫ਼ ਡਿੱਕੀ ਨੂੰ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਨਿਰੰਜਣ ਕੌਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਨਿੰਮੇ ਦੀ ਭੂਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਕ ਦਾ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਸ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ) ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਹਤਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਦੇਵਨੇਤ ਹੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨਿੰਮਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਅਤੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਿੰਮਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਹਿਚਾਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸ੍ਰੀ ਨਿੰਮਾ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇ. ਐਲ. ਐਫ. (ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤੀਂ 11 ਵਜੇ 34 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਡਿੱਕੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਨਿਰੰਜਣ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿੰਮਾ ਸ੍ਰੀ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

ਬੀਬੀ ਨਿਰੰਜਣ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰਾਂ ਉਦੋਂ ਤਿੜਕਿਆ ਜਦੋਂ 1993 ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਈ ਵੇਰਕਾ ਚੌਕੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕੇਟ ਤੋਂ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿੰਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਨਿੰਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਵਰੀ, 1993 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿੰਮਾ ਲੋਪੋਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲ ਦੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿੰਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਆਰ. ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਲ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਹਵਾ ਹੋ ਗਈ।

ਨਿਰੰਜਣ ਕੌਰ

ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਨਿੰਮੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਿਆ।

ਬੀਬੀ ਨਿਰੰਜਣ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਰੂਬੀ ਨਾਮੀ ਕੈਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਿੰਮੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਡਕਾਰ ਲਏ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਇਸੰਸੀ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰੰਜਣ ਕੌਰ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿੰਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਪਤ੍ਰਿਕਾ 6 AUG 1995

ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਿਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੰਡਨ–ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪੰਜਵਾੜ ਗੁਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ

ਤਰਨਤਾਰਨ, 4 ਅਗਸਤ -ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਵਿਚ ਛੱਪੀ ਖ਼ਬਰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਦਾਰ [illegible] ਵਿਚ ਸਾਲ 1974 [illegible] ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ [illegible] ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1979 ਵਿਚ ਇਹ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਉਪਰੰਤ ਇਸਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਸਾਲ 1988 ਵਿਚ ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲਗਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਰਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਰੋਟੀਨ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਦਫਤਰ ਜੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੋਂ ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਪੋਸਟ ਤੂਤ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 28.3.95 ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ 10.7.95 ਨੂੰ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਖ਼ੁਦ ਬਾਖੁਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਵਾਲਦਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਾਲੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਅੱਗੋ [illegible] ਵੀ ਗੱਲ [illegible] ਕਿਸ [illegible] ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਾਕੀਪੁਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਾਕੀਪੁਰ ਇਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ [illegible] ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ [illegible] ਬਿਨਾਹ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਭੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਰਕਵਾਂ ਲਈ। ਮਿਤੀ 6.6.95 ਨੂੰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਭੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮਿਤੀ 7.6.95 ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ 107/151 ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਢਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਲਾਸੌਰ ਨੇ ਇਕ ਰਿਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਦ ਸੁਣਵਾਈ ਰਿਟ ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਮਿਤੀ 24.7.95 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਿੰਡ ਝਾਮਕੇ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਥਾਣਾ [illegible] ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ [illegible]

[illegible] ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਝਾਮਕੇ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥਾਣਾ ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੈਨ ਵਿਚੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ [illegible] ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਆਦਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਨੇ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਉਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਗਰੁਪ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਗੂੜੇ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੁਟਪਾਓ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਗਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਮਨਘੜਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮਈ ਹੈ। ਪੰਜਵਾੜ ਗਰੁਪ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰਮਦੇ ਸਨ ਉਹ [illegible] ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ [illegible] ਬਾਹਰਲੇ [illegible] ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ [illegible] ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਅਰਚਨਾ ਸੈਕਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਵੜ ਗਰੁਪ ਦੇ ਦੋ ਅਤਵਾਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਸਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਾਮ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੇ ਅਸਾਲਟਾ ਸਮੇਤ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਰਿਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨਘੜਤ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।

30 July 1995

Doctored post-mortem reports worry NHRC

NEW DELHI, July 30 (PTI) – The National Human Rights Commission (NHRC) has expressed serious concern over the increasing incidents of divergent post-mortem reports of custodial deaths or deaths under suspicious circumstances.

The commission had recently convened a meeting of top medical experts to discuss the issue of the law enforcing agencies resorting to second post-mortem in cases of unnatural deaths.

This issue was discussed threadbare and suggestions were made to ensure that the first post-mortem report was as foolproof as possible. Some of the members of the commission suggested to the experts from the Medical Council of India (MCI) to look into whether the post-mortem was actually and properly done and whether there was a delay in conducting the post-mortem and the possibility of manipulation to suit "vested interests", sources said.

When contacted, MCI sources said they would present a report shortly to the NHRC on the present position of post-mortem in the country and suggestions regarding action to be taken on a short – term as well as long – term perspective.

Taking cognizance of the two recent cases in Tamil Nadu where deaths of two Scheduled Caste women and a nurse were altered from suicides to suspicious death and homicide respectively on the basis of the second post-mortem reports, the NHRC has decided to take up the issue for serious consideration, the sources said.

Even in the recent sensational "tandoor" murder case in Delhi, two post-mortems were carried out on the charred and chopped body of Naina Sahni giving altogether different findings.

In a number of incidents especially pertaining to custodial deaths, post-mortem reports were "doctored" to suit the interests of the police and there were also inordinate delays in submitting them, the sources said.

While the commission would seek information regarding post-mortem cases from all the states through a proforma, the experts have been asked to suggest the name of a doctor who could be associated with an inquiry into the custodial deaths in Tihar Jail.

ਅਜੀਤ 7 Sept

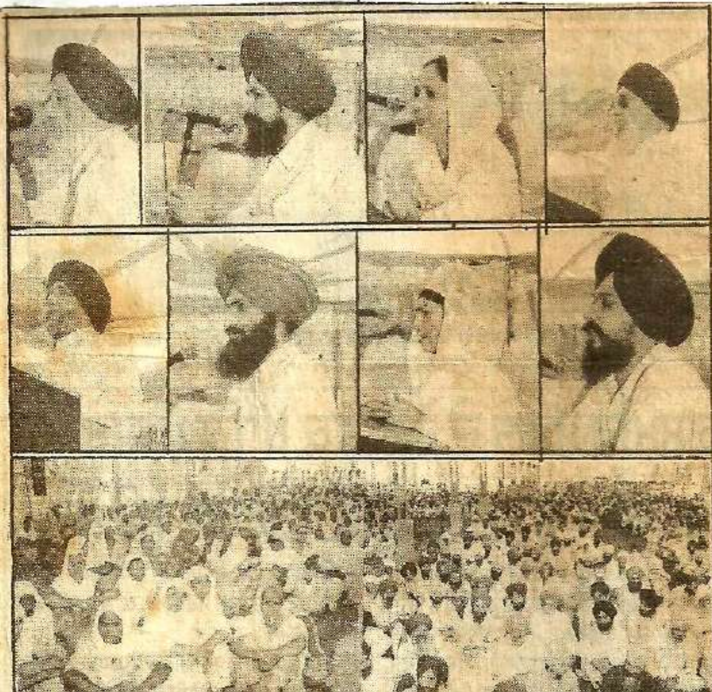

ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਖਾਲੜਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁਪਤਨੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਸ: ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕ ਐਮ. ਐਲ. ਏ., ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ, ਸ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਕਨਵੀਨਰ ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹੇਠਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ। ਫੋਟੋਆਂ : ਨਿਰਮਲ ਸਟੂਡੀਓ

29 July 1995

ਪੁਲਿਸ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਸਫ਼ਾ 3 ਦੀ ਬਾਕੀ

ਦੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਲਕੇ ਲਾਗੇ ਡਰੇਨ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੀਬੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਡਣ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗਿਉਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪੂਹਲਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਪੂਹਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਆਓ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵੈਨ (ਨੰ: ਪੀ. ਬੀ. 02-3202) ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਏ ਤਾਂ ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਨੇੜੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੈਨ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨ ਵਿਚੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਵਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਮ ਨਾਥ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਰਾਮ ਨਾਥ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣ ਕੂੜੇ ਆਸਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਅਜੀਤ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਇਥੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।

29 ਜੁਲਾਈ

ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਪਗ 25000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਵਾਰਿਸ 6017 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 1135 ਦਾ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਜੈਨ ਸਭਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ, 1915 ਦਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਹੋਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

29 July 1995.

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ !

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਜੁਲਾਈ-(ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਮਕ-ਮਾਰ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਾਲੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਏਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉ[illegible] ਨੂੰ ਆਪਣ[illegible] [illegible] ਰਹਿੰਦੇ 21 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ [illegible] ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿ[illegible] ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, 'ਅਜੀਤ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਕੇ ਸਾਲੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਝਬਾਲ ਨੂੰ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਝਬਾਲ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ) ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ, 1993 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਝਬਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਕ ਟੈਕਰ (ਨੰ: ਪੀ. ਬੀ. 02-9938) ਰਾਹੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੁੜ ਉਸ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਪਿਛੋਂ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਲਾਂ ਵਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਉਥੋਂ ਟੈਕਰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।

ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਭਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਝਬਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੱਠ-ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਲਾਹ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਵੰਬਰ 1994 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਰਿਟ ਨੰ: 853/94) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਰਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਉਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ।

ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਲਟੋਹੇ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਤੂਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 311 ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੀਤੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਡੂੰਮ ਡਰਾਵੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਜਸਪਾਲ ਨਗਰ [illegible]ਬਾਦੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਏਨਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 10 ਜੁਲਾਈ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾਲਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਕੇ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਘੱਟ ਏਨਾ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ।'

ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇ. ਸੀ. ਐਫ. (ਪੰਜਵੜ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸ: ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਅਜੀਤ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਵੜ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੜਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਉਘ-ਸੁੱਘ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਐਚ. ਐਸ. ਬੇਦੀ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਅਤੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਝਬਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, 'ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾ ਰਸਤਾ ਛੋੜ ਕਰ ਅਪਨੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੋ।' ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹੇ ਘੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬੰਦੇ (ਰਾਜੂ) ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ

ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਬੀਬੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ

ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸਿਟੀ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਸ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਢਾਂਗੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 7-51 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ-ਪਿੰਡ ਝਾਮਕੇ ਕਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ 21 ਜੁਲਾਈ, 1992 ਨੂੰ ਬਾਲਕੇ ਨੇੜੇ ਡਰੇਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਤੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਤੀਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਨੇ 'ਅਜੀਤ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਜੂਨ, 1992 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਘਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ (21) ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ (19) ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੋੜਾ ਚੌਕੀ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ

(ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 8 ਕਾਲਮ 7)

28 July 1995

'Cops cremated bodies without sanction'

AMRITSAR, July 28 (PTI) – The Human Rights wing of the Shiromani Akali Dal today claimed that the bodies of more than 25,000 Sikhs who were eliminated by the Punjab Police on the pretext of being militants or their sympathisers, were cremated at crematoriums throughout the state by the cops themselves.

In a statement here today, the Human Rights Organisation's General Secretary Jaswant Singh Khalra said in Amritsar district alone 6017 'unclaimed bodies' were cremated by the cops. Out of this 1135 were cremated at the Jain Sabha cremation grounds at the sub-divisional town of Patti, 1915 at Tarn Taran town and another 2000 odd at the cremation grounds in Amritsar city. The statement said while records of these unlawful cremations existed these were not being made public.

The statement regretted that none of the political parties or the judicial courts had intervened to question the right of the Punjab Police to cremate the bodies in such fashion. The statement called upon the Akali Dal chief Parkash Singh Badal to take up this issue with other political parties.

The four-page statement signed by Mr Khalra further claimed that a total of 17,634 Sikhs were detained under TADA and more than 40,000 tortured inhumanly during the past couple of years. A number of those who were detained under TADA were later released by the courts, the statement said while urging those who had been released to file compensation cases against the government.

The statement alleged that those who had filed public interests litigation (PIL) petitions against the Punjab Police were being harassed by police officers and were being pressurised and bribed for withdrawing these. The statement urged the courts to expedite all pending PIL petitions.

The statement also criticised Chief Minister Beant Singh's statement that the government would protect those police officers who were being hauled up by the judicial courts. The statement demanded that the courts should take a serious note of this statement of the Chief Minister.

28 JULY 1995

'Cops cremated bodies without sanction'

AMRITSAR, July 28 (PTI) – The Human Rights wing of the Shiromani Akali Dal today claimed that the bodies of more than 25,000 Sikhs who were eliminated by the Punjab Police on the pretext of being militants or their sympathisers, were cremated at crematoriums throughout the state by the cops themselves.

In a statement here today, the Human Rights Organisation's General Secretary Jaswant Singh Khalra said in Amritsar district alone 6017 'unclaimed bodies' were cremated by the cops. Out of this 1135 were cremated at the Jain Sabha cremation grounds at the sub-divisional town of Patti, 1915 at Tarn Taran town and another 2000 odd at the cremation grounds in Amritsar city. The statement said while records of these unlawful cremations existed these were not being made public.

The statement regretted that none of the political parties or the judicial courts had intervened to question the right of the Punjab Police to cremate the bodies in such fashion. The statement called upon the Akali Dal chief Parkash Singh Badal to take up this issue with other political parties.

The four-page statement signed by Mr Khalra further claimed that a total of 17 634 Sikhs were detained under TADA and more than 40,000 tortured inhumanly during the past couple of years. A number of those who were detained under TADA were later released by the courts, the statement said while urging those who had been released to file compensation cases against the government.

The statement alleged that those who had filed public interests litigation (PIL) petitions against the Punjab Police were being harassed by police officers and were being pressurised and bribed for withdrawing these. The statement urged the courts to expedite all pending PIL petitions.

The statement also criticised Chief Minister Beant Singh's statement that the government would protect those police officers who were being hauled up by the judicial courts. The statement demanded that the courts should take a serious note of this statement of the Chief Minister.

28 JULY 1995

CONT----

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

28/7/95

(ਸਫਾ 1 ਦੀ ਬਾਕੀ)

ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਦੋ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੇ ਦੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੱਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਟ ਵਢ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਭਣਵਈਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ 7 ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲੈਈ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਕੋ: ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀਪੁਰ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀਪੁਰ ਦੀ ਪਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਕੇ ਘੁਮਾਈ ਗਈ। ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ: ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਛਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅੰਦਰਲੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 1984 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 311 ਤਹਿਤ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ: ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

28 July 1995

ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲੇ

ਅਜਨਾਲਾ, 28 ਜੁਲਾਈ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਊਸਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ-ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਖਾਤਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ । ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 5017 ਦਾ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1135ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਜੈਨ ਸਭਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ, 1915 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ-ਘਾਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2967 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ-ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸ੍ਰ: ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੁਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਹਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ । ਸ੍ਰ: ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 17634 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2548, ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ 2203, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1728, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 6479 ਟਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਹਲੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 30 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਲਟੋਹਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਚੈਕ-ਅੱਪ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਜਿਪਸੀ ਉੱਪਰ ਪੱਟੀ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਨਦਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਬਾਕੀ ਸਫਾ 6 'ਤੇ)

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ (ਭਾਸ਼ਾ)—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10-15 ਕੇਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ।

ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰੇ।

TRIBUNE JULY 3, 1995

(AN OPEN LETTER TO KPS GILL)(CONTD)

punishment has been given to those responsible for atrocities on men as well as women for reasons having nothing to do with the fight against terrorism? The government should defend the former type, but should the latter type, too, be protected?

What has provoked me to write this letter has something to do with hockey, a game which I too tried to play during my college days. I must say that I did not like your becoming the Indian Hockey Federation chief for only one reason, i.e. every minute of yours was needed to evolve a new strategy for the new situation and for making some amends, at least, for the wrong done during the fight against terrorism. Also, I considered highly objectionable the way the police officers were used to win the federation battle. In due course of time, I forgot about it all. Recently, all this came back to my mind with a bang.

A young girl of my town had either been kidnapped, or enticed away by some persons. After some days, the police registered an FIR. The girl was sent to her parents' home in U.P. by those who had taken her away. She was brought to Amritsar. The police took her into custody on the valid ground that she would be sent for a medical examination. I asked an officer why this was being delayed. I was told that the police force was busy in connection with a hockey match being played in Guru Nanak Dev University on May 31, where you as the President of the Indian Hockey Federation were to be the chief guest. Invitations were issued by your S.S.P. as "President, District Hockey Association".

More recently, I came across another invitation issued by him in connection with another hockey match to be played on June 15 in G.N.D. University at which one of our DGPs was to be the chief guest and an I.G.P. was to preside with the local Mayor thrown in as the guest of honour. Perhaps, Amritsar pattern for district hockey associations is typical and not an exception.

I wonder how much time, preoccupation with hockey on the one hand and VIP duties on the other (as you know we have a battalion of ministers and our Chief Minister is very much mobile despite his age) leave the police force to fight crime, which seems to be on the increase.

There are other problems which remain unattended. For instance, about 125 private buildings, if not more, were illegally occupied by the police for its needs during the days when terrorists were on the top. Owners are not being paid rent. Except one or two, these are not being vacated even after the matter was agitated in the March 1995, session of the state assembly. Let that be.

Your contribution in the difficult task of restoring peace is indeed big and needed to be recognised and rewarded. But as long an extension as "Mr Gill wants" even after two years of extension after superannuation is open to many objections. There are people in Punjab who think that this may have something to do with the help you allegedly rendered to a grandson of the Chief Minister and the Chief Minister himself in the Katia episode.

I would like to believe that this is not true.

With regards,
Yours sincerely
(Satya Pal Dang)
27.6.1995

Mr K.P.S. Gill, IPS,
D.G.P. Punjab,
Chandigarh.

ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) –ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਦਬਕਾਇਆ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ–ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀਪੁਰ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਗੁਰਬੇਜ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਟਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰੌਅ ਵੇਖਣ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਨੇਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਬਿਲੇ ਲਗਾ ਦੇਣ" ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਿੜ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਬੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ।

ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਿਆਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ 8 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 1993 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 94 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਉਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ 94 ਨੂੰ ਪੁਲ ਕੁੰਜਰ, ਧਾਰੀਵਾਲ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਿਚ ਹੋਏ "ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ" ਵਿਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਾਜੂ ਪਿੰਡ ਭੇਟੀ ਪਸਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੂਬਾ ਜਾਗੋਵਾਲ ਬੇਟ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਮਾਰੇ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੁਰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਬੇਜ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

10 June-1995.

5 MAY 1995

ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰਾ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ-ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸੇ ਅਯਾਲਾਲੋਸੋ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਫਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਥਾਨਕ ਮਾਊਂਟਵਿਊ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਫਦਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਲੋਸੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲੱਖਨਪਾਲ ਇਕੋ ਵਫਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਰੰਜਨ ਲੱਖਨਪਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਲੱਖਨਪਾਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਲੋਸੋ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਈ।

ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਪ੍ਰੋ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਫਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਦੇ ਉਸ ਲੇਟਰ ਪੈਡ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਖੰਡਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਸ: ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਚ ਐਮਨੇਸਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਟਾਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 1992 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਰਅਮਨ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ 12 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਫਦ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ੧ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੀਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਲੋਸੋ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੋਗਾ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਲੋਸੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮੇਗਾ ਸਾਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ, ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦਾਦੂਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਵਾਸੀ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਮ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੋ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਫਿਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ

19 April 1995

Punjabi Tribune.

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਰ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ 1993 ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਉਰਫ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। 17 ਮਈ 1993 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤੜਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਲੈਟ ਵਿਚ ਘੁਸ ਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ। ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਈ ਗਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਕ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਐਲ. ਵਡੇਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੰਕੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਨਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਇਕੋ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਖ ਕੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਏਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਔਰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਕਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ [illegible]

ਅਜੀਤ 10 April - 1995.

10 April 95

ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ

ਅਜਨਾਲਾ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ-(ਵਿ. ਪ੍ਰ.) ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ: ਖਾਲੜਾ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੋਕਟਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਿਆਂਗ ਚੇਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋਹਨ ਵਾਲਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਕਤ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ. ਐਨ. ਕੋਲ ਵੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ: ਖਾਲੜਾ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਦੀਨਾਨਗਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੜੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

23 MARCH 1995

ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਮਾਰਚ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਵਾਰਸ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸ: ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਸ: ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰੇਗੀ । ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬਾਪ ਤੇ ਪਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਨਤਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ । ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ।

ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਣਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਲ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਤਹਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੱਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਰਾਪ ਦੇ ਨਿਆਈਂ ਹੈ । ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਇਸ ਮਹਾਂ ਨਰ-ਸੰਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ

(ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 6 'ਤੇ)

ਜਥੇਬੰਦੀ

(ਸਫਾ 1 ਦੀ ਬਾਕੀ)

ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰੇਗਾ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇ-ਸਹਾਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਤੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜੋ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ।

April 6-13 . P.T. CANADA

20 March 1995

ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਮਾਰਚ -(ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬੀਤੀ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਘਰਿਆਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨਿਵਾਸੀ 65 ਸਾਲਾ ਸ. ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਉਕਤ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੱਟੜ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਵਲਟੋਹਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕਾ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ।

ਸਰਦਾਰ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਔਟਵਾ--ਬਰੈਮਲੀ-ਗੋਰ-ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਸਰਦਾਰ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨਾਲ ਤੁਆਰਫ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਔਟਵਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫ਼ਖਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖ਼ੁਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੋ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਟਾਡਾ (Terrorist And Disruptive Activities [Prevention] Act) ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੌਲਾਰੱਪਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ।

ਸਰਦਾਰ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੀਤਾ।

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ

[ਪੰ]ਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ [ਰਾ]ਈਟਸ ਗਰੁੱਪ (ਯੂ.ਕੇ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ [ਸ.] ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਿੱਖ ਐਮ.ਪੀ. ਸ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ [ਕੀ]ਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ' ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ [ਜਿਸ]ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ [illegible] ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰੀ [ਅੱ]ਤਵਾਦ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ [illegible] ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ [illegible] [ਨਹੀਂ ਹੋ] ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਫਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੀ [ਵਾਪਰ] ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਐਮ.ਪੀ. ਡੈਰਿਕ ਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲਿਆਨ ਬਿਊਮੀਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ [ਦੀ] ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ, ਸ. ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਸ. ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ [ਹਾਂ]। [ਉ]ਪਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸ. ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨਾਲ ਓਟਾਵਾ ਵਿਖੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

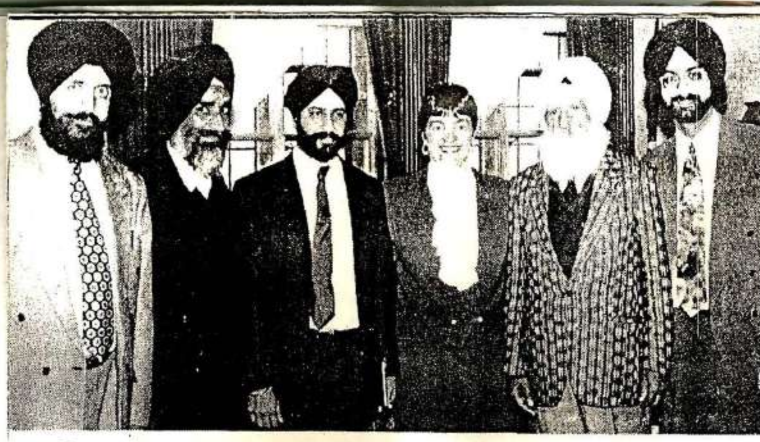

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ

ਔਟਵਾ-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ, *ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ,* ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਾਰਚ 1995 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏ (ਯੂ.ਕੇ.) ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਲੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿ: ਰੇਮੰਡ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਉਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਪੀ. ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਲੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ I ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ: ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾ: ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਔਟਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ [illegible]

ਮਿਊਂਸਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਪਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6017 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦਰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।

ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਨਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੁਲੀਨ ਬੋਮੀਏ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ [illegible] ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਹਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

APRIL 6-13 1995
PUNJABI TRIBUNE
CANADA

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ -28 Feb 1995

ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਹੋਣਾ : ਖਾਲੜਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਫ਼ਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਕੈਟ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਭ ਪੈਮਾਨੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਕਰ ਕੇ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਅਜੀਤ 4 FEB 1995

ਅਜੀਬ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ...

ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 1991 ਤੋਂ 1994 ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਾੜਕੂਆਂ, ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ-ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਟੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲੇ ਲਾਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੋਹਤਬਰ ਤੇ ਆਮ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਟੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ 'ਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ 'ਚ 1991 ਤੋਂ 1994 ਦੌਰਾਨ ਬਿਲੇ ਲਾਈਆਂ 538 'ਲਾਵਾਰਿਸ' ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 35 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਦਫ਼ਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਿਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ

ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲੇ ਲਾਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ 538 ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 115 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੱਟੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, 103 ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ, 101 ਵਲਟੋਹਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, 61 ਖਾਲੜਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, 50 ਹਰੀਕੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, 35 ਖੇਮਕਰਨ ਥਾਣੇ ਤੋਂ 9 ਕੱਚਾਪੱਕਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, 5-5 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਭਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਅਤੇ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਘੜਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 52 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚੂਸਲੇਵੜ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਚੂਸਲੇਵੜ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 1994 ਵਿਚ ਪੱਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ

(ਬਾਕੀ ਸਫਾ 8 ਕਾਲਮ 1)

ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ (ਸਫਾ 1 ਦੀ ਬਾਕੀ)

ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਠੱਟਾ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੁਬਲੀ ਦਾ 65 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਪੰਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 'ਅਜੀਤ' ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ 'ਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲੇ ਲਾਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਵਰੀ, 1992 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 1992 ਤੱਕ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ 412 ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ। ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਣੇ ਦਾ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 'ਲਾਵਾਰਿਸ' ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੂ ਰਿੱਟ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ-ਹਿਤੂ ਰਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਕਤ 'ਲਾਵਾਰਿਸ' ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 1994 ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੜਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

INDIAN EXPRESS
FRIDAY FEB 3, 1995

Skeletons in Punjab police cupboard

by S. P. S. Pannu

PATTI (Amritsar) – Damning evidence has surfaced of the bodies of suspected terrorists killed in police custody having been cremated as "unclaimed". This was done not only at the height of terrorism in Punjab but even after the situation had changed for the better.

Evidence gathered by Indian Express reveals that during the three-year period between 1991 and 1993 the Punjab police dumped at least 426 bodies for cremation as "unclaimed", at the expense of the Patti Municipal Committee alone. In many cases, the relatives of the deceased were not informed, even though they had been identified.

Significantly, even after a complete turn-about in the law and order situation, the incidents continued, although their frequency declined. During 1994, the Patti Municipal Committee records show that at least 17 "unclaimed" bodies were brought by the police for cremation.

An extensive tour of the Amritsar district revealed that the families of those picked up by the Punjab police for suspected links with terrorists, still nurture hope of their returning home. While some families have moved habeas corpus petitions in the high court, several others have not done so for fear of police reprisals. Sources within the police disclosed that while some of the "missing" persons may have succumbed to torture by the police, some others may have been eliminated if they happened to be witnesses to these deaths in police custody.

UNDERCURRENT: While, informed political leaders acknowledge that extra-constitutional methods may have helped root out terrorism, the cost in terms of innocent lives lost appears to have been heavy. Said veteran CPI leader, Satya Pal Dang, "this has left an undercurrent of resentment in the rural areas".

The Punjab DGP, Mr K. P. S. Gill, has been maintaining that the missing youths in Punjab had gone abroad as illegal immigrants and were working there. The Additional Director General of the Punjab Police (Operations), Mr P. C. Dogra, denied any knowledge of cremations of such "unclaimed" bodies. "The state police have killed only terrorists in encounters and all these deaths have been recorded by the press as well," he added.

PLEA REJECTED: A human rights group had also compiled statistics from these municipal records and moved the high court. However, the plea was dismissed last fortnight on the ground that the affected families should be a party to the petition. A visit to the Amritsar and Tarn Taran cremation grounds confirmed that several hundred bodies were brought as "unclaimed" by the Punjab police and cremated at the expense of the municipal committees of these towns as well. Police records show that some of them were subsequently "identified" for claiming the "unannounced rewards".

Some citizens of Patti town claimed that at times they had to arrange for more wood to take care of the smouldering bodies on the cremation grounds as often the wood fell short due to the large number of unclaimed bodies coming in. These bodies were brought to Patti from various villages under the Valtoha, Bhikiwind, Harike, Kairon and Khalra police stations.

In Amritsar, Baba Bhut Nath who lights the funeral pyres at the Durgiana Mandir crematorium said that during 1992 and 1993, often five or six unclaimed bodies brought in on a single day. According to the Tarn Taran crematorium staff during 1992-1993, sometimes seven or eight unclaimed bodies were cremated in a day.

CONTRADICTORY: During 1992, the Amritsar Municipal Corporation paid for the cremation of 300 "unclaimed" bodies of youths. Sources in these municipal committees disclose that all these payments have been made by cheque and this evidence exists in the records of the banks as well. In a few cases the relatives of the "unclaimed" deceased managed to get information about the death in custody. They then contacted the cremation staff on their own and made payments for a "better" funeral.

Surprisingly while the police have submitted in writing that these persons were unidentified or unclaimed, their names and the villages they hail from are mentioned in the list. A visit to some of these villages by an Indian Express team showed that some youths had actually been picked up by the police from there.

INDIAN EXPRESS FEB 3, 1995

Skeletons tumble out of Punjab police vaults

by S.P.S. Pannu

PATTI (Amritsar) – Damning evidence has surfaced of the bodies of suspected terrorists killed in police custody having been cremated as "unclaimed". This was done not only at the height of terrorism in Punjab, but even after the situation had changed for the better.

Evidence gathered by *Indian Express* reveals that during the three-year period between 1991 and 1993, the Punjab police dumped at least 426 bodies for cremation as "unclaimed", at the expense of the Patti Municipal Committee alone. In many cases, the relatives of the deceased were not informed, even though they had been identified.

Significantly, even after a complete turn-about in the law and order situation, the incidents continued, although their frequency declined. During 1994, the Patti Municipal Committee records show that at least 17 "unclaimed" bodies were brought by the police for cremation.

An extensive tour of the Amritsar district revealed that the families of those picked up by the Punjab police for suspected links with terrorists, still nurture hope of their returning home. While some families have moved habeas corpus petitions in the High Court, several others have not done so for fear of police reprisals.

Sources within the police disclosed that while some of the "missing" persons may have succumbed to torture by the police, some others may have been eliminated if they happened to be witnesses to these deaths in police custody.

While informed political leaders acknowledge that extra-constitutional methods may have helped root out terrorism, the cost in terms of innocent lives lost appears to have been heavy. Said the veteran CPI leader, Mr Satya Pal Dang, "This has left an undercurrent of resentment in the rural areas".

The Punjab DGP, Mr K.P.S. Gill, has been maintaining that the missing youth in Punjab had gone abroad as illegal immigrants and were working there. The Additional Director General of the Punjab police (Operations), Mr P.C. Dogra, denied any knowledge of cremations of such "unclaimed" bodies. "The state police have killed only terrorists, in encounters and all these deaths have been recorded by the press as well", he added.

A human rights group had also compiled statistics from these municipal records and moved the high court. However, the plea was dismissed last fortnight on the ground that the affected families should be a party to the petition.

A visit to the Amritsar and Tarn Taran cremation grounds confirmed that several hundred bodies were brought as "unclaimed" by the Punjab police and cremated at the expense of the municipal committees of these towns as well. Police records show that some of them were subsequently 'identified' for claiming the "unannounced rewards".

Some residents of Patti town claimed that at times they had to arrange for more wood to take care of the smouldering bodies on the cremation grounds as often the wood fell short due to the large number of unclaimed bodies coming in. These bodies were brought to Patti from various villages under the Valtoha, Bhikiwind, Harike, Kairon and Khalra police stations.

In Amritsar, Baba Bhut Nath, who lights the funeral pyres at the Durgiana Mandir crematorium, said that during 1992 and 1993, often five or six unclaimed bodies were brought in on a single day. According to the Tarn Taran crematorium staff, during 1992-1993, sometimes seven or eight unclaimed bodies were cremated in a day.

During 1992, the Amritsar Municipal Corporation paid for the cremation of 300 "unclaimed" bodies of youth. Sources in these municipal committees disclosed that all these payments w[ere] made by cheque and this evi[dence] exists in the banking rec[ords] as well.

In a few cases the relatives [of] the "unclaimed" deceased m[an]aged to get information about [their] death in custody. They then co[n]tacted the cremation staff [on] their own and made paymen[ts] for a "better" funeral.

Surprisingly, while the poli[ce] have submitted in writing th[at] these persons were unidentifi[ed] or unclaimed, their names a[nd] the villages they hail from [are] mentioned in the list. A visit [to] some of these villages show[ed] that some youth had actuall[y] been picked up by the poli[ce] from there.

INDIAN EXPRESS
FRIDAY FEB 3, 1995

Skeletons in Punjab police cupboard

by S. P. S. Pannu

PATTI (Amritsar) – Damning evidence has surfaced of the bodies of suspected terrorists killed in police custody having been cremated as "unclaimed". This was done not only at the height of terrorism in Punjab but even after the situation had changed for the better.

Evidence gathered by Indian Express reveals that during the three-year period between 1991 and 1993 the Punjab police dumped at least 426 bodies for cremation as "unclaimed", at the expense of the Patti Municipal Committee alone. In many cases, the relatives of the deceased were not informed, even though they had been identified.

Significantly, even after a complete turn-about in the law and order situation, the incidents continued, although their frequency declined. During 1994, the Patti Municipal ...mmittee records show that ... least 17 "unclaimed" bod... were brought by the police ... cremation.

... extensive tour of the ...sar district revealed that ...milies of those picked ... the Punjab police for ...ted links with terrorists, still nurture hope of their returning home. While some families have moved habeas corpus petitions in the high court, several others have not done so for fear of police reprisals. Sources within the police disclosed that while some of the "missing" persons may have succumbed to torture by the police, some others may have been eliminated if they happened to be witnesses to these deaths in police custody.

UNDERCURRENT: While, informed political leaders acknowledge that extra-constitutional methods may have helped root out terrorism, the cost in terms of innocent lives lost appears to have been heavy. Said veteran CPI leader, Satya Pal Dang, "this has left an undercurrent of resentment in the rural areas".

The Punjab DGP, Mr K. P. S. Gill, has been maintaining that the missing youths in Punjab had gone abroad as illegal immigrants and were working there. The Additional Director General of the Punjab Police (Operations), Mr P. C. Dogra, denied any knowledge of cremations of such "unclaimed" bodies. "The state police have killed only terrorists in encounters and all these deaths have been recorded by the press as well," he added.

PLEA REJECTED: A human rights group had also compiled statistics from these municipal records and moved the high court. However, the plea was dismissed last fortnight on the ground that the affected families should be a party to the petition. A visit to the Amritsar and Tarn Taran cremation grounds confirmed that several hundred bodies were brought as "unclaimed" by the Punjab police and cremated at the expense of the municipal committees of these towns as well. Police records show that some of them were subsequently "identified" for claiming the "unannounced rewards".

Some citizens of Patti town claimed that at times they had to arrange for more wood to take care of the smouldering bodies on the cremation grounds as often the wood fell short due to the large number of unclaimed bodies coming in. These bodies were brought to Patti from various villages under the Valtoha, Bhikiwind, Harike, Kairon and Khalra police stations.

In Amritsar, Baba Bhut Nath who lights the funeral pyres at the Durgiana Mandir crematorium said that during 1992 and 1993, often five or six unclaimed bodies brought in on a single day. According to the Tarn Taran crematorium staff during 1992-1993, sometimes seven or eight unclaimed bodies were cremated in a day.

CONTRADICTORY: During 1992, the Amritsar Municipal Corporation paid for the cremation of 300 "unclaimed" bodies of youths. Sources in these municipal committees disclose that all these payments have been made by cheque and this evidence exists in the records of the banks as well. In a few cases the relatives of the "unclaimed" deceased managed to get information about the death in custody. They then contacted the cremation staff on their own and made payments for a "better" funeral.

Surprisingly while the police have submitted in writing that these persons were unidentified or unclaimed, their names and the villages they hail from are mentioned in the list. A visit to some of these villages by an Indian Express team showed that some youths had actually been picked up by the police from there.

ਅਜੀਤ 25 Jan - 1995

ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 25 ਜਨਵਰੀ-(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਘਰਿਆਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਹਿਣਾ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂ ਇਥੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਜਨਵਰੀ-(ਸ. ਰ.) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁ: ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ।

ਅਜੀਤ

20 JAN 1995

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ-ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ

ਅਜੀਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਜਨਵਰੀ-(ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਛਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਢੀ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਦਲੀਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਅਲੀ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਵਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਗੁੰਮ' ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਘੱਤਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ', ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਸਚਾਈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ 17 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਬੀ.ਆਰ. ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 17 ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਬੇਕਫਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

23 ਜੁਲਾਈ 1992 ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 1992 ਤੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 168 ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1992 ਵਿਚ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕੇਵਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 64 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੱਟੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ।

ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 18, ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ 18, ਹਰੀਕੇ ਨੇ 11, ਕੈਰੋਂ ਨੇ 11, ਪੱਟੀ ਨੇ 11 ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਥਾਣਾ ਨੇ 6 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਥੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 455 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਲਣ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

20 Jan 1995   4

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ-ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਜਨਵਰੀ-(ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ). ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਛਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਢੀ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਦਲੀਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਅਲੀ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਵਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਗੁੰਮ' ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਘੱਤਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ', ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਸਚਾਈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ 17 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਨੇ ਦਿਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੋਤਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਬੀ.ਆਰ. ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 17 ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਬੇਕਫਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

23 ਜੁਲਾਈ 1992 ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 1992 ਤੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 168 ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1992 ਵਿਚ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕੇਵਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 64 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੱਟੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ।

ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 18, ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ 18, ਹਰੀਕੇ ਨੇ 11; ਕੈਰੋਂ ਨੇ 11, ਪੱਟੀ ਨੇ 11 ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਥਾਣਾ ਨੇ 6 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਥੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 455 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਲਣ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

CONT....

19 JAN 1995

ਮੀਤਾ ਤੇ ਡੋਲੀ (ਸਫਾ 1 ਦੀ ਬਾਕੀ)

(ਸਫਾ 1 ਦੀ ਬਾਕੀ)

ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਮੀਤਾ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਡੋਲੀ ਅਤੇ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਭਿਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਸੰਗਰੂਰ) ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਤਾ-ਡੋਲੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੀਤਾ ਦੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ ਦਸਦੀ ਰਹੀ।

ਜੁਲਾਈ 93 ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੋਲੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਤੰਬਰ 93 ਤੱਕ ਤਰੀਕਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਤੰਬਰ 93 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 23-24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੋਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੇ ਡੋਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੋਲੀ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਮੈਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਖੇਪ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।' ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡੋਲੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 11 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ 600 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੋਲੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥਕੜੀ ਸਮੇਤ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ 600 ਰਾਊਂਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਖੋਖੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਏ.ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਐਲ. ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਦੀ ਸਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਐਲ. ਆਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 17 ਅਗਸਤ 1993 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਲੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਸੇ।

ਹੁਣ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਰੰਜੀਤ ਪਚਨੰਦਾ ਵਲੋਂ ਥਾਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨੇ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਤਾ ਤੇ ਡੋਲੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਦੇ ਐਸ. ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 93 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ ਯਮੁਨਾਨਗਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਥੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਮ ਵਿਚ ਪਾਗਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਛੁੱਡਾ ਦੇਵੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੀਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਮੀਤਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗਲੇ ਵਿਚ ਲਟਕਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌ-ਸੌ ਵਾਰ ਕੋਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਣ।

ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੋਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੀਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲ ਹੈ ਪਰ ਡੋਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ: ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਂ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁਦ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।

19 JAN 1995

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ 'ਮੀਤਾ' ਤੇ 'ਡੋਲੀ' ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਹਵਾਲੇ

ਭਵਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ

ਸਹਾਰਨਪੁਰ, 19 ਜਨਵਰੀ–ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾਨਗਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਥਾਣਾ ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੋਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜੋ ਕਿ 'ਟਾਡਾ' ਤਹਿਤ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ (ਜਗਾਧਰੀ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਸਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਐਨ. ਸਿੰਗਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 27 ਫਰਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਧਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ 'ਹਾਰਜ਼ੀ ਖਾਲਸਾ ਫਰਨੀਚਰਜ਼' ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਾੜਕੂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੀਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਨਪਾਲ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਟਾ ਮੋਬਾਇਲ

ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ 11 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ–ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ

ਗੱਡੀ (ਨੰਬਰ ਐਚ. ਆਰ-02 ਏ/7431) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿਚ 1 ਮਾਰਚ 1993 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਡੋਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੀਲੀਆ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ ਨੇ ਡੋਲੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਸ: ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਕੁਤੁਬਸ਼ੇਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਕੁਤੁਬਸ਼ੇਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਕੁਤੁਬਸ਼ੇਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ 1993 ਤੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੋਲੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸ: ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਵੀ 4 ਮਾਰਚ 93 ਨੂੰ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਛਪਦੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਾਰਚ 1993 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਤਾ ਅਤੇ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਯਮੁਨਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪੁਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਧਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਰਦ ਜੁਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ. ਪੀ. ਸ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ, ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਮੋਤੀ ਬੀੜ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਉਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਹੱਥਕੜੀ ਸਮੇਤ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. (ਨੰਬਰ-14/17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993) ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ, 300, 224, 34 ਅਤੇ 25/54 ਅਤੇ 59 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ

(ਬਾਕੀ ਸਫਾ 8 ਕਾਲਮ 3)

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ : ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ.

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ., ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਅਲੀ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਵੇਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 'ਗੁੰਮ' ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਜੀਬ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਔਖੀ ਹੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ 'ਲਾਪਤਾ' ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਥਿਤ 'ਗੁੰਮ ਹੋਏ' ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਬਾਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪੀਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕੱਲੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਨਾਹ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ' ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਗਲਤ ਦਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ 1990-91 ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾੜਕੂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਨੇ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਹਿੜਾ

ਮੁੰਡੇ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ. ਔਲਖ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ - ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਛਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂ ਟੋਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਘੁਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 25000 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ

PUNJABI TRIBUNE 19 JAN 1995

19 JAN 1995

Tribune
17 Jan 1995

Security forces "bulldozed" rights

Tribune News Service

AMRITSAR, Jan 16 – The human rights wing of the Akali Dal (Amritsar) has alleged that the security forces had bulldozed human rights and human values essential for the maintenance of a civil society during an operation to capture Gurbachan Singh Manochahal, a listed militant in February 1993.

This allegation has been levelled in its report which was released to the Press here today. The six-page report in Gurmukhi has been prepared by Mr Jaspal Singh Dhillon and Mr Jaswant Singh Khalra, president and secretary, respectively, of the wing. According to the report, Manochahal, a listed militant, was killed in an encounter with the security forces on February 28, 1993, his death did not fall under the ambit of human rights, but the ways employed to eliminate him by the security forces and the "inhuman" treatment meter out to his family members, and relatives did pose a serious threat to the human rights consciousness. On August 2, 1992, Nirvair Singh, a brother of Manochahal was taken in custody by the CIA staff, Tarn Taran. After a week he returned to Naushehra Pannuan police post and was unable to walk. On August 10, Atma Singh, father of the militant was taken in custody along with his mother, Gurmej Kaur, sister-in-law, Baljit Kaur and Gurmit Kaur another sister-in-law from Brahmpura village. They were taken to Vairowal police station. Nirvair Singh was killed in a "fake" encounter on September 9, while the body of Atma Singh was thrown in the Beas.

The report said 43 relatives from 15 villages were picked up by the Tarn Taran police, which included 16 women and 27 men. The women folk were kept together at Vairowal, Khadoor Sahib and Sarhali police stations, "brutally tortured" and were forced to perform "ardas" for Manochahal. All the men were kept at various police stations. No one was officially arrested but were kept in illegal custody for more than 9 months. Out of these 43, Mr Kewal Singh Sangatpura an ex-serviceman, died of "excessive torture" Surjit Singh Malmohri was shown as killed in an encounter near Jagraon. Nirmal Singh, Gulzar Singh of Pandori Gola village were also eliminated. Five out of 43 picked up by the police never returned to their respective homes.

After the elimination of Manochahal, the report says his brother Balwinder Singh, was picked up from Nakodar on March 16 and was killed in an "encounter" during the intervening night of March 29 and 30, 1993 near Kaura Wadhana village under Sarhali police station, Manochahal's mother Gurmej Kaur was picked up by the DSP, Mr Gurmit Singh himself, and was also killed.

In a communication to the chairman of the National Human Rights Commission Justice Ranganath Misra, the human rights leaders demanded an enquiry into the elimination of 14 persons to capture one militant.

17 JAN 1995

ਇਕ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ...

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) -ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 1993 ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਾਮੀਂ ਖਾੜਕੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ- ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਕਿ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਮਾਤ ਪੈ ਗਏ।

ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ 6 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਇਕ ਨਾਮੀਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਕੰਬ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰਇਨਸਾਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੇ ਇਕ ਭਰਾ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਕ ਹਫਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰੀ ਸੀ। ਦਸ ਅਗਸਤ [illegible] ਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਤੇ ਇਕ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੈਰੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ 'ਝੂਠੇ' ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੇ 43 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 16 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 27 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੋਵਾਲ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜਬਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਮੋਹਰ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਨੇੜੇ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਲਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ 43 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤ ਸਕੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 29 ਤੇ 30 ਮਾਰਚ 1993 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੌੜਾ ਵਧਾਣਾ ਨੇੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਜੀਤ

16-Jan-1995.

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ–ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜਨ ਲੱਖਣਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਦਨਸੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਪੁੱਤਾਂ-ਧੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਅਣ-ਪਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ।

ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ਤੱਕ ਹੀ 412 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 112 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੇਤ) ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਚ 400 ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਝੰਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਤ ਆਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ

(ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 6 ਕਾਲਮ 3)

THE TRIBUNE

16 JAN 1995

Security forces "bulldozed" rights

Tribune News Service

AMRITSAR, Jan 16 – The human rights wing of the Akali Dal (Amritsar) has alleged that the security forces had bulldozed human rights and human values essential for the maintenance of a civil society during an operation to capture Gurbachan Singh Manochahal, a listed militant in February 1993.

This allegation has been levelled in its report which was released to the *Press here* today. The six-page report in Gurmukhi has been prepared by Mr Jaspal Singh Dhillon and Mr Jaswant Singh Khalra, president and secretary, respectively, of the wing. According to the report, Manochahal, a listed militant, was killed in an encounter with the security forces on February 28, 1993, his death did not fall under the ambit of human rights, but the ways em[illegible]yed to eliminate him by the security forces and the "inhuman" treat[illegible]t meter out to his family members, and relatives did pose a serious threat to the human rights consciousness. On August 2, 1992, Nirvair Singh, a brother of Manochahal was taken in custody by the CIA staff, Tarn Taran. After a week he returned to Naushehra Pannuan police post and was unable to walk. On August 10, Atma Singh, father of the militant was taken in custody along with his mother, Gurmej Kaur, sister-in-law, Baljit Kaur and Gurmit Kaur another sister-in-law from Brahmpura village. They were taken to Vairowal police station. Nirvair Singh was killed in a "fake" encounter on September 9, while the body of Atma Singh was thrown in the Beas.

The report said 43 relatives from 15 villages were picked up by the Tarn Taran police, which included 16 women and 27 men. The women folk were kept together at Vairowal, Khadoor Sahib and Sarhali police stations, "brutally tortured" and were forced to perform "ardas" for Manochahal. All the men were kept at various police stations. No one was officially arrested but were kept in illegal custody for more than 9 months. Out of these 43 Mr Kewal Singh Sangatpura an ex-serviceman, [illegible]

Singh Malmohri was shown as killed in an encounter near Jagraon. Nirmal Singh, Gulzar Singh of Pandori Gola village were also eliminated. Five out of 13 picked up by the police never returned to their respective homes.

After the elimination of Manochahal, the report says his brother B[illegible]xander Singh, was picked up from Nakodar on March 16 and was killed in an "encounter" during the intervening night of March 29 and 30, 1993 near Kaura Wadhana village under *Sarhali police station*. Manochahal's mother Gurmej Kaur was picked up by the DSP, Mr Gurmit Singh himself, and was also killed.

In a communication to the chairman of the National Human Rights Commission Justice Ranganath Misra, the human rights leaders demanded an enquiry into the elimination of 14 persons to capture one militant.

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥

Ph. (0172) 540244 P.P.

HUMAN RIGHTS WING (S.A.D)

ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਿੰਗ (ਸ਼੍ਰੋ: ਅ. ਦਲ)

HEAD OFFICE : Kothi No. 30 , Sec. 5 Chandigarh-160005 (INDIA)

Dated 23.2.95

[illegible]

12 DEC 1995

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ (ਭਾਸ਼ਾ)—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10-15 ਕੇਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ।

ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰੇ।

ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

20/July 1996

20 JULY 1996

ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤ ਬਾਹਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ

ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ. 19 ਜੁਲਾਈ—ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸ: ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਚਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ: ਘਰਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ: ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਝੂਠਾ ਕਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ: ਘਰਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਝਬਾਲ ਥਾਣਾ ਵਿਖੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ: ਘਰਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

● ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੂਰੀਆ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਭਾਸ਼ਿਵ ਰਾਓ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕੇ।

Khalra case: CBI report likely on July 22

THE TRIBUNE
SATURDAY
20 JULY, 1996

AMRITSAR, July 19 (UNI) – The Central Bureau of Investigation (CBI) has completed its preliminary investigations in the Jaswant Singh Khalra disappearance case and the inquiry report is likely to be submitted to the Supreme Court on July 22.

The apex court had ordered an inquiry in November last year into the "mysterious disappearance" of Mr Khalra following the filing of a public interest litigation case by Mrs Paramjit Kaur, wife of Mr Khalra, an Akali Dal (Badal) human rights activist who has been missing since September 5 last year.

The inquiry was completed on July 15 and during the course of the investigations, a number of Punjab police officials were questioned by CBI sleuths. Mrs Khalra in her cpmplaint to the Punjab Government had alleged that the Punjab police was responsible for the disappearance of her husband as he had collected vital information pertaining to fake encounters and cremation of a large number of unidentified of bodies boys who were allegedly killed by cops in stage-managed encounters.

During the course of the CBI investigations, human rights activists belonging to the Khalra action committee had alleged that Mr Ajit Singh Sandhu, a former SSP of Tarn Taran police district, had been responsible for the disappearance of Mr Khalra.

INDIAN EXPRESS

20 JULY 1996

Khalra case: CBI report on July 22

AMRITSAR, July 19: The Central Bureau of Investigation (CBI) has completed its preliminary investigations into the Jaswant Simgh Khalra disappearance case and the enquiry report is likely to be submitted to the Supreme Court on July 22. The apex court had ordered an enquiry in November last into the "mysterious disappearance" of Khalra following the filing of a public interest litigation (PIL) case by Paramjit Kaur, wife of Khalra, an Akali Dal (Badal) human rights activist, who has been missing since Sept 5 last year.

The enquiry was completed on July 15 and during the course of the investigations, a number of Punjab Police officials were questioned by CBI sleuths. Khalra's wife, in her complaint to the Punjab government had alleged that the Punjab Police was responsible for the disappeaance of her husband as he had collected vital information pertaining to fake encounters and cremation of a large number of unidentified bodies of young boys who were killed by the cops in stage-managed encounters on grounds that they were militants.

During the course of the CBI investigations, human rights activists belonging to the Khalra Action Committee had alleged that Ajit Singh Sandhu, a former senior superintendent of police of Tarn Taran police district, had been responsible for the disappearance of Khalra.

The chairman of the Khalra Action Committee Surinder Singh Gharyala had on a number of occasions, alleged that the state government had not provided any form of assistance to the investigation team. In April, two Punjab Police constables posted in Tarn Taran police district had in a complaint to senior officials alleged that they had been harassed and tortured by the CBI team investigating the Khalra case.

Paramjit Kaur, wife of the missing human rights leader, had already indicated that she proposes to sit on a dharna outside Parliament on April 25 to lodge her protest against the negative attitude of the government towards the enquiry. After the submission of the report to the Supreme Court. The CBI is likely to ask the court's permission to arrest those named in the enquiry, so as to enable to proceed further with the investigations.

Eyewitness fears for life

EXPRESS NEWS SERVICE

AMRITSAR, July 19: Kikkar Singh, an eyewitness in the Khalra abduction case, today alleged that some musclemen of former Tarn Taran SSP Ajit Singh Sandhu had made an attempt on his life.

Surinder Kumar Gharala, chairman of the Khalra action committee, sought immediate action against the accused. He said that Kikkar Singh had confessed that Jaswant Singh Khalra had been kept under illegal police custody along with him.

15 JULY 1996

ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ 25 ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) –ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਏ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ।

Khalra panel to stage dharna

AMRITSAR, July 15: All members of Khalra Action Committee will accompany Paramjit Kaur Khalra, wife of Jaswant Singh Khalra of Human Rights wing (SAD), allegedly kidnapped by the police since June 1994, to stage dharna in front of Parliament on July 25, as stated by Justice Ajit Singh Bains, chairman Punjab Human Right wing, here today.

He said that CBI inquiry should be conducted to know the whereabouts of 25,000 innocent Sikh youths killed by the police.

ਅਜੀਤ

15 July - 1996

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ

ਜਲੰਧਰ, 14 ਸਤੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵੱਜ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਮਾਰੂਤੀ ਵੈਨ ਅਤੇ ਜਿਪਸੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਸਿਵਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਇਕ ਮਾਰੂਤੀ ਵੈਨ ਨੰਬਰ ਡੀ. ਐਨ. ਵੀ. 5969 ਅਤੇ ਇਕ ਜਿਪਸੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧੂਹ ਕੇ ਵੈਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ

(ਬਾਕੀ ਸਫਾ 8 ਕਾਲਮ 6)

ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ (ਸਫਾ 1 ਦੀ ਬਾਕੀ)

ਅਤੇ ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਏਨੇ ਤੱਥ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ੰਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁਚਾ ਦੇਵੇ।

ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫੂਕੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਏ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੇ 'ਨਰਮ' ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸ: ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਥੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਸੰਧੂ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ: ਸੰਧੂ 1991 ਤੋਂ 93 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 1992 ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 'ਗੁੰਮ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕੋ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਅਗਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਾਜ ਸਭਨਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਫਗਵਾੜਾ-(ਪ.ਪ.) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਰਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

16 MAY 1996

पंजाब में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यालय खोलने की मांग

अमृतसर, 16 मई/जगतार

शिरोमणि अकाली दल के मानव अधिकार विंग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से आयोग का एक कार्यालय पंजाब में खोलने की मांग की है।

यह मांग आयोग को दिए एक ज्ञापन में की गई है। यह ज्ञापन आयोग के चेयरमैन न्यायाधीश [illegible] प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिया गया। 51 सदस्यीय इस प्रतिनिधि मंडल ने श्री चल्लैया को दिए ज्ञापन में बताया है कि किस तरह राज्य की युवा पीढ़ी को मौत के मुंह में धकेला गया।

विंग के चेयरमैन एडवोकेट सुरिन्द्र सिंह धरियाला ने इस ज्ञापन द्वारा श्री चल्लैया को बताया है कि उन्होंने इस सार्वजनिक नरसंहार की घटना के विषय में विश्व स्तर पर आवाज बुलंद की है लेकिन केन्द्र सरकार और विरोधी दलों के व्यवहार ने पंजाबियों व विशेष कर सिखों को निराशा ही दी है। उन्होंने बताया कि विंग के महासचिव स. जसवंत सिंह खालड़ा ने अगर इस नरसंहार की जानकारी लोगों को देनी चाही तो पुलिस द्वारा उन्हें ही उठा लिया गया और गायब कर दिया गया।

स. धरियाला ने बताया कि उक्त विषय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स. खालड़ा की जांच के लिए यह दायित्व सी.बी.आई. को सौंपा गया था लेकिन राजनीतिक दबाव के कार [illegible] का रफ्तार बहुत सुस्त है। उन्होंने बताया कि सी.बी.आई. 2000 लावारिस लाशों को शमशान घाटों पर जलाने की बात मान चुकी है लेकिन विंग की रिपोर्ट के अनुसार 25 हज़ार युवाओं को लावारिस बता कर विभिन्न शमशान घाटों में जला दिया गया जिसमें 950 के करीब महिलाएं, 1200 के करीब पुलिस कर्मचारी, 320 के करीब वृद्ध और कई मासूम बच्चे भी शामिल थे।

ज्ञापन में बताया गया है कि 15 दिसम्बर 1992 को तरनतारन के स्टेन फोर्ड स्कूल की प्रिंसीपल बीबी सुरिन्द्र कौर का अपहरण कर उसे सी.आई.ए. स्टाफ तरनतारन लाया गया। जहां उस पर अमानवीय यातनाओं का दौर चला। कई पुलिस थानों में उसे रखने के बाद उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध कर उसे हरीके दरिया में बहा दिया गया। झब्बाल की महिला कंस कौर अपने पति व पुत्र की हत्या के बाद सड़कों पर पागलों की तरह घूमती नजर आती है। कस्बा पंजवाड़ की बीबी जोगिन्द्र कौर [illegible] द्वारा 31 दिसम्बर, 1992 को सुबह के उजाले में सारे गांववासियों के समक्ष उठाया गया था लेकिन वह अभी तक घर वापिस नहीं पहुंचे हैं। इसी तरह चोटी के एक खाड़कू गुरबचन सिंह मनोचाहल को मारने की खातिर पुलिस ने उसके परिवार के करीब दो दर्जन व्यक्ति लापता कर दिये।

सब्बानपुर की बीबी सविंदर कौर, भजन कौर, घसीटपुर निवासी महिला दीपो, शिंदो (निवासी भरड़), कश्मीर कौर निवासी थांदे और भूपिन्द्र कौर की मौत के किस्से भी दिल दहला देने वाले हैं। उन्होंने आयोग से न्याय दिलवाने की अपील की है।

ਅਜੀਤ

4 May - 1996.

ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰਾ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ-ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸੇ ਅਯਾਲਾਲੇਸੋ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਫਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਥਾਨਕ ਮਾਊਂਟਵਿਊ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਫਦਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਲੈਸੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲੱਖਨਪਾਲ ਇਕੋ ਵਫਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਰੰਜਨ ਲੱਖਨਪਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਲੱਖਨਪਾਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਲੈਸੋ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਈ।

ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਪ੍ਰੋ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਫਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਦੇ ਉਸ ਲੈਟਰ ਪੈਡ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਖੰਡਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਸ: ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਟਾਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 1992 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਰਅਮਨ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ 12 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਫਦ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ੧ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੀਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਲੈਸੋ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਲੈਸੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮੇਗਾ ਸਾਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ, ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦਾਦੂਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਵਾਸੀ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਮ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੋ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

27 APRIL 1996

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ

<u>ਮੇਤਾ ਸਿੰਘ</u>

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ. ਜਸਬੀਰ ਸ਼ਿੰਘ ਪੱਧਰੀ. ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮੀਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 950 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀਬੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤ ਸ੍. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ. ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ (ਵਾਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸ੍. ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

20 April 1996

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ :- (ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰ. ਘਰਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

ਸ੍ਰ. ਘਰਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰੋਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰ. ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਵਫਦ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

17 April 1996.

ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ✓

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ-(ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਅਗ਼ਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 17 ਮਈ, 1993 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਮ. ਅਹਿਮਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐਸ. ਪਰਿਪੂਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੈਂਕਟਾਸੁਆਮੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ-ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਐਸ. ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਮ ਦਿਆਲ (ਜੋ ਹੁਣ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ), ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੋਂ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

14 April - 1996.

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਛੇਤੀ : ਮਿਸ਼ਰਾ

ਕਟਕ, 14 ਅਪਰੈਲ (ਯੂ. ਐਨ. ਆਈ.) -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਇਥੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 17 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ 7800 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 2500 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਔਸਤਨ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਤੋਂ 50-50 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਚਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਅੰਤ ਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

1 april 1996

1APRIL 1996

੧ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥
ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ ॥

...kh Students Federation
...O. Sri Amritsar Sahib.
...r. 87-Rani Ka Bagh, Amritsar.
...one : 0183-64122

ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ-ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਫੋਨ : ੦੧੮੩-੬੪੧੨੨

ਮਿਤੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1996

[illegible]

[illegible]

1 april 1996

1 APRIL 1996

੧ੳ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥
ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ ॥

Sikh Students Federation
H.O. Sri Amritsar Sahib.
Ar. 87-Rani Ka Bagh, Amritsar.
Phone : 0183-64122

ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ-ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਫੋਨ : ੦੧੮੩-੬੪੧੨੨

ਮਿਤੀ 2 [illegible] 1996

[illegible]

[illegible]

ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਜਨੇਵਾ 26 ਮਾਰਚ (ਅ.ਬ.)- ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਯੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜਾਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਵਿਸ ਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਬੈਨਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਜ-ਧਜ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਬੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਹਿਯੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚਿਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫਦਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।ਇਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਹਰੀਕ-ਇ-ਹੁਰੀਅਤ--ਇ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਖਾਲਸਾ ਹਿਯੂਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਯੂ.ਕੇ.ਦੀ ਆਈ.ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਫ. ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਹ-ਇ-ਰਵਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰ, ਖਾਲਸਾ ਹਿਯੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ ਬੀਬੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਫ. ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਖਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਕੇ.ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਨ ਸਿੰਘ (ਚਾਰੇ ਹਾਈਜੈਕਰ) ਬਾਬਾ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ (ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ, ਸ. ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਭਾਈ ਅਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਿਫਊਜੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੇ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਿਯੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੁੜਾਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ "1947 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਕਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿਉ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇੰਨਸ਼ਾਅਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਨ,ਮਨ,ਧਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਫਦ ਭੇਜ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਵੇ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ "ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਹਲੂਣੇ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

"ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੁਆਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕੀਏ।" ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ (ਹਾਈਜੈਕਰ 1984) ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, "ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨ। ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।" ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ (ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਸ. ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।"

ਅੱਜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼

27 MARCH 1996

22 MARCH 1996

ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਯੂ. ਐਨ. ਆਈ.) - ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 1996

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ. ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਲੱਡੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਆਰਾ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ।

ਖੰਨਾ, (ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) - ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਜ਼ੁਲਮਗੜ੍ਹ, ਸ੍ਰੀ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਅਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਰੋਪੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਰੋਪੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਨੇ ਰੋਪੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦਲ ਦੇ ਪ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਅਜੀਤ 22 MARCH 1996

ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਨਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਮਾਰਚ-(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਗਪਗ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ (ਝਬਾਲ) ਵਿਖੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ: ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮੀਸ਼ਾਹ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਥੇ ਸੱਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ-ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਗਈ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।

MON 5, FEB 19996

ਅਜੀਤ

ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਫਰਵਰੀ-(ਹਰਕੰਵਲ ਕੋਰਪਾਲ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਭਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਨੋਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ।

100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਸਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਥੋਂ ਘਰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਉਠੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ:) ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ, ਪੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਤਫਤੀਸ਼) ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਲਾਸੌਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀ: ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੈਮੇਂਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮੀਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇ-ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਕਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਅੱਜ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਵਿਧੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਆਮੂਮਨ 'ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਖਾਹ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਦੁਖਿਆਰਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇਹ ਕੈਸੀ ਵੇਦਨਾ-ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਕਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ 'ਸਵਿੱਤਰੀ ਦੀ ਮਿੱਥ' ਸੱਜਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ:) ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਜਿਸ ਨੇ ਬੋਸਨੀਆ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਲਈ ਵੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ।

PUNJABI TRIBUNE

ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਤੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਫਰਵਰੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) - ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੰਗ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ-ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮੀਸ਼ਾਹ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰੋਪੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ।

1 FEBRUARY 1996.

~~31 JANUARY 1996.~~

ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ • ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਯੂ. ਐਨ. ਆਈ.) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਲੱਭਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਭ ਪਾਸਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਰਹਿਹਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ ਕਰੇਗੀ।

'ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ' ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਥੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ [illegible] ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਕਮ [illegible] ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਦਲਿਤ ਵੀਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜੂਝੀਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ 8, ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਵਿਚੋਂ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਲਗਪਗ 9-10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਧਾਕੜ ਡਰਾਮਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੰਮੀ . ਚੌੜੀ ਖੋਜ, ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਐਮ. ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 31 [illegible] ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਕ ਬਜ਼ਿਊ ਤਿਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ [illegible] ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਮਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

'ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਵਲੋਂ ਖਰੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ 'ਲੀਕ' ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁੱਝੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਿੰਟਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਫੋਰਡ ਤੇ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਸਕਾਊਕਰਾਫਟ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਮੇਰਿਲ ਵੇ, ਮਨਪੀਕ, ਮੋਰਟਨ ਅਬਰਾਮੋਵਿਟਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Wife seeks God's help in Khalra case

EXPRESS NEWS SERVICE

AMRITSAR, Jan 31: Mrs Paramjit Kaur, wife of human rights activist, Mr Jaswant Singh Khalra, after failing to get justice from the law of the land, has now "left her fate" to the Almighty.

She told newsmen here, today, that she would start 'dawn to dusk' recitation of Gurbani at Akal Takht, from February 4, till she gets back her husband, from the alleged il- [illegible]

She said that she would also [illegible] ation of Sikh youth in fake encounters.

1 FEB 1996

Khalra's wife leaves it to God

From Our Correspondent

AMRITSAR, Jan 31 – Mrs Paramjit Kaur Khalra wife of the human rights activist Mr Jaswant Singh Khalra, today issued an impassioned appeal through the newspapers and mediapersons, describing the events leading to the alleged kidnapping of her husband engineered by the SSP Tarn Taran, Mr Ajit Singh Sandhu last year.

Narrating the events relating to the kidnapping of her husband Mrs Khalra said she had along with a few bystanders seen her husband being forcibly taken in a vehicle outside her residence in the Kabir Park area.

She felt that Mr Khalra was picked up as he had exposed the Punjab police for its alleged involvement in cremating thousands of bodies of unidentified youths in various crematoria in Amritsar district. She said that her husband had prepared a list of persons killed by the police in fake encounters. While Mr Khalra was preparing the list he was threatened with dire consequences she added.

She lamenled that despite the intervention of the Supreme Court. Mr Khalra still remained untraced, so much so that even a C.B.I. inquiry which was ordered by the apex court had not been able to establish his whereabouts.

Left with no other option, she had decided to seek the blessings of the almighty in helping her find her husband. From February 4 she would begin the recitation of 'Gurbani' at Akal Takht, her statement said.

Everyday from morning till evening she would recite prayers from Guru Granth Sahib "As my pleas at all quarters have failed I have decided to take the help of God" the statement said.

Mrs Khalra said even persistent appeals by human rights organisations in India and abroad had failed to break the silence of the state government on this issue. She appealed to the Sikh sangat (community) to help trace her husband. "In the absence of my husband and in the presence of my two minor childern I have resolved to appeal before the Sikh "sangat" so as to demand an answer from the government, the statement added.

Mrs Khalra said she would complete the task initiated by her husband so as to expose the guilty police officials who indulged in eliminating Sikhs in fake encounters.

खालड़ा की पत्नी द्वारा मानवाधिकार संस्थाओं से सहयोग की अपील

चंडीगढ़, 31 जनवरी (वि.प्र.) : अकाली दल के मानवाधिकार प्रकोष्ठ के लापता महासचिव स. जसवंत सिंह खालड़ा की पत्नी श्रीमती परमजीत कौर खालड़ा ने देश-विदेश की मानवाधिकार से सम्बन्धित समाज-सेवी तथा धार्मिक संस्थाओं से अपील की है कि वह स. खालड़ा की सही-सलामत वापिसी के लिए उनसे (श्रीमती खालड़ा) सहयोग करने की अपील की है।

श्रीमती खालड़ा ने लिखित घोषणा की है कि वह इसी मकसद को लेकर 4 फरवरी से श्री अंकाल तख़्त की हजूरी में प्रतिदिन दिन-रात बैठकर जाप करेंगी।

आज यहां खालड़ा एक्शन कमेटी के संयोजक भाई सुरिन्द्र सिंह घरियाला द्वारा श्रीमती परमजीत कौर खालड़ा की अपील जारी की गई। इसमें उन्होंने कहा है कि लम्बी खोज-पड़ताल, पूछताछ के बाद प्राप्त हुए चिन्हों से यह बात सिद्ध हो गई है कि यह कार्रवाई उच्च राजनीतिक नेताओं तथा सरकारी अधिकारियों के आदेशों के अधीन तरनतारण में तत्कालीन एस.एस.पी. की हिदायत पर की गई थी।

लिखित घोषणा में श्रीमती खालड़ा ने कहा है कि वह 4 फरवरी को प्रातः 10 बजे अरदास करने के पश्चात् कार्रवाई आरम्भ करेंगी तथा नित्यप्रति सुबह से शाम तक गुरु रामदास तथा गुरु हरगोबिंद साहिब के चरणों में गुरबाणी का जाप करेंगी।

INDIAN EXPRESS.

26 JAN - 1996

Khalra case: President submitted memo

EXPRESS NEWS SERVICE

AMRITSAR, Jan 25: A senior human rights leader of Shriomani Akali Dal, Mr Balwinder Singh Chhabal, here said today that panches and sarpanches of various villages had started sending memoranda to the President for safe release of senior human right's leader, Mr Jaswant Singh Khalra.

In a Press release here today, he said sarpanches and panches of villages, namely Desh Singh (sarpanch), Kulwant Singh (panch), Karnail Singh (panch), Baksish Singh (panch), Karm Singh (panch), Pooniya's Skatar Singh (sarpanch), Balinder Singh (panch), Hari Singh (panch), Karamjit Kaur (panch), Palwinder Singh (sarpanch), Major Singh (panch), Minder Kaur (panch), Major Singh (panch), Veer Singh (panch), Surjit Singh (panch), and Boor Singh (panch), have already sent memoranda.

They all demanded immediate release of Mr Jaswant Singh Khalra who was abducted by Tarn Taran police on September 6 from his residence. Mr Chhabal urged sarpanches and panches to send memoranda to the President for the safe release of Mr Khalra. He alleged that the abduction of Mr Khalra was a heinous terrorist crime of government agencies.

A committee consisting of wing leaders met journalist Kuldeep Nayar who gave assurance that a committee consisting of judges and journalists would be formed who would investigate the Khalra abduction case.

He also demanded that Ammnesty International be allowed to visit Punjab so that it investigates independently the abduction of Mr Khalra.

FEB 5 JAN - 1996

Khalra's wife performs ardas

EXPRESS NEWS SERVICE

AMRITSAR, Feb 4: Mr Surinder Singh Ghariala, convenor of Khalra case action committee, said here today that Mrs Pramjit Kaur, wife of Mr Jaswant Khalra, general secretary of human rights wing of Shriomani Akali Dal, performed 'ardas' at Akal Takht at 10 a.m. today. The motive of ardas is to pray for safe release of Mr Khalra and prevention of repression on Sikh youth.

According to Mr Ghariala, about 100 men and women attended the "ardas". The gurbani was commenced after ardas.

Bhai Mohkam Singh, spokesman of Damdami Taksal, Prof Manjit Singh, jathedar of Akal Takht, Justice Ajit Singh Bains, chairman of Punjab Human Rights Organisations, Mr Baljinder Singh Gandiwind of Sikh Students Federation, Balwinder Singh Chabhal ofhuman rights wing, Mr Kirpal Singh Randhawa, district president of the PHRO, joined the ardas.

Justice Bains seeks Khalra's release

Tribune News Service

AMRITSAR, Feb 4 – Mrs Paramjit Kaur, wife of Mr Jaswant Singh Khalra, general secretary, Human Rights wing of the Shiromani Akali Dal, who was allegedly kidnapped by the Tarn Taran police from their residence here on September 6 last, started offering prayers in the Golden Temple here today to seek the Almighty's blessing for the "safe release" of her husband.

After paying obeisance at the sanctum sanctorum, she started the recitation of "path" near Akal Takht. About 80 others, including women, also sat with her.

The Chairman of the Punjab Human Rights Organisation, Justice Ajit Singh Bains, who also joined her, demanded the immediate release of Mr Khalra from the "illegal" custody of the Tarn Taran police. "The only sin of Mr Khalra was that he had exposed the cremation of 25,000 unclaimed bodies of Sikh youth in Amritsar revenue district".

He demanded that a commission should be set up to enquire into the killings in "fake" encounters

31 JAN 1996.

PHRO flays Governor for praising Gill

EXPRESS NEWS SERVICE

AMRITSAR, Jan 30: The Punjab Human Rights Organisation (PHRO) today reacted sharply to the reported remarks of the Punjab Governor, Mr K.N. Chhibber, on human rights abuses during a function organised at Jalandhar to honour the former DGP Mr K.P.S. Gill.

Mr Kirpal Singh Randhawa, president of Amritsar unit of PHRO, said in a statement that it was inappropriate for the Governor to eulogise Mr Gill at the cost of human right values.

According to press reports, the Governor had said that Mr Gill had fought against the propaganda war of Pakistan which was using human rights as a weapon.

Mr Randhawa said that the Governor had also made contemptible remarks against the judicial system. He said that such remarks would encourage the politics of bullet and added that judiciary's role was instrumental in safegaurding the democratic institutions in the country. He said that morale of security forces was not undermined by the court verdicts in human rights cases but by the corrupt political system. He said that hawala racket had unmasked the so called nationalist leaders of the country.

Mr Randhawa said that that the violation of human rights by the Punjab Police was now an established fact.

He said that Mr Chhibber had hurt the sentiments of hundreds of victims of police repression. He said that Mr Jaswant Singh Khalra, who was kidnapped by police in broad day light, was still untraceable. He demanded an apology from Mr Chhibber on this issue.

ਰੂਪਨ ਬਜਾਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸੰਗਠਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)

ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ

*** ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਨਕਲੀ-ਰੂਪਨ * ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਕਰਣ ਕੀਤਾ-ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ * ਗਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮ-ਜਾਮ ਤੇ ਟਕਰਾਏ**

ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰ.ਡੀ. ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਪਾ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੱਥ-ਪੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ।

ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਨ ਬਜਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਬਣਾਏਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਾਰਨ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ । ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ

(ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 6 'ਤੇ)

ਰੂਪਨ ਬਜਾਜ

2 JANUARY 1996

THE TRIBUNE
10 MAY 1996

CRPF ring around SPO

From Navjot Sandhu and TNS

BACHADE (Tarn Taran) May 9 — The eyewitness in the sensational Jaswant Singh Khalra abduction case, SPO Kuldip Singh has got 20 CRPF security guards who make a "tight security ring" around him.

The CRPF personnel from 86 Batallion are under the supervision of Sub-Inspector Ram Singh. When this correspondent visited the village last evening, Sub-Inspector Ram Singh was giving instructions to the jawans to keep a strict vigil on every person who comes to the village.

The CRPF guards have put up their tents on the outskirts of the village to keep a watch on every person who enters the village. He said the SPO shared meals with the guards to rule out the possibility of his being poisoned.

Mr Kuldip Singh said he was satisfied with the present security ring. "I am not scared now. Now Mr KPS Gill and others involved in the Khalra murder case will go to jail".

He alleged he was recruited as SPO because he had "sensational" information on high officials and was even issued an AK-47 rifle for which he was not eligible.

He alleged that at least a dozen AK-47 rifles could be recovered from relatives of officials. He said he had more information but would open the "Pandoras box" at the right time.

PATIALA: District Sessions Judge K.S. Garewal today fixed May

Khalra case

30 for framing of charges and consideration of the application of the CBI, urging that the eight accused in the Jaswant Singh Khalra disappearance case be taken into custody.

The Sessions Judge announced this after the special CBI prosecutor, Mr H. Qureshi, submitted an application claiming that as the case was committed to the Sessions Court, as per Section 209 the accused had to be taken into custody, subject to the provision of bail.

This issue of The Tribune consists of 28 pages, including an eight-page Sunday Reading pullout.

He argued that the accused had been released on bail only for offence triable by a Magistrate, that is Section 365 (Abduction), and not for offences under Sections 364 or 302, IPC.

Mr Balwant Singh Jandu, counsel for the accused, argued that the prosecution needed sanction of the Central Government before proceeding against them. He said it was necessary to take permission of the Union Government under Section 197, CrPC, if the complainant wanted to proceed against the accused under Section 364, IPC.

Meanwhile, Amnesty International has decided to send an observer to monitor the progress made in the case.

A communication in this regard has been sent to the Union Government by Ms Emma Blower, Chairperson, Asia Desk of Amnesty International.

The decision to send an observer has come after the witnesses in the case and lawyers arguing the case for Mrs Paramjit Kaur Khalra, wife of the missing activist, sent a representation to the Amnesty, alleging that their life was under threat.

THE TRIBUNE

20 DEC 1996

Jail incident 'made-up story'

Tribune News Service

PATIALA, Dec 19 – The human rights wing of the Shiromani Akali Dal headed by Mr Parkash Singh Badal in a statement issued here today has urged the Punjab Government to order a judicial inquiry into the Amritsar jail incident in which Mr Ajit Singh Sandhu, a former SSP of Tarn Taran, and Nishan Singh Kalanaur were involved.

Mr Surinder Singh Gharyala, chairman, and Mr Balwinder Singh Jhabahl, general secretary of the human rights wing of the SAD said here today the police story regarding attempt to murder Mr Ajit Singh Sandhu by Nishan Singh was a "made up" one and a part of a deep conspiracy.

Mr Surinder Singh and Mr Balwinder Singh, who had come here along with Mrs Paramjit Kaur, wife of Mr Jaswant Singh Khalra, who was allegedly kidnapped by a police party at Tarn Taran a few months ago and has not been traced yet, said following exchange of arguments between Mr Sandhu and Nishan Singh inside jail Mr Sandhu and other police official lodged in the jail along with him allegedly started beating up Nishan Singh mercilessly.

Condemning the alleged action of Mr Sandhu and other police officials in jail, human rights activists said that police officials lodged in jails were throwing all jail rules and regulations to winds and doing what they wanted.

As Mr Sandhu and other jailed officials were undertrials and accused in a number of cases, they were not entitled to any special treatment.

Criticising the statements made by a number of Congress leaders supporting Mr Sandhu, human rights activists asked why those leaders were silent regarding kidnapping of Jaswant Singh Khalra allegedly by the police while the CBI following a probe had indicted several police officials in this case.

Mrs Paramjit Kaur alleged that certain important witnesses in the Khalra case were being threatened by the police and efforts were being made to make them to withdraw their statements by using various methods. A police party was permanently stationing in the fields of Mr Kikar Singh, who was one of the main witnesses in Khalra case. The police was not allowing Mr Kikar Singh to plough his fields.

Jail Supdt shifted

Tribune News Service

AMRITSAR, Dec 19 – Mr Amarjit Singh, superintendent of the local Central Jail, in Ludhiana in the same capacity, it is learnt. The DGP (Prisons) today ordered his transfer.

Mr Amarjit Singh was in news following the recent incident in which Mr Ajit Singh Sandhu, a former SSP of Tarn Taran, was allegedly assaulted by Nishan Singh, a hardcore militant, on Tuesday.

Mr Sandhu had alleged that Nishan Singh attacked him with the intention of killing him in connivance with Mr Amarjit Singh whose son and brother were called by the Ropar police for interrogation for their alleged links with militants in 1993. Mr Amarjit Singh, however, refuted the allegations.

"Treat Sandhu like other prisoners"

Tribune News Service

CHANDIGARH, Dec 19 – Mr Justice Ajit Singh Bains, Chairman, Human Rights Organisation, and Mr Inderjit Singh Jaijee, Chairman, Movement Against State Oppression, today called upon the authorities concerned to "let the law take its own course" in the case of the scuffle between Mr Ajit Singh Sandhu, a former SSP of Tarn Taran, and another prisoner in a prison in Amritsar.

They said let Mr Ajit Singh Sandhu be a prisoner like any other prisoner but safe for facing the trial so that the "law can prevail".

The chiefs of the two organisations deplored the demand for conversion of a guest house or a forest bungalow for Mr Sandhu, now arrested for murdering Kuljit Singh, "a publicman". The only achievement of Mr Ajit Singh Sandhu, they said, was that "during indiscriminate killings he managed to kill some wanted men also".

ਅਜੀਤ
ਐਤਵਾਰ, 1 ਦਸੰਬਰ, 1996 (7)

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਧਰਨਾ 10 ਨੂੰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਨਵੰਬਰ-(ਵਿ. ਪ.) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਥਹੁ ਪਤਾ ਦੱਸਣ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ: ਘਰਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਸ: ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ: ਚੂਹੜ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਵਲਟੋਹਾ ਸਰਕਲ, ਸ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰਕਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲੂਵਾਲ ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਸਰਕਲ, ਸ: ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵੀਰਮ ਨੂੰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਸ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜੀਤ 15 NOV 1996

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ

ਤਰਨਤਾਰਨ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਮੇਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਉਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਸ ਦੇ ਅਗਵਾ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਵਿੰਗ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਖਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿ

ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਬਕਾ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਕੇ. ਗਰਗ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।

ਅਜੀਤ 19 Sept - 1996.

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅਜੀਤ ਫੋਟੋ : ਆਰ. ਐਨ. ਸਿੰਘ

ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ

ਜਲੰਧਰ, 18 ਸਤੰਬਰ-(ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਗਰਲਜ਼, ਮੇਹਰਚੰਦ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲੱਖਪੁਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਥੋਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 'ਖਾਲੜਾ' ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜਲੰਧਰ-(ਵਿ. ਪ੍ਰ.) ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-(ਵਿ. ਪ੍ਰ.) ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲਜਾਂ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।

ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

18 Aug 1996.

ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਸਮਾਗਮ 6 ਨੂੰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਅਗਸਤ (ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ)—ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਸ਼ੁਦਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਸ: ਘਰਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 984 ਵਿਅਕਤੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮੀਸ਼ਾਹ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂ ਨੰਗਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 9 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ: ਘਰਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 8 [illegible] ਪਾਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਕਬਰਪੁਰੇ ਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 30 ਨੂੰ

ਸੰਗਰੂਰ, 17 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਜੰਟ ਚਾਹਲ)—ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਖੁਰਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 10.00 ਵਜੇ ਮਾਲਵਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਅਗਰਵਾਲ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ [illegible] ਪੰਜਾਬ-ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪੁੱਜਣਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3[illegible] ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।

ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ

ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

4 Aug 1996.

ਸਖਤ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਜਲੰਧਰ, 3 ਅਗਸਤ-(ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਰੱਖੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇਤਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਹਰਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਈ।

ਲਾਵਾਰਸ ਦੱਸ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਇਹ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਯੂਥ ਦਲ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲਾ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਨੂਰਮਹਿਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਟਰਾਂ, ਮੈਟਾਡੋਰ ਅਤੇ ਜੀਪਾਂ ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਚੌਕ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦਮ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇਤਾ ਹਰਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ।

(ਬਾਕੀ ਸਫਾ 7 ਕਾਲਮ 4)

ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ: ਹਰਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਸ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੀਤ ਫੋਟੋ: ਆਰ. ਐਨ. ਸਿੰਘ

Ajit
4 Aug - 1996.

984 अज्ञात शवों को खुर्दबुर्द करने के मामले व स. खालड़ा के अपहरण व गुमशुदगी के विरुद्ध आयोजित रोष मार्च के दौरान फैडरेशन के कार्यकर्ता व नेता।

फैडरेशन के नेताओं ने पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों की निंदा की

जालन्धर, 3 अगस्त (वि.प्र.) : आल इंडिया सिख स्टूडैंटस फैडरेशन (बादल) द्वारा ज़िलाधीश के कार्यालय के बाहर दिए गए धरने के दौरान पुलिस द्वारा फैडरेशन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है।

आज यहां संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए फैडरेशन के कार्यकारी प्रधान स. करनैल सिंह पीर मुहम्मद, स. चेत सिंह दोलोनंगल ने कहा है कि पुलिस ने फैडरेशन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया गया है।

बाद में इन नेताओं सहित फैडरेशन के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जालन्धर के ज़िलाधीश श्री एम.पी. सिंह को केन्द्र सरकार के नाम एक मांग पत्र भेंट किया।

उन्होंने मांग की है कि पंजाब में पिछले समय के दौरान हुए कत्लेआम की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच कराई जाए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों के साथ ही लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों व सिंह सभाओं के चुनाव करवाने, पंजाब विधानसभा भंग करके पुनः विधानसभा चुनाव करवाने, जेलों में बंद नवयुवकों को बिना शर्त रिहा किए जाने की मांग की गई व यह भी मांग की गई कि पंजाब की शिक्षा नीति में परिवर्तन करके ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम बनाया जाए।

दूसरी ओर फैडरेशन के शहरी प्रधान श्री सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जिन कार्यकर्ताओं को प्रातः धरने के दौरान हिरासत में लिया था उनमें फैडरेशन के वरिष्ठ उपप्रधान स. हरशंकर सिंह राणा को अभी तक छोड़ा नहीं गया और कुछ पता नहीं चल रहा कि पुलिस उन्हें कहां ले गई है। उन्होंने श्री राणा का पता बताने की मांग की है।

जालंधर से का. सं. के अनुसार : आज आयोजित किया गया रोष मार्च असफल बनाने के लिए पुलिस द्वारा भरसक प्रयास किए गए। विभिन्न दिशाओं से आने वाले काफिलों को रास्तों में ही रोक लिया गया। जालंधर के गुरुद्वारा माडल टाऊन व सैंट्रल टाऊन के इर्द-गिर्द पुलिस ने सख्त घेराबंदी करके यहां किसी को भी एकत्र न होने दिया। पुलिस के सख्त प्रतिबंधों के बावजूद फैडरेशन नेता कम्पनी बाग से उपायुक्त कार्यालय तक रोष मार्च व रैली करने में सफल रहे।

स. नूरमहल व अन्य कुछ स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सभी प्रतिबंधों के बावजूद स्कूटरों, मैटाडोरों व जीपों में सवार होकर शहर में दाखिल होने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में फैडरेशन नेताओं हरशंकर सिंह राणा, स. कृपाल सिंह बोदल, स. दिलबाग सिंह, अमरजीत सिंह पठानकोट, खालड़ा एक्शन कमेटी के चेयरमैन स. सुखि सिंह, बलविंद्र सिंह झबाल, राजबीर सिंह भूरेगिल, मनजीत सिंह नौशहरा पत्रुआं परमजीत सिंह, हरमनदीप सिंह, जगदीश सिंह नूरमहल, गुरमननिंद्र सिंह ढिल्लों शामिल हैं।

स. रामा ने प्रातः पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार के गलत कार्यों के विरुद्ध 13 अगस्त को पंजाब के समूह विद्यार्थियों से हड़ताल करने का आह्वान किया गया है।

फैडरेशन नेता स. यादविंद्र सिंह चीमा ने बताया कि पुलिस ने विभिन्न स्थानों से करीब 100 फैडरेशन नेताओं को गिरफ्तार किया है।

4 Aug 1996

4.8.1996 दैनिक पंजाब केसरी, जालंधर (13)

अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के नेता व कार्यकर्ता जालंधर में रोष प्रदर्शन करते हुए। (छाया : कोहली)

पंजाब सरकार ने सिख छात्र संघ के रोष मार्च पर पाबंदी लगाई : कई संघ नेता गिरफ्तार

जालंधर, 3 अगस्त (धवन) : पंजाब में 1990 से 95 के बीच मारे गए 984 लोगों सम्बंधी सी.बी.आई. द्वारा तथ्य सामने लाए जाने के बावजूद केन्द्र की देवेगौड़ा सरकार द्वारा उनके नाम व पते बताने के लिए कोई कार्रवाई न किए जाने के विरुद्ध अखिल भारतीय सिख छात्र संघ (बादल) द्वारा आज जालंधर में निकाले जाने वाले राज्यस्तरीय रोष मार्च पर पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों पर पुलिस ने पाबंदी लगा दी तथा कई संघ नेताओं को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। सिख छात्र संघ के वरिष्ठ उपप्रधान हरशंकर सिंह राणा, जिला जालंधर (देहाती) के अध्यक्ष यादविन्द्र सिंह चीमा ने एक संवाददाता सम्मेलन में पंजाब सरकार द्वारा संघ के प्रदर्शन पर पाबंदी लगाने की कड़ी आलोचना करते हुए इसे मानवाधिकार का हनन करार दिया। उन्होंने कहा कि रोष मार्च सुबह 11 बजे सैंट्रल टाऊन गुरुद्वारे से अरदास के बाद शुरू होना था, परन्तु पुलिस ने सुबह से ही पूरे गुरुद्वारे की घेराबंदी कर दी थी तथा जो भी कार्यकर्त्ता वहां पहुंचा, उसे कह दिया गया कि धरना नहीं दिया जा रहा है।

संघ नेताओं ने बताया कि अमृतसर से संघ के अध्यक्ष अवतार सिंह बोपाराय व महासचिव मनजीत सिंह भोमा को ब्यास के निकट पुलिस ने रोक लिया तथा आगे नहीं बढ़ने दिया। जालंधर में संघ के उपप्रधान जोगिन्द्र सिंह जोगी व युवा अकाली नेता बलजीत सिंह नीलामहल को पुलिस सुबह ही अपनी हिरासत में लेकर चली गई। पंजाब के कुछ अन्य जिलों से भी संघ कार्यकर्त्ताओं को जालंधर पहुंचने नहीं दिया गया।

श्री हरशंकर सिंह राणा ने पंजाब सरकार द्वारा रोष प्रदर्शन पर पाबंदी लगाने के विरुद्ध 13 अगस्त को पंजाब के सभी शिक्षा संस्थानों में हड़ताल का आह्वान किया है।

दोपहर 12 बजे लगभग 200 संघ कार्यकर्त्ता कम्पनी बाग में इकट्ठे हो गए तथा उन्होंने 'देवेगौड़ा मुर्दाबाद' के जोरदार नारे लगाए। बाद में वह एक काफिले के रूप में जिलाधीश कार्यालय के बाहर पहुंचे, जहां पर पुलिस ने उन्हें जिलाधीश को ज्ञापन देने के लिए आगे नहीं जाने दिया। संघ नेताओं व कार्यकर्त्ताओं, जिनकी संख्या लगभग 25 से 30 थी, को तुरंत पुलिस हिरासत में ले लिया गया।

इससे पूर्व दिए गए धरने में यादविन्द्र सिंह चीमा, हरचरण सिंह मैंगी, मुनीष शर्मा, हरदीप सिंह गोल्डी, रजिन्द्र सिंह संदल, जसबीर सिंह वालिया भी शामिल हुए। इस अवसर पर धरने को सम्बोधित करते हुए पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुरजीत सिंह मिन्हास ने पंजाब सरकार द्वारा रोष मार्च पर पाबंदी लगाने तथा संघ नेताओं को जिलाधीश को ज्ञापन न देने की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि शीघ्र ही अब इस सरकार का पतन हो जाएगा। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए एस.पी. (आप्रेशन) खूबी राम, एस.पी. सिटी अरुण आरेन तथा थाना डिवीजन नंबर 4 के एस.एच.ओ. हरप्रीत सिंह स्वयं मौजूद थे। जिलाधीश कार्यालय के बाहर से हिरासत में लिए गए नेताओं में खालड़ा एक्शन कमेटी के सदस्य भी थे।

बाद में एस.पी. सिटी डा. अरुण आरेन ने पंजाब केसरी को बताया कि सिख छात्र संघ के रोष मार्च पर पाबंदी लगाने का निर्णय इसलिए लिया गया था, क्योंकि इसके विभिन्न गुटों में आतंरिक कलह मौजूद है। यदि रोष मार्च की अनुमति दे दी जाती, तो सड़कों पर हंगामा-मारपीट हो सकती थी, जिससे शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति के बिगड़ने की आशंका थी।

उन्होंने बताया कि जालंधर शहर में जिलाधीश ने धारा 144 भी लगाई हुई है, जिसके तहत एक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। यदि संघ को मार्च निकालना था, तो उन्हें इसकी पूर्व में जिलाधीश से अनुमति लेनी चाहिए थी।

रिहा : मालूम हुआ है कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए कुछ संघ नेताओं व कार्यकर्त्ताओं को बाद में पुलिस ने करतारपुर व आम दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर छोड़ दिया।

ਜਗ ਬਾਣੀ 4-Aug-1996.

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਤੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਹਰਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। (ਫੋਟੋ : ਕੋਹਲੀ)

ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਤਾ

ਜਲੰਧਰ, 3 ਅਗਸਤ (ਧਵਨ)– ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ 984 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਉਥੇ ਪੁਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਨੇੜੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲਾ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚੁਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁਧ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲਗਭਗ 200 ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਕੁਨ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਜੇ, ਜਿਥੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਤਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25-30 ਸੀ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੈਂਗੀ, ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦਲ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਖਣ ਲਈ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿਟੀ ਅਰੁਣ ਓਰਾਨ ਤੇ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ. 4 ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਤੇ ਕੁਟਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ।

Aug 4 - 1996.

Protest march against mass cremation

■ 100 AISSF members detained

EXPRESS NEWS SERVICE

JALANDHAR, Aug 3: Despite tight security arrangements and the attempts by the police to foil the state level demonstration, the All India Sikh Students Federation (Badal) and the Khalra Action Committee, today, successfully organised a protest march and staged a dharna outside the deputy commissioner's office. They were protesting against the inaction of the government in booking the police officers responsible for the mass cremation of 984 bodies and the illegal detention of human rights activist, Jaswant Singh Khalra.

About 100 federation members were detained for violating the prohibitory orders in force in the district.

The police had laid siege around the Central Town Gurdwara here early this morning and did not even allow devotees to cross the barricades and nakas laid at all the approach roads. But the federation workers converged at the Nehru Garden Park, from where they started their protest march. Veteran Akali leader Surjit Singh Minhas and Surinder Singh Ghariala, chairman, Khalra Action Committee, along with others were bundled into police trucks. Several, federation leaders were picked up from their residences early in the morning, while many others from different districts were detained at various places.

AISSF workers being bundled into a police truck at the DC's office in Jalandhar. Express photo by R.K.Kohli

Harshankar Singh Rana, senior vice-president, while condemning the police action said that the police had detained federation president, Avtar Singh Boparai at Beas, while he was on his way to Jalandhar. Vice-president, Joginder Singh Jogi, Baljit Singh Neela Mahl and several other members from Amritsar, Ludhiana and Gurdaspur districts were stopped by the police at various points in a bid to foil the march.

The federation leader demanded that the human rights activist Jaswant Singh Khalra and other Sikh detenues lodged in various jails be released immediately.

Meanwhile, the fissures in the federation came to the fore with a faction headed by Karnail Singh Duule Nangal alleging that the Boparai group had not consulted them on today's protest march. Chet Singh Daule Nangal, vice-president, while talking to the media persons termed the march as a failure and claimed that a six-member delegation headed by Pir Mohammed submitted a separate memorandum to the DC seeking early release of Khalra.

TRIBUNE
4. AUG 1996.

AISSF, Youth Akali Dal hold protest

Tribune News Service

JALANDHAR, Aug 3 – Members of the All-India Sikh Students Federation, affiliated with the Akali Dal (Badal), and Youth Akali Dal today outsmarted the police by succeeding in staging a dharna in front of the Deputy Commissioner's office here.

The call for dharna and march was given by the Federation to press the demand for publication of the list of persons who had been cremated as unclaimed by police during the height of terrorism.

Earlier, the police had arrested Mr Baljit Singh Neelamahal and Mr Tejinder Singh Joga from their residences in the city. It also raided the houses of a number of other activists of the Federation and Youth Akali Dal to arrest them but could not succeed as they had gone underground.

The police had been posted in strength near the gurdwara in Central Town from where the march was to begin. No one was allowed to go to the gurdwara.

Instead, volunteers of the Federation and Youth Akali Dal gathered in Nehru Gardens, marched to the Deputy Commissioner's office raising slogans against the Prime Minister and the Punjab Government. As the police did not allow them to enter the office complex, they sat in dharna on the road.

Among those who addressed them were Mr Surjit Singh Minhas, a former Speaker of the Punjab Vidhan Sabha, and Mr Harshanker Singh Rana, senior vice-president of AISSF.

Soon, the police arrived on the scene and picked up 20 activists of the federation. The rest dispersed.

Among those who participated in the dharna were members of the Khalra Action Committee.

Federation leaders said the police

Continued on page 5 col 2

AISSF, Youth Akali Dal hold protest

Continued from page 1 col 1

did not allow people to come to Jalandhar to participate in the protest march. Mr Avtar Singh Boparai and Dr Manjit Singh Bhoma, who were coming from Amritsar, were stopped at Beas. Severals others were stopped at Phillaur, Wadala railway crossing and Nakodar.

Later, addressing a press conference, Mr Rana condemned the police for preventing the party workers from coming to Jalandhar and for the "unannounced" ban on a peaceful protest march.

He called for strike in the educational institutions in Punjab on August 13 to protest against the police action.

UNI adds: Later, another group of Federation activists led by its vice-president Chet Singh Dullonangal submitted a memorandum for the Prime Minister to the Deputy Commssioner, listing the demand. It, however, also sought release of Mr Khalra, who was allegedly picked up by police, and a three-member inquiry commission of Supreme Court Judges to probe all the killings in Punjab during the decade-long militancy.

Mr Dullonangal criticised his colleagues for unilaterally deciding the protest march without taking him and several other into confidence. He said he would bring it to the notice of Mr Parkash Singh Badal. He said the Federation would organise another protest march from Tarn Taran to Amritsar later this month to press for the release of list of 984 bodies.

Mr Dullonangal said besides AISSF colleagues, Mr Khalra's wife also accompanied the delegation which met the Deputy Commissioner.

Aug 4 - 1996.

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਅਗਸਤ (ਅ.ਬ.)- ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਘਰਿਆਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੇ ਗਿੱਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਕਲਗੱਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮੀਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੁਲਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। (ਬਾਕੀ ਸਫਾ 6 'ਤੇ)

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

(ਸਫਾ 3 ਦੀ ਬਾਕੀ)

ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ 25000 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ, ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨ੍ਹੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ 984 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਗੂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

4- Aug - 1996

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਉਂਦੇ...?

ਜਲੰਧਰ, 3 ਅਗਸਤ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) – ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੰਗ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਣ।

Khalra alive: Wife

EXPRESS NEWS SERVICE

Jalandhar, August 3: Paramjit Kaur Khalra, wife of Jaswant Singh Khalra, the missing human rights activist of the Shiromani Akali Dal, has claimed that her husband is still alive and that she has witnesses to support her claim.

Paramjit, who was here in connection with a protest march organised by the All India Sikh Students federation (Badal), asserted that her husband was in the custody of a Central agency working in Punjab. However, she maintained that she had full faith in the enquiry being conducted by the CBI into the disapperance of her husband on the direction of the Supreme Court.

She was accompanied by Surinder Singh Ghariala, chairman Khalra Action Committee and asserted that she had three witnesses who had seen Khalra in various police stations from October last to June this year. She said that one such witness had already been presented before the CBI, who had seen her husband at Kang police station in Amritsar district on October 13, while the other two were to be presented. She feared that the Punjab police was trying to abduct these witnesses to weaken the case.

ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ

ਜਲੰਧਰ, 3 ਅਗਸਤ (ਪਵਨ)– ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹਨ।

ਅਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਭ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ 95 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਕਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ ਥਾਣੇ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਵਿਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ 95 ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 96 ਵਿਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ।

August 6.' 1996

Khalra is alive, says wife

Tribune News Service

JALANDHAR, Aug 3 – Mr Jaswant Singh Khalra, human rights activist who has been missing since September 6 last year from Amritsar, is alive. This was claimed here today by Mrs Paramjit Kaur, wife of Mr Khalra.

Mrs Paramjit Kaur, who had come to Jalandhar to participate in the AISSF protest march along with members of the Khalra Action Committee, said her husband was under police detention at an undisclosed place.

She was confident that Mr Khalra would be released soon.

Mr Surinder Singh Gharyala, chairman of the Khalra Action Committee, also said that Mr Khalra was alive. He claimed that Kikar Singh Jaura had seen Mr Khalra at the police station at Kang village in Tarn Taran on October 23 last year. Again on March 2 this year Mr Khalra was seen by two persons but he refused to disclose any details.

Some persons also made an attempt to kidnap one of them from Amritsar. An FIR in this connection had been lodged with Civil Lines police station, Amritsar.

Both Mrs Paramjit Kaur and Mr Surinder Singh expressed satisfaction at the action taken by the Supreme Court and the CBI. They wanted the CBI to expedite the enquiry so that Mr Khalra returned soon.

Typing course for ex-servicemen

From Our Correspondent

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਉਂਦੇ...?

ਜਲੰਧਰ, 3 ਅਗਸਤ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) – ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੰਗ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਣ।

1 Aug. 1996.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ [illegible] ਹੁਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖੰਡ ਪੀਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲੜਾ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ: ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਕੇਸ 'ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 365/220 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 365 ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ।

ਖਾਲੜਾ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ. ਜਾਂ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ [illegible] ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਆਰ. ਐਸ. ਸੋਢੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਨਾਇਰ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ

(ਬਾਕੀ ਸਫਾ 9 ਕਾਲਮ 7)

ਕਿਸ਼ਤੀ [illegible]

SAT 27 JULY 1996

ਉਠਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਾ ਉਠਾ ਦੇਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ: ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ 'ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

27 July 1996.

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ

ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਜੁਲਾਈ- ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ. ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ, ਸ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸ. [illegible] ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਲਈ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਅਗਵਾਹ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਸ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸ. ਜੀ.ਐਸ.ਗਿੱਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮੀਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲ-ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

26 JULY 1996

ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਧਰਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ-(ਯੂ. ਐਨ. ਆਈ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਸਾਧਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮੰਚ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ-ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਪੀ. ਏ. ਸੰਗਮਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ।

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਸਲਘਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਠ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ: ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮੰਚ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਪਗ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸ: ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ: ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ।

ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮੰਚ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਸੜਕ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਭੇਦ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ (ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਐਮ. ਪੀ.) ਡੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਐਚ. ਐਸ. ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ-ਟੌਹੜਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-(ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਲਾਵਾਰਸ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਸਲਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ

(ਬਾਕੀ ਸਫਾ 9 ਕਾਲਮ 3)

26 July 1996.

ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ

– ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਰਵਿੰਦਰ –

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ : ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਚੌਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਣ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ (ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ) ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ-ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ।

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮਾਗਾਟੂ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਥੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਹੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜਿਸ ਨੇ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ 1984 ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ, ਨਵੰਬਰ '84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ 'ਨਜ਼ਾਰਾ'

(ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 5 ਕਾਲਮ 2)

ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ

(ਸਫ਼ਾ 1 ਕਾਲਮ 4 ਦੀ ਬਾਕੀ)

ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲਚਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ 'ਤੇ 'ਲਾਵਾਰਸ' ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ।

ਸ੍ਰੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਕੌਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।"

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ "ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਧਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈ।"

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ।

ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ. ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਟਾਡਾ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗਿਉਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

25 JULY 1996

ਅਜੋਕੀ ਆਵਾਜ਼

ਵੀਰਵਾਰ 25 ਜੁਲਾਈ 1996

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਅਮਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਮਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1990 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 984 ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 74 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਫੜਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਪੱਖੀਆ ਦਾ 'ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਪੂਰੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 1992 'ਚ ਜਾਅਲੀ ਚੋਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚਰਮਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਰ ਨਜਾਇਜ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਅਦਾਲਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਝੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਫੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਏਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਦੱਸਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਜਾਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

24 July 1996

ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ 25 ਨੂੰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਜੁਲਾਈ-(ਸ. ਰ., ਵਿ. ਪ੍ਰ.) ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ 25000 ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ 984 ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ: ਝਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਉਘੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸ: ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

25 July 1996

ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਅੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) -ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲ੍ਹ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਾਲਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

22 July 1996.

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ

90 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸੁ. ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼

ਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ- ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ 90-95 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 74 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਸਰੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ 984 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲਵਾਰਿਸ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਂਜ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗਤ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਫਸਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ.ਬੀ.ਈ. ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ 'ਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਜੀਤ

23 JULY 1996

ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ 'ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ' ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ-(ਏਜੰਸੀਆਂ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾੜੀਆਂ 984 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਰੋਸ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀਂ ਹੱਥੋਂ ਰੁਲਦਿਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਸਾਂਸਦ ਸ: ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ ਨੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ

ਉਕਤ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸਸਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਖਲਪ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.5 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਘਾਟਾ-ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੀ. ਐਮ. ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 1995-96 ਦੌਰਾਨ 244 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਕਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1994-95 'ਚ 40.80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬੀ-747-400 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੋਇੰਗ ਏਅਰਪਲੇਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।

ਪਾਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ-ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

(ਬਾਕੀ ਸਫਾ 10 ਕਾਲਮ 5)

23 JULY 1996

CBI submits report in Khalra case

NEW DELHI, July 23: The CBI has submitted a report on its probe into the abduction of Jaswant Singh Khalra, a human rights activist of Punjab, to the Supreme Court, reports PTI.

The report was submitted to the division bench of the Apex Court, comprising Justice Kuldeep Singh and Justice Saghir Ahmad, yesterday, a CBI spokesman said today.

The CBI informed the court that investigation in this matter was complete and the investigating agency would soon file a chargesheet against the officials involved in the case, he said.

The CBI would shortly be seeking sanction for prosecuting the officials allegedly involved from the Punjab government.

The judges, after perusing the report, appreciated the work done by the CBI officials, he said. The Supreme Court directed the CBI to complete this process by July 30.

20 July 1996

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨੂੰ

ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਜੁਲਾਈ-(ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਸਥਿਤ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਉਕਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੀ. ਐਸ. ਸੰਧੂ ਨਾਮੀਂ ਇਕ ਐਸ. ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬੀਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ. ਐਸ. ਸੋਢੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸ. ਪੀ. (ਹੈਡਕੁਆਟਰਜ਼ ਤਰਨ ਤਾਰਨ), ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਝਬਾਲ), ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਐਸ. ਐਚ. ਓ., ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਸਰਹਾਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਚਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ: ਘਰਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ: ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਖਲ 'ਤੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ: ਘਰਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਖਾਲੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮ. ਪੀ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।

18 JUNE 1997 ਅਜੀਤ

ਸੰਧੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਸਫਾ 3 ਦੀ ਬਾਕੀ)

ਸ: ਢੱਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਠੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਸੂਹੇ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 38 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ: ਢੱਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ 'ਤੇ ਦਸੂਹੇ ਵਿਖੇ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਦੀ 3 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ,. ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਸ: ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ-ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਹੜੱਪੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਠੱਠੀਖਾਰਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹੀ ਕਰੀਬ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 30 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦਾ ਭਰਾ ਸ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢੱਟ, ਝਬਾਲ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਮਾਲੂਵਾਲ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਬਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਚਰਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲੀਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ, ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 7 ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਕਹਿਰ ਦੀ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਵਿਥਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਾਡਾ ਦੇ 17634 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਕੱਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2548, 2203 ਅਤੇ 1928 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਕਾਰਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ 1200 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, 950 ਬੀਬੀਆਂ, 9 ਵਕੀਲਾਂ, 6 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਲਾਵਾਰਿ... ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ... ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਸਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ... ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ...

ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿ... ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ... ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੀਆਂ।

THE TRIBUNE

WED 4 JUNE 1997

PM urged to order probe into killings

Tribune News Service

AMRITSAR, June 3 — Mrs Parmjit Kaur Khalra, wife of Jaswant Singh Khalra, general secretary, human rights wing of the Shiromani Akali Dal, who was allegedly picked up by the Tarn Taran police in 1995, has demanded the setting up of a judicial commission headed by a Supreme Court judge to investigate the killings of innocent people in Punjab at the hands of the police and the victims should be extended assistance.

In a communication to the Prime Minister, Mr I.K. Gujral, a copy of which was released to the Press here today, she demanded immediate arrest of Mr K.P.S. Gill, a former DGP, and his prosecution in a special court for the alleged killings of innocent people in "fake" encounters and atrocities committed on innocent people on his orders. "Punjab should not be sacrificed to save 140 police officials."

She appealed to the Prime Minister to pay a visit to Tarn Taran and have first-hand information about the alleged repression and oppression committed by Mr Ajit Singh Sandhu and other police officials on innocent people.

Referring to the recent statements and the letter written by Mr Gill to the Prime Minister, she said that after the death of Mr Sandhu, Mr Gill had been blowing hot and cold against the human rights organisations, the judiciary and the Press describing them as agents of foreign powers posing danger to the unity and integrity of the country.

She said the Punjab problem erupted due to a series of discrimination against Sikhs, the "attack" on the Golden Temple, the demolition of Akal Takht, the "massacre" of Sikhs in November, 1984, killings of "25,000 innocent Sikhs" and their cremation describing them as "unclaimed" bodies, fake encounters, denigration of womenfolk etc. Instead of amicably resolving the Punjab problem, an "army solution" was given.

She alleged that Mr Khalra was kidnapped by the police party of Mr Sandhu because he had "exposed" the cremation of 25,000 Sikh youth declaring them as "unclaimed bodies."

She asked the Prime Minister whether he would like to save police officials for killing Mr Kuljit Singh Dhat, a nephew of Shaheed Bhagat Singh, for the disappearance of Baba Charan Singh of the kar seva sect and his family, for the killing of Mr Kulwant Singh, an advocate and his family, for using seven persons as a "human shield" in the Behla encounter and for killing many other innocent people.

Ajit

6 April 1997

ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ! ਮਝੈਲ ਸਪੋਰਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਸ: ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਭਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸ: ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਐਮ. ਪੀ. ਸ: ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਕਾਜੂਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 29-30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਫੋਟੋ: ਨਿਰਮਲ ਸਟੂਡੀਓ

"Bhupinder Singh's case was no

can be found in one out of five.

Indian Express, April 19, 98

Khalra's wife accused of graft

UNITED NEWS OF INDIA
JALANDHAR, APRIL 18

SPECIAL police officer (SPO) Kuldip Singh, one of the two important witnesses in the case of disappearance of human rights activist Jaswant Singh Khalra, has charged Khalra's wife Paramjit Kaur among others with having bribed his (SPO's) wife, asking her that he (SPO) should depose in their favour in the Khalra case in the CBI court at Patiala.

In a complaint lodged with the Shahkot police in Jalandhar district, Kuldip Singh alleged that Paramjit Kaur, Balwinder Singh Chabal, Surinder Singh Ghariala, Rajiv, Gurbhaj Singh and others came to his in-laws house at Sarangwal village where he had come to drop his wife.

A resident of Machar village in Tarn Taran city police station area, Kuldip Singh said when Paramjit Kaur and her associates came to his in-laws house around 11.30 pm, he had already left but the accused met his wife and gave her Rs 50,000 with a promise to send him (SPO) to the United States and get him a house in Amritsar if he deposed in their favour in the Khalra case.

The Shahkot police yesterday registered a case under Sections 8, 9, 12 of the Prevention of Corruption Act against the accused named in the FIR on the statement of Kuldip Singh.

The Committee for Coordination on Disappearances among other human rights organisations had met Chief Minister Parkash Singh Badal in Chandigarh on April 14, alleging that the accused involved in the Khalra disappearance case were resorting to intimidation of key witnesses.

The activists alleged that Kikar Singh and Kuldip Singh, two important witnesses in the case, were allegedly being pressurised, while five cases had been slapped against one of the two witnesses.

They also alleged that the lawyer fighting the Khalra case in the CBI court at Patiala was being harassed and threatened and the vehicle in which they travel from Chandigarh to Patiala was damaged, while threatening phone calls were also being made to the complainant lawyer.

Jaswant Singh Khalra, convenor of the human rights wing of the Akali Dal, had disappeared while collecting evidence on disappearances and cremation of thousands of youth during the heydays of terrorism in Punjab.

He was allegedly abducted by the Punjab Police on September 6, 1995 and is claimed to have been seen by some witnesses in police custody, sometime in October, of the same year.

ਅਜੀਤ

19 APRIL 1998

ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਜਲੰਧਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਇਕ ਗਵਾਹ ਐਸ. ਪੀ. ਓ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।

ਉਕਤ ਐਸ. ਪੀ. ਓ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੱਚੜ, ਥਾਣਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਿਟੀ ਜੋ ਖਾਲੜਾ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਸੇਰੰਗਵਾਲ, ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਾਸੀ ਝਬਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਘੜਿਆਲਾ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਲਾਸੌਰ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ 'ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ' ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸ. ਪੀ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਂਗੇ।

ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8, 9, 12 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 506 ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਤਹਿਤ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ: 63 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।

ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ

INDIAN EXPRESS
TUESDAY - 7 DEC 2004

Families of missing youth to move apex court

DHARMENDRA RATAUL
AMRITSAR, DECEMBER 6

THE families of the youth who were killed during the height of militancy in Punjab have rejected the compensation amount of Rs.2.5 lakh recently announced by National Human Rights Commission (NHRC). Instead, ninety out of the 109 such families, have submitted their power of attorneys to the Association of Families Disappeared in Punjab who will file a writ petition before the Supreme Court seeking 'adequate compensation and justice'.

At a meeting convened by the AFDP here on Sunday to know the views of the families on the NHRC compensation, they unanimously agreed not to accept the amount since was too little too late. General Secretary of AFDP Paramjit Kaur Khalra said: "Now that we have received their power of attorneys, senior advocates would be consulted for filing the petition in the Supreme Court."

Khalra herself was at the receiving end of police brutality during the militancy when her husband Jaswant Singh Khalra, who was a human rights activist, was picked up from home allegedly by the police.

The families of the victims have demanded compensation of Rs.10 lakh, a job for a member of the family and pension for the deceased.

Khalra said that the next hearing of the NHRC would be held on December 23, following which, they would file the fresh petition in the apex court. She said that the compensation announced was not at all enough to heal the wounds considering the scale of excesses committed by the police against them during the height of militancy.

She, however, acknowledged that the NHRC judgement last month had provided a ray of hope for the aggrieved families of the young youth who were killed and their bodies cremated as unidentified.

ਅਜੀਤ

14 Nov 2004

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ)–ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨਾਮੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 109 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਨਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ 'ਅਜੀਤ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ/ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸ: ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੁਰੰਤ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ: ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

*** ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ**
*** ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਫ਼ਾ 9 'ਤੇ**

(ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 11 ਕਾਲਮ 3)

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

(ਸਫ਼ਾ 1 ਦੀ ਬਾਕੀ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1996 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰਸੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 109 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਅਨੰਦ, ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ. ਭਾਸਕਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਕੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਕਦ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਮਿਆਦੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਰਿਪੋਰਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸ: ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2097 ਅਜਿਹੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ (ਕਲੇਮ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 1600 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 109 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ: ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 2097 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੀ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਸ: ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵਾਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਸ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਿੱਲੀ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਖਾਲੜਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜੀਤ
SUNDAY 14 Nov 2004

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ

(1) ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ 'ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ' ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ (ਸੱਜੇ) ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ। (2) ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ 'ਮੱਖਣ' ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ (ਸੱਜੇ) ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ। (3) ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਾਲੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ (ਸੱਜੇ) ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ। *ਤਸਵੀਰਾਂ : ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤਰਨਤਾਰਨ*

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਲਾਂਬਾ, ਪ੍ਰੀਤ, ਸੋਢੀ)-ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 109 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 109 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

30 ਨਵੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲਾ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੱਖਣ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।

ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਭਰਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਹਿਲਾ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰ (ਉਸ ਸਮੇਂ) 19 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਫੜ ਕੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਬਹਿਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਐਸ. ਪੀ. ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਰਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (19) ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਕੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (22) ਤੇ ਪਿਤਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

दैनिक जागरण

FRIDAY 12 NOV 2004

मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे सरकार

जागरण ब्यूरो/भाषा, चंडीगढ़/ नई दिल्ली

आतंकवाद के दौर में पुलिस हिरासत में मारे गए लोगों का मामला

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश सरकार को दोषी माना
- दो माह के अंदर प्रभावित परिवारों को राशि दी जाए

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली वर्ष 1984 से 1994 के बीच पुलिस हिरासत में हुई मौतों के 109 केसों में मुआवजा देने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस के डीआईजी लिटिगेशन ने बताया कि इन केसों में हर एक वारिस को 2.50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इस मुआवजे को अमृतसर के जिला न्यायाधीश या सब डिविजनल मिजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाना है।

मानवाधिकार आयोग में प्रदेश सरकार व पुलिस दोषी ठहराते हुए आदेश दिया है कि उसे प्रत्येक मृतक के परिजन को ढ़ाई लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएस आनंद और सदस्यों, न्यायमूर्ति वाय भास्कर राव तथा आरएस काल्हा की पीठ ने कहा कि पंजाब सरकार इन 109 व्यक्तियों की जान की रक्षा करने में असफल रही। इन लोगों के जीवन के अधिकार का हनन करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। अमृतसर में कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी कर अथवा मानवाधिकार के उल्लंघन के बारे में विचार किए बिना करीब 2097 शवों को लावारिस और अज्ञात करार देते हुए कथित तौर पर उनका चुपचाप अंतिम संस्कार करने के मामले में आयोग के इस फैसले को पहली राहत कहा जा सकता है।

आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि यह आदेश किसी पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारियों को दोषी ठहराए जाने के बारे में कोई राय जाहिर नहीं करता। आयोग ने आदेश दिया कि राज्य सरकार से मुआवजा राशि मिलने के दो माह के अंदर इसे अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट या संभागीय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़ितों को वितरित किया जाना चाहिए।

आयोग ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजन को 2.50 लाख रुपये बतौर मुआवजा दिए जाने चाहिए, जिसमें से आधी रकम परिजन को सीधे दे दी जाए और शेष रकम पांच वर्ष के लिए सावधि जमा कर दी जाए।

HINDUSTAN TIMES
FRIDAY 12 NOV 2004

'Secret cremations' in Punjab: NHRC orders compensation

Press Trust of India
New Delhi, November 11

IN A landmark order in the case of "secret" cremations by Punjab Police during its 1984-1994 anti-terror drive, the National Human Rights Commission (NHRC) today held the state government "vicariously liable" for 109 of these deaths and asked it to pay compensation of Rs 2.5 lakh each to the next of victims' kin.

"The state of Punjab is accountable and vicariously responsible for the infringement of the indefeasible right to life of those 109 persons as it failed to safeguard their lives and persons against the risk of avoidable harm," an NHRC Bench comprising chairperson Justice A.S. Anand and members Justice Y. Bhaskar Rao and R.S. Kalha, said.

This is the first time relief has been awarded in the case of the alleged cremations of 2,097 bodies as "unclaimed or unidentified" in Amritsar without observing lawful procedure or where there has been any other violation of rights.

The Commission directed that the disbursement of the amount shall be made by the District Magistrate, Amrtisar, or the SDM concerned within two months of receiving it from the state government.

Half of the Rs 2.5 lakh compensation has to be paid directly to the next of kin and the rest to be kept in a fixed deposit for a period of five years, the NHRC said. The next of kin of the victims can draw interest on the fixed deposit.

In its affidavit before NHRC, Punjab Police admitted that the 109 people were in its custody before they died and were cremated. NHRC said it "unhesistantly" holds that "human rights of these 109 persons... stood invaded and infringed when they lost their lives, while in the custody of the police, thereby rendering the state vicariously liable".

"The Commission is firmly of the view that whereas terrorism must be countered effectively and strongly, no democratic society can be permitted to chill civil liberties of the citizens while taking measures against the terrorists," Justice Anand said, pronouncing the order.

NHRC, as per a Supreme Court order, has been hearing the case to consider grant of compensation.

NHRC said the authorities and the people should treat its order as an "application of balm to whatever wounds were still left and to engage themselves to make the state of Punjab more prosperous and peaceful". "This order should not be considered in the spirit of 'win' or 'lose' as indeed it is not meant to be so construed," the Commission said.

'Damages inadequate'

PARAMJIT KAUR, who had petitioned the NHRC in the killing of 109 persons in Punjab Police during terrorism in the state, has expressed dissatisfaction with NHRC's order for cash compensation for the victims' families. P3

"The state of Punjab is accountable and vicariously responsible for the infringement of the indefeasible right to life of those 109 persons as it failed to safeguard their lives and persons against the risk of avoidable harm"

ਅਜੀਤ

SUNDAY 14 Nov 2004

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ

(1) ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ 'ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ' ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ (ਸੱਜੇ) ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ। (2) ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ 'ਮੱਖਣ' ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ (ਸੱਜੇ) ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ। (3) ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਾਲੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ (ਸੱਜੇ) ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ। *ਤਸਵੀਰਾਂ : ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤਰਨਤਾਰਨ*

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਲਾਂਬਾ, ਪ੍ਰੀਤ, ਸੋਢੀ)-ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 109 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 109 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

30 ਨਵੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲਾ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੱਖਣ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।

ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਭਰਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਹਿਲਾ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰ (ਉਸ ਸਮੇਂ) 19 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਫੜ ਕੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਬਹਿਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਐਸ. ਪੀ. ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਰਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (19) ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝਾਮਕੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (22) ਤੇ ਪਿਤਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

दैनिक जागरण

FRIDAY 12 NOV 2004

मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे सरकार

जागरण ब्यूरो/भाषा, चंडीगढ़/ नई दिल्ली

आतंकवाद के दौर में पुलिस हिरासत में मारे गए लोगों का मामला

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश सरकार को दोषी माना
- दो माह के अंदर प्रभावित परिवारों को राशि दी जाए

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली वर्ष 1984 से 1994 के बीच पुलिस हिरासत में हुई मौतों के 109 केसों में मुआवजा देने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस के डीआईजी लिटिगेशन ने बताया कि इन केसों में हर एक वारिस को 2.50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इस मुआवजे को अमृतसर के जिला न्यायाधीश या सब डिविजनल मिजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाना है।

मानवाधिकार आयोग में प्रदेश सरकार व पुलिस दोषी ठहराते हुए आदेश दिया है कि उसे प्रत्येक मृतक के परिजन को ढ़ाई लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएस आनंद और सदस्यों, न्यायमूर्ति वाय भास्कर राव तथा आरएस काल्हा की पीठ ने कहा कि पंजाब सरकार इन 109 व्यक्तियों की जान की रक्षा करने में असफल रही। इन लोगों के जीवन के अधिकार का हनन करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। अमृतसर में कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी कर अथवा मानवाधिकार के उल्लंघन के बारे में विचार किए बिना करीब 2097 शवों को लावारिस और अज्ञात करार देते हुए कथित तौर पर उनका चुपचाप अंतिम संस्कार करने के मामले में आयोग के इस फैसले को पहली राहत कहा जा सकता है।

आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि यह आदेश किसी पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारियों को दोषी ठहराए जाने के बारे में कोई राय जाहिर नहीं करता। आयोग ने आदेश दिया कि राज्य सरकार से मुआवजा राशि मिलने के दो माह के अंदर इसे अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट या संभागीय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़ितों को वितरित किया जाना चाहिए।

आयोग ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजन को 2.50 लाख रुपये बतौर मुआवजा दिए जाने चाहिए, जिसमें से आधी रकम परिजन को सीधे दे दी जाए और शेष रकम पांच वर्ष के लिए सावधि जमा कर दी जाए।

THE TRIBUNE

FRIDAY 12 NOV 2004

Kairon, PS Patti, Dist Amritsar, Punjab. 63. 436/100 Sukhwinder Singh, S/o Dalip Singh Jat, R/o Manawala, PS Lopoke, Tehsil Ajnala, Dist Amritsar, Punjab. 64. 437/101 Sucha Singh, S/o Bhagwant Singh, R/o Madiawala, PO Bhilowal, PS Lopoke, Tehsil Ajnala, Dist Amrisar, Punjab. 65. 447/109 Sawinder Singh @ Shindu, S/o Shiv Singh, R/o Manga Sarai, PO Dhadde, PS Kathu Nangal, Dist Amritsar, Punjab. 66. 449/111 Tarlochan Singh @ Husna, S/o Kishan Singh Jat, R/o Saidolehal, PS Mehta, Tehsil Baba Bakala, Dist Amritsar, Punjab. 67. 450/112 Paramjit Singh, S/o Jaswant Singh Jat, R/o Village Vachnova, PS Jhander Singh, Tehsil Ajnala, Dist Amritsar, Punjab. 68. 479/127 Baldev Singh @ Deva @ Fauji, S/o Buta Singh, R/o Basarke Baini, PS Chheharta, Tehsil & Dist Amritsar, Punjab. 69. 480/128 Dalbir Singh @ Kala, S/o Kulwant Singh, R/o Pallah, PO Gagar Bhana, PS Mehta, Tehsil Baba Bakala, Dist Amritsar, Punjab. 70. 481/129 Balwinder Singh, S/o Najar Singh.,R/o Pallah, PO Gagar Bhana, PS Mehta, Tehsil Baba Bakala, Dist Amritsar, Punjab. 71. 482/130 Shaib Singh, S/o Kahan Singh, R/o Chung, PO & PS Mehta, Tehsil Baba Bakala, Dist Amritsar, Punjab. 72. 525/145 Tarsem Singh @ Sema, S/o Meju Kaka Sansi, R/o Bhourwala, PO Mohan Bhandarian, PS Ramdas, Tehsil Ajnala, Dist Amritsar, Punjab. 73. 526/146 Anokh Singh, S/o Banta Singh, R/o Bindi Aulakh, PS Lopoke, Tehsil, Ajnala, Dist Amritsar, Punjab. 74. 608/170 Lakhwinder Singh @ Lakha, S/o Harbhajan Singh Ramgaria, R/o Chowgan PS Mattewal Chogawan, Tehsil Baba Bakala, Dist Amritsar, Punjab. 75. 611/171 Rupinder Singh @ Fauji, S/o Harbans Singh, R/o Borewal kang, PS Majhitha. 76. 207/25 Shri Kashmir Singh S/o Gulzar Singh JatR/oV Jhander, Tehsil Ajnala, Amritsar. 77. 330/41 Kulwinder Singh S/o Bawa Singh JatR/o Vill Dhardeo, PS Mehta, Majitha. 78. 396/58 Manjinder Singh @ Jinda S/o Thakur SinghR/o Village Pakhoke, Majitha. 79. 582/92 Sukhdev Singh @ Billa S/o Kishan SinghR/o Village Harian, PS K Nangal.

Tarn Taran Police District: 80. 37/99 Sarbjeet Singh S/o Tirath Singh Jat, r/o Nagoke, PS Verowal, Police District Tarn Taran, Amritsar. 81. 38/100 Gurbir Singh @ Raju S/o Joginder Singh Jat r/o Jhabal, PS Jhabal, Police District Tarn Taran, Amritsar 82. 48/121 Kuldip Singh @ Ghuggi S/o Kartar Singh Mehra r/o Chola Sahib, PS Sarhali, Police District Tarn Taran, Amritsar. 83. 49/122 Jassa Singh S/o Dharam Singh Majbi r/o Chola Sahib, PS Sarhali, Police District Tarn Taran, Amritsar. 84. 54/135 Darshan Singh S/o Dayal Singh Jat, r/o Mehmodpura, PS Valtoha, Police District, Tarn Taran. 85. 56/147 Balbir Singh @ Pappu S/o Mukhtiar Singh Jat, r/o Jella Roda, PS Mallanwala, District Ferozpur, Punjab. (However in CBI list, his name is mentioned as Balwinder Singh S/o Mukhtiar Singh) 86. 57/148 Dilbagh Singh @ Baba S/o Ram Singh Jat, r/o Koharka, PS Patti, Police District, Tarn Taran. 87. 72/183 Kashmir Singh S/o Dharam Singh Jat, r/o Jhander, PS Sadar Tarn Taran, Police District Tarn Taran, Amritsar. 88. 161/628 Inderjeet Singh @ Hardeep Singh @ Deepa S/o Karam Singh Jat, r/o Thatha, PO Sarhali Kalan, PS Harike, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar. 89. 169/655 Dilbagh Singh @ Bagha S/o Harnam Singh Mazbi, r/o Ratoul PS City, Tarn Taran District Amritsar. 90. 172/662 Manjinder Singh S/o Ajit Singh Jat, r/o Ratoul, PS City Tarn Taran, District Amritsar. 91. 181/682 Kulwinder Singh @ Pappu S/o Jassa Singh Jat, r/o Valtoha, PS Valtoha, Police District Tarn Taran, District Amritsar. 92. 186/695 Shri Manjit Singh @ Manna S/o Sardool Singh Jat, r/o Tanda, PS Sarhali, Police District Tarn Taran District, Amritsar. 93. 202/745 Harjit Singh S/o Amrik Singh Jat, r/o Sukhawala, PS Jandiala Guru, Police District Majitha, District Amritsar. 94. 205/773 Jatinder Singh S/o Jagir Singh Mehra, r/o Nurdi, Bazar Tarn Taran PS City Tarn Taran, Police District Tarn Taran, Amritsar. 95. 206/774 Salwant Singh @ Kulwant Singh S/o Tarlok Singh Jat, r/o Padri Kalan, PS Jhabal, Police District Tarn Taran, District Amritsar. 96. 216/811 Parabhjot Singh @ Jyoti S/o Avtar Singh Jat, r/o Muradpur, PS City Tarn Taran, Police District, Tarn Taran. 97. 260/920 Gurnam Singh @ Palli S/o Mohinder Singh Swarnkar, r/o Gali Kaselian Wali, Nurdi Adda, Police Station - City Tarn Taran. 98. 261/925 Jagdeep Singh @ Makhan Singh S/o Pritam Singh Goldsmith, r/o Adda Nurdi, Tarn Taran, PS City Tarn Taran.. 99. 262/926 Jatinder Singh S/o Darbara Singh Jat, r/o Mehmoodpura, PS Valtoha, Police District Tarn Taran, District Amritsar. 100 263/932 Rajinder Singh @ Bhupinder Singh Jat S/o Charan Singh Ramgarhia, r/o 3/36 Jandiala Road, Tarn Taran, PS Tarn Taran 101 264/933 Udham Singh @ Pastol Singh @ Bahadur Singh S/o Mehar Singh Ramgarhia, r/o Nanaksar, PS Tarn Taran, Police District Tarn Taran.. 102 266/942 Harbans Singh @ Kabal Singh S/o Santokh Singh Jat r/o Rasulpur, PS Tarn Taran (Sadar), Police District Tarn Taran, District Amritsar. 103 305/101 Harbans Singh @ Bansa s/o Milkha Singh Jat r/o Uboke, PS Patti, Police District Tarn Taran, District Amritsar. 104 319/104 Desa Singh S/o Amar Singh Majbi, r/o Raniwalah, PS Sirhali, Police District Tarn Taran, District Amritsar. 105 320/104 Shinda Singh S/o Bachan Singh Majbi, r/o Raniwalah, PS Sarhali, Police District Tarn Taran, District Amritsar. 106 322/104 Mangal Singh @ Manga S/o Karnail Singh Majbi, r/o Dhunda, PS Gonidwal, Police District Tarn Taran, District Amritsar. 107 84/746 Shri Rupinderjit Singh S/o Bhajan Singh Jat, R/o Village Kang, Police Station Sadar Tarn Taran 108. 113/1030 Paramjit Singh @ Pamma s/o Narinder Singh JatR/o Bahmiwala, Police Station Patti, Tarn Taran. 109. 629/1073 To 634/1078 Jagtar Singh @ Jagga s/o Bawa Singh MehraR/o Village Tarsika, Police Station Mehta, Majitha.

Kidwai greets people on Divali

TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, NOVEMBER 11
The Punjab and Haryana Governor, Dr. A.R. Kidwai, today conveyed his good wishes to the people of Punjab, Haryana and Chandigarh on the eve of the auspicious festival of Deepawali.

In a message Dr Kidwai hoped that this festival would bring happiness and harmony in the lives of the progressive people of this region. He called upon the people to celebrate this festival rising above parochial considerations of caste, colour and creed to strengthen "our centuries-old traditions of peaceful co-existence."

12 Nov 2004

Kangra valley

Kargi hero's

Di... will be compensated

Amritsar Police District: Sr.No. CBI No. Name of deceased, parentage and address 1. 53/1 Tejinder Singh s/o Roor Singh r/o Tharu, PS Tarn Taran City, Dist Amritsar 2. 88/6 Nishan Singh s/o Bahal Singh r/o Ranian, PS Lopoke, Ajnala Dist, Amritsar 3. 121/7 Parminder Singh @ Balour S/o Amrik Singh Jat r/o Kalia Sakatra, P.S. Khemkaran, Amritsar 4. 122/8 Harinder Singh @ Shaheed s/o Pyara Singh r/o Kohali, PS Lopoke, Ajnala Dist, Amritsar 5. 160/11 Dalbir Singh s/o Karnail Singh r/o Bal Saran, PS Beas, Phatak Dhanpai Road, PS Islamabad, Amritsar 6. 161/12 Rajinder Singh s/o Preetam Singh r/o Gali No. 13, Guru Nanak Pura, PS Islamabad, Dist Amritsar 7. 162/13 Vijay Kumar s/o Joginder Pal r/o Near Jwala Flour Mills, PS Islamabad, Amritsar. 8. 163/14 Harish Chander s/o Inderjit r/o Nawan Kot, PS Islamabad 9. 167/16 Arjinder Pal Singh @ Toni @ Nihal Singh s/o Chain Singh Jat r/0 Kasel, Mane KI Patti, Sarai Amanat Khan, The TTN, P S Sadar, Dist Amritsar 10. 201/25 Daljit Singh @ Billa s/o Sucha Singh r/o Mohalla Bog, Phagwara 11. 202/25 Gurinder Singh @ Jinda s/o Bhakshish Singh Jat s/o Basarke Gillan, PS Chheharta, Dist Amritsar 12. 218/27 Kashmir Singh @ Laddu s/o Kundan Singh r/o Nehru Colony, Amritsar 13. 220/28 Jaspal Singh s/o Preetam Singh r/o Mustafabad, Batala Road, PS Sadar, Dist Amritsar 14. 263/33 Avtar Singh s/o Dalip Singh r/o Kot Khalsa, PS Sadar, Amritsar 15. 266/34 Amrik Singh @ Bau @ Fakkar s/o Jagir Singh r/o Kirtangarh, Thandey, PS Sadar, Dist Amritsar 16. 273/36 Harjinder Singh @ Kala s/o Sadhu Singh r/o Amritsar, Shahid Udham Singh Nagar, Gali No. 2, Dist Amritsar 17. 292/44 Sucha Singh @ Charan s/o Mohinder Singh r/o Chhina Subjpur PS Raja Sansi, Ajnala Dist Amritsar 18. 313/50 Udham Singh s/o Gajjan Singh r/o Thathgarh, PS Jhabal, Dist Amritsar 19. 350/62 Randhir Singh @ Dhir Singh s/o Chanan Singh r/o Pairewal, PO & PS Ramdas, Ajnala Dist Amritsar 20. 352/63 Mohinder Singh s/o Mohan Singh r/o Sultanwind 21. 363/67 Piara Singh s/o Shingara Singh Jat r/o Sultanwind, Amritsar 22. 379/69 Jhujar Singh @ Neetu s/o Heera Singh r/o Gali No. 1, Anterzami Colony, PS A-Division, Dist Amritsar 23. 198/32 Swaran Singh S/o Lal SinghR/o Talwandi, Jalle Khan, PS Zira, Amritsar 24. 199/33 Daljit Singh s/o Saudagar Singh R/o V Chhapa, PS Chabal, Amritsar. 25. 219/37 Inderjit Singh S/o Harbhajan Singh JatR/o Shangana, PS Sadar, Amritsar

Majitha Police District: 26. 93/4 Jaswinder Singh, S/o Darshan Singh Arora, R/o Shaheed Udham Singh Nagar 27. 95/2 Randhir Singh @ Dhira, S/o Mann Singh Jat R/o Munda Pind, PS Jandiala. 28. 100/6 Jaswant Singh ,S/o Chanan Singh, R/o Sharifpura, District Amritsar 29. 124/13 Sukhdev Singh @ Sukha S/o Pyara Singh,R/o Tarsikka, PS Majitha. 30 233/34 Raghbir Singh @ Bira S/o Pratap Singh,R/o Runseeke, PS & Tehsil Derra Baba Nanak, Dist Gurdaspur, Punjab. 31. 234/25 Nirmal Singh @ Bittu S/o Mohinder Singh, R/o Runseeke, Ramgarian PS & Tehsil Derra Baba Nanak, Dist Gurdaspur, Punjab. 32. 239/26 Satnam Singh, S/o Ajit Singh Jat, R/o Bhagupur, PS Patti, Police District Tarn Taran, Dist Amritsar, Punjab. 33. 253/30 Kartar Singh @ Fauji, S/o Buta Singh Mazbi, R/o Adaliwal, PS Raja Sansi, Tehsil Ajnala, Dist Amritsar, Punjab. 34. 255/31 Mangal Singh @ Bittu, S/o Kartar Singh caste Mazbi R/o Adaliwal, PS Raja Sansi, Tehsil Ajnala, Dist Amritsar, Punjab. 35. 262/32 Gurmail Singh @ Gullu @ Pappu @ Udhna Sup S/o Naranjan Singh, R/o Village Cheema Bath, PS Beas, Tehsil Baba Bakala, Dist Amritsar, Punjab. 36. 263/33 Prem Singh @ Prema S/o Mohinder Singh, R/o Village Cheema Bath, PS Beas, Tehsil Baba Bakala, Dist Amritsar, Punjab. 37. 270/36 Lakhwinder Singh, S/o Balwant Singh, R/o Sathiali PS Kahnuwan District Gurdaspur 38. 272/37 Narinder Singh @ Ninda, S/o Rattan Singh, R/o Bham, PS Shri Har Gobindpur, Batala, Dist Gurdaspur, Punjab. 39. 274/39 Baljit Singh @ Chhota , S/o Gurdit Singh, R/o Nangli , PS Mehta, Tehsil Baba Bakala, Dist Amritsar, Punjab. 40. 284/42 Swaran Singh @ Swarana, S/o Dhian Singh Jat , R/o Mandranwala, Po & PS Ramdas, Tehsil Ajnala, Dist Amritsar, Punjab. 41. 298/44 Randhir Singh @ Dhira s/o Chanan Singh Jat R/o Natibpura, Model Town, Division No. VI, Jalandhar, Punjab. 42. 311/50 Gurinder Singh @ Hira , S/o Major Singh Jat, R/o Nagoke, PS Verowal, Tehsil Tarn Taran, Dist Amritsar, Punjab. 43. 316/51 Narinder Singh, S/o Manga Singh Jat, R/o Jalalpura, PS Majitha, Tehsil & Dist Amritsar, Punjab. 44. 322/52 Mangal Singh @ Manga, S/o Sohan Singh Jat, R/o Village of Arjun Manga, PS Mehta, Tehsil Baba Bakala, Dist Amritsar, Punjab. 45. 327/54 Paramjit Singh, S/o Avtar Singh, R/o Udhowali 46. 332/55 Surta Singh, S/o Malook Singh Jat, R/o Harar Kalan, PO,PS & Tehsil Ajnala, Dist Amritsar, Punjab. 47. 343/56 Kewal Singh, S/o Hazara Singh, R/o Village Kiampur 48. 344/57 Paramjit Singh @ Kala, Ranjha, S/o Hazara Singh, R/o Chhina Shahbazpur. 49. 348/58 Balwant Rai @ Gulu @ Gurdit Singh, S/o Harichand Arora, R/o Khilchian 50. 349/59 Balkar Singh, S/o Mohinder Singh, Village Jabhowal District Amritsar, 51. 350/60 Gurjit Singh @ Phumman Singh, S/o Bhajan Singh, R/o Chajjalwadi, PS Jandiala, Tehsil Baba Bakala, Dist Amritsar, Punjab. 52. 371/68 Malkiat Singh @ Meeta, S/o Gulzar Singh Jat, R/o Rana Kala, PO Jabbowal, PS Jandiala Guru, Tehsil & Dist Amritsar, Punjab. 53. 372/69 Gurmukh Singh @ Gorkhi , S/o Veer Singh, R/o Jani ki Patti, Mehta, Tehsil Baba Bakala, Dist Amritsar, Punjab. 54. 375/70 Trilochan Singh, S/o Joginder Singh, R/o Doojowal, PS Ramdas, Tehsil Ajnala, Dist Amritsar, Punjab. 55. 378/73 Balwinder Singh S/o Ajit Singh Jat, R/o Village Nangli Nusehra, PS Sadar, Dist Amritsar, Punjab. 56. 392/78 Angrej Singh, S/o Charan Singh Jat, R/o Jalal Usma, PS Mehta, Tehsil Baba Bakala, Dist Amritsar, Punjab. 57. 395/80 Gurdev Singh @ Bhutto S/o Harbans Singh, R/o Pakhoke, PS Tarn Taran (Sadar), Tehsil Tarn-Taran, Dist Amritsar, Punjab. 58. 400/81 Lakhwinder Singh @ Lakha, S/o Surjit Singh Jat, R/o Chak Kamal Khan, PO Sorian, PS Ajnala, Tehsil & Dist Amritsar, Punjab. 59. 401/82 Harjit Singh @ Har singh Butter, S/o Kashmir Singh, R/o Buutar Kalan, Mehta, Tehsil Baba Bakala, Dist Amritsar, Punjab. 60. 415/89 Jagtar Singh @ Jagga, S/o Dilip Singh, R/o Kairon, PS Patti City, Tehsil Patti, Dist Amritsar, Punjab. 61. 416/90 Sarwan Singh, S/o Mohinder Singh, R/o Village Makhi Margindpura, PS Bhikhiwind, Tehsil Patti, Dist Amritsar, Punjab. 62. 417/91 Satnam Singh, S/o Jarnail Singh, R/o

Relief too little, too late, says SAD

SAURABH MALIK
TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, NOVEMBER 11

Too little, too late that is how political parties in the state, and relatives of the victims, have described the order of the National Human Rights Commission (NHRC). The order may have ended struggle for monetary relief spread over a period of two decades, but the affected say the amount of compensation should have been "more".

Taking up the mass cremation case, the NHRC on Thursday awarded a compensation of Rs 2.50 lakh each to the relatives of 109 residents who died in the custody of the Punjab Police.

The commission was earlier directed by the Supreme Court to decide the compensation claims filed by dependents of the victims taken into custody by the police on the suspicion of being terrorists.

After they were served the final summons of death, their bodies were allegedly cremated in three police districts of Amritsar, Majitha and Tarn Taran. Over 2,000 people were reported missing during the period. The matter was subsequently referred to as the "mass cremation case".

Reacting to the judgement soon after its pronouncement, Shiromani Akali Dal's Secretary Dr D.S. Cheema claimed that at least Rs 10 lakh should have been handed over to the next of kin.

"After all, several young and innocent lives were lost due to police atrocities", he asserted. The matter, he added, should not end here. "Police officers involved in the commission of heinous offences like these should not be allowed to go scot-free," "They should be brought to the book", he said.

Expressing dissatisfaction with the compensation amount, Ms Paramjit Kaur Khalra — wife of human rights activist Jaswant Singh Khalra who went missing in1995 — said they had sought compensation of at least Rs 10 lakh each, besides jobs for members of the aggrieved families.

Human Rights lawyer R.S. Bains added that though the judgement was commendable, yet the commission as an institution had failed to deliver justice on time. The matter, he said, was hanging fire for over two decades.

On the other hand, former MLA-cum-human rights activist Inderjit Singh Jaijee said the directive would encourage other aggrieved families to approach the commission for justice.

The Punjab Police, in the meantime, clarified that the award of monetary relief was not an expression of opinion about "culpability or otherwise" of any police personnel.

Quoting the contents of the judgement, Deputy Inspector-General of Punjab Police (Litigation) said the commission had clarified that the "order should be treated as an application of balm to whatever wounds that were still left and should not be considered in the spirit of 'win' or 'lose'".

---

ing establishment of such courts was the only way to deal with terrorism following the withdrawal of POTA.

Talking to The Tribune here last evening, Mr Bitta said the courts so formed should be given wide-ranging powers so that they could root out terrorism from the country.

The front leader, while speaking about the latest peace initiatives put forward by Pakistan President Parvez Musharraf, said the proposal was an insult to the sacrifices made by the country on the issue.

He said Gen. Musharraf should not talk through the media and if at all he had any proposal it should be discussed at an appropriate forum.

THE TRIBUNE
FRIDAY 12 NOV 2004

THE TRIBUNE FRIDAY 12 Nov 2004

2.72 cr relief for kin of custodial death victims

S.S. NEGI
LEGAL CORRESPONDENT

NEW DELHI, NOVEMBER 11

The National Human Rights Commission (NHRC) today ordered the Punjab Government to pay Rs 2.72-crore compensation to the kin of 109 persons who had died in custody during militancy, holding that the state was liable to make monetary amends for infringment on their right to life.

The state government was directed to pay Rs 2.5 lakh to the kin of each victim in the three police districts of Amritsar, Majitha and Tarn Taran within two months through the district magistrates, who would ensure disbursement of the money through the sub-divisional magistrates concerned.

"We hold the state of Punjab liable to make monetary amends in this regard," the NHRC panel comprising Chairman Justice A.S. Anand, Justices Y. Bhaskar Rao and R.S. Kalha said.

Giving its verdict on a batch of petitions referred to it by the Supreme Court for deciding the compensation issue, the NHRC said 25 victims were detected by the CBI in Amritsar district, 54 in Majitha and 30 in Tarn Taran.

The government was directed to pay 50 per cent of the amount to each awardee in cash or through cheque and deposit the remaining 50 per cent in their name in fixed accounts for five years from which they would be entitled to withdraw the annual interest earned on it.

Asking the government to submit its compliance report after two months, the commission said the order "shall be binding" on the state as directed by the apex court.

The Committee for Coordination on Disappearance (CCDP) in Punjab had filed 1,600 claims before the commission, which had invited applications from victims' kin in July.

Since the NHRC in today's order had taken cognisance of 109 cases, hope for other victims is not over yet as further hearing in the matter has been fixed on December 23, CCDP counsel P.S. Grewal said.

Though the NHRC refrained from expressing opinion about the culpability of any police official for the mass custodial deaths for reasons that it might prejudice the ongoing CBI probe in these cases.

"A critical task of striking a fair balance by way of security concerns and human rights is to be performed and need of proportionality must not be ignored... the state cannot be permitted to go over board and in effect declare a war on the civil liberties of people because the rationale of anti-terrorism measures is aimed at protecting human rights and democracy," it said, adding that "counter-terrorism measures should therefore not undermine democratic values or subvert the rule of law."

The commission in a compassionate appeal to both Punjab Government and the people of the state reminded that the state had gone through a "turmoil" during militancy and with their united efforts it was able to come out of it and the order on compensation should be "treated as an application of balm to whatever wounds are still left and to engage themselves to make the state more prosperous and peaceful in keeping with its great traditions."

The order on compensation "should not be considered in the spirit of 'win' or 'loose' as, indeed, it is not meant to be so construed," the NHRC said.

See also pages 3, 14

HINDUSTAN TIMES 12NOV2004

'NHRC relief inadequate'

Vishal Rambani
Amritsar, November 11

PARAMJIT KAUR, who had petitioned the National Human Rights Commission (NHRC) in the killing of 109 persons in Punjab Police custody between 1984 and 1994 during terrorism in the state, today expressed dissatisfaction with NHRC's order for cash compensation for the affected families.

"Though the NHRC decision is a step towards victory, which my late husband Jaswant Singh Khalra had dreamt for the affected families, a compensation of Rs 2.5 lakh to each affected family after a long battle of 20-odd years is a mockery with victims' kin. Rs 2.5 lakh is inadequate for a family that had lost a near and dear one due to police brutality," Paramjit Kaur remarked.

Talking to Hindustan Times, she said that an affidavit submitted by the Punjab Government in which it admitted to killing of 109 persons in police custody had vindicated Khalra's findings of fake killings resorted to by Punjab Police during terrorism.

'A step in the right direction, but not good enough for a 20-yr fight for justice'

— Paramjit Khalra

"We had pleaded for Rs 10-lakh compensation, a job and a pension for elder persons of each affected family. The compensation ordered by the NHRC is very less," she maintained.

She also said that she hoped that compensations would be granted in nearly 1,800 cases of custodial death and police brutality filed by the Khalra Mission Committee in the NHRC.

Kaur further asserted that the KMC would now fight for identification and conviction of police officials who had killed these 109 persons in custody, which was admitted to by the state government.

We will appeal to the NHRC to increase the compensation amount as was in case of the death of my husband and advocate Kulwant Singh, in which the Supreme Court had granted a compensation of Rs 10 lakh each to the family of the duo.

It is pertinent to mention here that NHRC had issued public notice on July 19 in connection with the reported killings of 2,097 youths in fake encounter and cremations of their bodies as "unclaimed" during the militancy days.

Paramjit had filed a writ petition in the Supreme Court after the death of her husband to seek a probe into these killings.

Khalra, who had first raised the issue, was reportedly murdered by cops. Eight policemen are currently facing murder charges in a Patiala court in this regard.

ਅਜੀਤ

SUNDAY 15 AUG 2004

ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਅਗਸਤ (ਲਾਂਬਾ)-ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ "ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋ: (ਏ.ਐਫ.ਡੀ.ਪੀ.)" ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਵਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ, ਬੀ: ਬਲਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਸ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਸ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ: ਰਮਨ ਸਭਰਵਾਲ

ਏ.ਐਫ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਸ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਸ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 88 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰੀਬ 1500 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ 13 ਸਤੰਬਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 300-400 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 1200-1300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਬੀ ਬਲਾਕ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਵਿਖੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਲਈ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 30 ਜੁਲਾਈ, 2004

30 July 2004

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਗਿਆਨ ਉਹ ਪੰਖ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੂਝ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਹਾਂ।

-ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ

ਲਾਪਤਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡ

ਅਣਗਿਣਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਸੰਨ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਘੇਰਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1995 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅਧੂਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 19 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਘਟ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਵਾਜਬ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਪਿਛੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

HINDUSTAN TIMES
FRIDAY JULY 30, 2004

'No one can limit illegal cremation cases'

Gurpreet Singh Mehak
Fatehgarh Sahib, July 29

BIBI PARAMJIT Kaur Khalra, the wife of Jaswant Singh Khalra, today categorically stated that they would not allow anyone to limit the cases relating to illegal cremation cases of unclaimed body to the police districts of Amritsar, Tarn Taran and Majitha.

"Amritsar is not the only district where innocent people were killed. The entire state suffered the police atrocities," Bibi Khalra, who is also general secretary of the Association of Families of Disappeared in Punjab (AFDP), said.

Many of those coming to the camp set up at Amritsar are returning disappointed after being informed that only claims from the three police districts were being entertained, she said.

The AFDP is committed to fighting for all victims of the state, she said, adding that people should come forward and help her association by giving details of all those who were killed in the "fake encounters".

"This is the same list released by my husband in 1994. However, out of the list of 6,000 compiled by him, only 2,097 have been short listed for compensation," she said.

The AFDP will try its best to get compensation for the remaining cases as well, she added.

Asked about the SGPC's role, she said her association was in fact doing what the SGPC and the Panthic parties should have been doing, as they were busy in their politics.

"All officers involved in these false encounters would try to suppress the claims by all means. They should hence be identified and transferred to far-flung places," Bibi Khalra added.

HT

Paramjit Kaur Khalra, wife of Jaswant Singh Khalra, expressing her views in Fatehgarh Sahib on Thursday.

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ THURSDAY 22 JULY 2004

ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਚੈਨ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ: ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 1994 ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਮੁੜ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ। ਦਰਜਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਸਦਾ ਲਈ ਬੁਝ ਗਏ।

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ➔ਬਾਕੀ ਸਫਾ 10 'ਤੇ

ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਚੈਨ

ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵੇਲੇ ਐਸ. ਪੀ. (ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1986 ਤੱਕ ਉਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੱਜ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਚਲਦੇ ਸਨ। ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਪੋਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਦ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ

ਰਾਜਨ ਮਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਜੁਲਾਈ : ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਈ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2097 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 582 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, 274 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 1238 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਠੱਠੀਆਂ ਖੁਰਦ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਮਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 28 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਰੀਏ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਤਿਵਾਦੀ ਛੁਪੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰੀਕੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। 24 ਸਤੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੂਹ ਨੇੜੇ ਝੂਠਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਕ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਈ।

ਪਿੰਡ ਧਾਰੜ (ਜੰਡਿਆਲਾਗੁਰੂ) ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀ.ਏ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, 1991 ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੀ।

ਪਿੰਡ ਸੁੱਖੇਵਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੱਠ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ।

ਪਿੰਡ ਚੋਗਾਵਾਂ ਸਾਧਪੁਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋ ਜੇਠ '93 ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਟ ਆਤਮਾ ਰਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ... ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ, 1992 ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ, 1992 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਰਪਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਲਟੋਹੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 11 ਜੂਨ, 1992 ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ 12 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਖੋਕੇ ਵਾਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1990 ਵਿਚ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਾਤ ਘਰੋਂ 12 ਵਜੇ ਚੁੱਕਿਆ।

ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕੈਂਪ ਸਥਾਨਕ ਬੀ. ਬਲਾਕ ਰੇਲਵੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 2097 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 25 ਹਜ਼ਾਰ 9 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹਲਫੀ ਬਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲੀਸ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। -ਫੋਟੋ: ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ
THURSDAY 22 JULY 2004

NHRC notice: A ray of hope for affected families

Demand raised for Rs 10 lakh compensation and punishment to guilty cops

HT Correspondent
Amritsar, July 20

WITH THE National Human Rights Commission (NHRC) issuing a public notice in connection with the alleged killing of 2,097 youths in fake encounters and cremations of their bodies as "unclaimed" during militancy has brought a ray of hope for justice for the families which lost their near and dear ones.

The NHRC notice has not only led to a demand for suitable compensation to the affected families, but also punishment to the guilty police officials.

"*Der aaye par durust aye,*" is how Paramjit Kaur reacted to the Commission notice. She said that the NHRC had "vindicated" her husband and human rights activist Jaswant Singh Khalra's assertions about "fake encounter killings". "By the grace of God, the affected families will now get justice," she added.

It is pertinent to mention here that Paramjit had filed a writ petition in the Supreme Court after the death of her husband to seek a probe against the killings allegedly at the hands of police during militancy. Khalra, who had first raised the issue, was allegedly killed by cops. Eight policemen are facing murder charges in a Patiala court in this regard.

Paramjit Kaur told Hindustan Times that it was their "first win in a war" launched by Khalra, who helped identify bodies of those killed in "fake' encounters at graveyards and cremation grounds.

"The NHRC has published the same list that my husband released in the Canadian Parliament, which shows that the then Punjab DGP K.P.S. Gill always spoke lies on the issue of fake encounters. It also vindicates our stand," Kaur added.

It is pertinent to mention here that the NHRC is conducting an inquiry into the circumstances leading to the cremations carried out by Punjab Police of 2,097 bodies as "unclaimed" in the police districts of Amritsar, Majitha and Tarn Taran between June 1984 and December 1994.

Meanwhile, Association of Families of Deceased in Punjab coordinator Amrik Singh, who is fighting for compensation and justice to the affected families, asserted that each family should get Rs 10 lakh, an amount given to the family of Khalra.

"Though a belated move, we welcome it and urge the Supreme Court and the NHRC to punish the guilty cops, besides compensating the affected families," he added.

Other human rights and political outfits also welcomed the development. Human Rights Organisation chairperson Surinder Singh Gharyala termed it a "step toward justice". Police first killed Punjabi youths in fake encounters and then cremated the bodies as unclaimed, he charged.

Nahar Singh, who had lost his son in a "fake police encounter" in Tarn Taran, quipped, "It has given us hope for justice".

HINDUSTAN TIMES
21 JULY 2004

INDIAN EXPRESS. 20 JULY 2004 (TUESDAY)

At last, justice finds the missing

NHRC | Lists the names of 693 youths cremated by the Punjab Police

DHARMENDRA RATAUL
AMRITSAR, JULY 19

FOR years, their families had given them up for missing. For years, they had swung between hope and despair. Living life in a state of limbo in the absence of any proof to validate their worst fears: that their sons were dead. All because the Punjab police had cremated as unidentified the bodies of 2,097 men during the height of militancy. Today, many of these families were finally able to come to terms with the past when the National Human Rights Commission (NHRC) issued an advertisement listing the names of 693 youths who were cremated by the police, and asked them to submit claims for compensation if any on account of rights violations.

Tears coursed down the cheeks of Roor Singh as he clutched at the newspaper with the name of his son Tejinder Singh neatly underlined. "It was in a midnight swoopdown on our house at Throo village that the Bhikiwind police picked up my younger son Tejinder who was only 23. We asked them to tell us why but that only prompted them to give us all a hiding," he cries. About ten days later, they read in a

CONTINUED ON PAGE 2

PHOTO BY RANJIT SINGH

Roor Singh (in dark blue turban) and others who lost members of their family during militancy

vernacular that Tejinder, described as a 'militant', had been killed in an encounter. "But we never received his body, so how could we believe the report," says Roor Singh.

After today's ad, he believes it. But more important to him is the prospect of justice, the line that reads: "If, as a result of enquiry, it is found that these... bodies were cremated without following the lawful procedure or that there has been any other violation of human rights in relation to such deceased person, the Commission may... consider grant of compensation." For Roor, more than compensation, it's a chance to prove his son's innocence. This is the story of most of the people queuing up at the camp office of Amrik Singh, coordinator of Association of Families of Disappeared People in Punjab (AFDPP), who's examining their credentials as per directions of the NHRC.

Teja Singh, who fled his native village of Saido for the fear of police, tells how his son Gurnam Singh, who was in his early 20s, was picked up from their rented house in Harayana, and killed in a fake encounter by the Kairon police. "But we never got to see his body. Now it seems justice will finally be done," he sighs.

The 80-plus Dalip Kaur of Bhindia village near Lopoke, who lost her eyesight while waiting in vain for her son Karamjit Singh, sobs quietly when you broach the topic with her. "I can never forget the night of January 16, 1993, when the police barged into our house, woke up my sleeping son, and gave him a brutal thrashing in front of my eyes before taking him away with them. I tried so hard to stop them but failed." That was the last she saw of her son. Before leaving, the policemen said they were from Rajpura. Later, a neighbour told her about a newspaper report claiming that her son was a militant and had been killed in an encounter. Today her only aim in life is to see justice being done to his memory. "He was innocent, write that down," her voice trembles.

For Nishan Singh, whose brother Kulwant Singh, 28, was also killed in an alleged encounter at Kakkar village, the news means an end to a futile search. "But I am still apprehensive about the police, the commission must ensure our safety if it wants us to come forth and speak out the truth," he says.

This is the demand of most people at the camp office which is registering the affected families and helping them file affidavits. "Out of the total of over 2,000 families, we have provided counselling to more than 800 and the process is on," said Amrik Singh, adding that most of the families are hoping to get some compensation.

Khalra's wife hopeful too

PARAMJIT Kaur, wife of Jaswant Singh Khalra, a human rights activist who had collected data regarding the disappeared persons and was allegedly kidnapped by the Punjab police on September 6, 1993, said the NHRC order was a ray of hope for everyone like her. "It's been a long legal haul, and I can finally see some reason for hope."

Deputy Chairman of Punjab Human Rights Organisation Kirpal Singh Randhawa called for compensation of at least Rs 10 lakh besides rehabilitation of the affrected families. He also sought punishment for the police officers involved. "The properties of the police officers who made riches and were promoted for committing these crimes must be confiscated, and criminal cases slapped on them."

THE TRIBUNE

19 JULY 2004

1

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

SARDAR PATEL BHAVAN, SANSAD MARG NEW DELHI-110001

REFERENCE CASE NO. 1/97/NHRC

(Arising out of the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated December 12, 1996 and September 10, 1998 in Writ Petition No. 447/95 and 497/95)

PUBLIC NOTICE

Under the remit of the Supreme Court of India, the National Human Rights Commission is conducting an inquiry into the circumstances leading to the cremation, by the Punjab Police, of 2097 dead bodies as unclaimed/unidentified in the police districts of Amritsar, Majitha and Tarn Taran between June 1984 to December 1994. If, as a result of the inquiry it is found that those 2097 dead bodies or some of them were cremated without following the lawful procedure or that there has been any other violation of human rights in relation to such deceased person, the Commission may in appropriate case or cases consider the question of grant of compensation to the legal heirs/NOK of the deceased.

For the aforesaid purpose, the National Human Rights Commission had invited claims/applications through a public notice from the legal heirs and dependants of the deceased. In response to the public notice 88 claims were received.

From the inquiry conducted so far, the CBI had submitted lists A,B and C furnishing the details of 582 identified dead bodies (List A), 278 partially identified dead bodies (List B) and 1237 unidentified dead bodies (List C). The National Human Rights Commission undertook an exercise to further identify the dead bodies cremated by the Punjab Police. As a consequence thereof, 64 more deceased from the 'List B' and 47 more deceased from the 'List C' have been identified whose names have been added in 'List A' of the identified deceased. Thus, as on date the identity of the 693 cremations under investigation, has been definitely ascertained.

In its order dated 17.03.2004, the National Human Rights Commission observed that for effective determination of issues, including compensation, it is essential to invite claims from next of kin (NOK) of the cremated persons. Hence by this public notice, the National Rights Commission invites NOK of all such persons whose name figure in the CBI Lists A & B (being published along with this notice) to submit their claims, if any, in person or through counsel. NOK of persons, other than those mentioned in Lists 'A' and 'B', who also consider that they have some claim to prefer in respect of their 'unidentified' deceased (List C) may also, likewise submit their claims to the Commission in person or through their counsel. Such NOKs may also refer to 'List C' (being published along with the notice) containing available particulars of the 'unidentified' cremations.

The Commission clarifies that the 88 claimants, who had responded to the earlier notice, need not file fresh claims. A separate communication is being sent to them in connection with processing of their claims.

The claims/applications, giving details/particulars of the complainant, his relationship with the deceased as well as the names and addresses of other legal heirs of the deceased along with the particulars and the facts within the knowledge of claimant relevant for the determination of claim supported by an affidavit duly attested by an Oath Commissioner, should be sent either by Registered Post or submitted in person at the Commission's office at Sardar Patel Bhavan, Sansad Marg, New Delhi within 8 weeks from the date of publication of notice.

Belated and incomplete claims/applications are liable to be rejected summarily. Any false information given either in the claim/application form or in the affidavit would invite prosecution of the claimant.

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL of the Commission this ______ day of May, 2004.

[By Order]
Registrar
NHRC

Reference Case No. 1/1997/NHRC

LIST - 'A'

LIST OF IDENTIFIED DEAD BODIES DIED DUE TO POLICE/PARA MILITARY FORCES ENCOUNTER AND CREMATED BY PUNJAB POLICE

POLICE DIST. TARAN TARAN, PUNJAB

Sl. No.	Name of the Deceased	Date of cremation	Police Stn. & FIR No.
1./001.	Sukhdev Singh @ Sukha, S/o Isher Singh, R/o Tanori Distt. Jind, Haryana	06.07.84	Verowal 256/84
2./002.	Acchar Singh, S/o Tara Singh, R/o Kamboke, Tehsil Patti, ASR	21.07.84	Pattia 223/84
3./008.	Virsa Singh, S/o Harnam Singh R/o SurSingh	10.05.87	Harike 59/87
4./011	Sukhwant Singh S/o Desa Singh R/o Chak Sikkander. PS. Ramdas	05.07.87	Valotha 90/87
5./017	Swarn Singh S/o Mahanta Singh R/o Kamboke, Tehsil. Patti	16.10.87	Jhabal 227/87
6./018	Narinder Singh, @ Pratap Singh, S/o Puran Singh, R/o Bhorsi	18.10.87	Verowal 204/87
7./021	Gurtej Singh, S/o Surinder Singh, R/o Vill. Gumtala	09.11.87	City Tarn Taran

	Khuharka.		
58/149	Resham Singh S/o Tarlok Singh Jat R/o Varlia	31.10.89	Valtoha 108/89
59/150	Balbir Singh @ Beera S/o Hazara Singh R/o Dhulkohna PS Khemkaran	31.10.89	Valtoha 108/89
60/151	Puran Singh @ Tunda S/o Gian Singh Jat R/o Khuharka PS. Patti	31.10.89	Valtoha 108/89
61/152	Gurdev Singh S/o Piara Singh R/o Ratoke	31.10.89	Valtoha 108/89
62/154	Ukuwinder Singh @ Gaddi S/o Harnam Singh Jat R/o Marar	11.11.89	Harike 94/89
63/156	Jagtar Singh @ Jaggi S/o Kundan Singh R/o Mehmoodpura	30.12.89	Khalra 148/89
64./158	Ruldu. S/o Bawa Singh R/o Pringri	13.01.90	Harike 5/90
65./159	Jarnail Singh S/o Kartar Singh, R/o Joura.	24.01.90	City T.T. 16/90
66/160	Paramjeet Singh @ Pamma, S/o Pyara Singh, R/o Kirtowal.Pargat Singh S/o Kartar Singh R/o. Jhugian Kaluwalian	25.01.90	Valtoha 7/90
67/161	Bohar Singh S/o Kashmir Singh Jat, R/o Kalse.	25.01.90	Valtoha 7/90
68/162	Sawinder Singh @ Mohinder Singh S/o Karnail Singh, R/o Rasoolpur.	25.01.90	Valtoha 7/90
69/167	Bhupinder Singh @ Bhola S/o Chanchal Singh, R/o Jandiala Guru.	03.03.90	Sadar T.T. 11/90
70/168	Ranjeet Singh @ Bitu S/o Harbhajan Singh Jat, R/o jandiala Guru.	03.03.90	Sadar T.T. 11/90
71/169	Dilbagh Singh S/o Hari Singh Jat, R/o Dhotian.	03.03.90	Sadar T.T. 11/90
72/183	Kashmir Singh S/o Dharam Singh, R/o Jhandel.	27.05.90	Jhabal 49/90
73/197	Chanan Singh S/o Darshan Singh, R/o Chumlewad.	28.07.90	City T.T. 147/90
74/199	Satnam Singh @ Satta S/o Sewa Singh, R/o Valtoha.	30.07.90	Valtoha 82/90
75/201	Mulagar Singh S/o Hardeep Singh, R/o Mehmoodpura.	02.08.90	Bhikhiwind77/90
76/205	Major Singh S/o Gulzar Singh Jat, R/o Nadhohar.	16.07.90	Harike 49/90
77/206	Gurnam Singh S/o Kartar Singh, R/o Rasoolpur.	16.07.90	Harike 49/90
78/207	Nishan Singh S/o Karnail Singh, R/o Shirpur Seda.	16.07.90	Harike 49/90
79/209	Amar Singh @ Pyara Singh, S/o Ajit Singh Jat, R/o Kalan Satatra.	06.07.90	Valtoha 71/90
80/210	Ranjit Singh @ Rana S/o Harbhajan Singh Jat, R/o Birja.	06.07.90	Valtoha 71/90
81/211	Sardool Singh S/o Dara Singh, R/o Jodh Singhwala.	02.08.90	Bhikhiwind 77/90
82/235	Amarjeet Kaur W/o Sardool Singh, R/o Moh. Nanaksar, Tarn Taran.	22.08.90	City T.T. 160/90
83/246	Darshan Singh S/o Jarnail Singh, R/o Sabra.	10.09.90	Patti 171/90
84/256	Bhinder Singh S/o Gurbachan Singh, R/o Shakhera.	04.10.90	Harike 66/90
85/257	Satnam Singh S/o Bhajan Singh, R/o Baghari.	04.10.90	Harike 66/90
86/258	Sukhdev Singh @ Kala S/o Virsa Singh Jat, R/o Dhulkouna.	11.10.90	Valtoha 109/90
87/259	Mukhtiar Singh @ Mand S/o Amar Singh, R/o Bhuakohnu.	11.10.90	Valtoha 109/90
88/260	Pappu S/o Jarnail Singh, R/o Verowal.	11.10.90	Valtoha 109/90
89/261	Kuldeep Singh S/o Puran Singh, R/o Ran Singhwala.	25.11.90	Valtoha 125/90
90/262	Beer Singh @ Beer Singh S/o Surbaksh Singh, R/o Chatiwind.	25.11.90	Valtoha 125/90
91/263	Gopal Singh S/o Bagh Singh, R/o Maneke.	04.12.90	Valtoha 128/90
92/267	Mangal Singh S/o Joginder Singh Jat, R/o Pakhoke	22.10.90	Sadar T.T. 94/90
93/268	Harbhej Singh S/o Angrez Zingh, R/o Dharar.	22.10.90	Sadar T.T. 94/90
94/270	Gurvail Singh S/o Joginder Singh, R/o Jawende.	22.10.90	Sadar T.T. 94/90
95/278	Sukhwinder Singh @ Sanga S/o Gulzar Singh Jat, R/o Sanga.	03.11.90	Sadar T.T. 106/90
96/279	Baljeet Singh @ Bali S/o Makhan Singh Jat, R/o Khiala.	03.11.90	Sadar T.T. 106/90
97/280	Vikramjit Singh S/o Gopal Singh, R/o Narula	03.11.90	Sadar T.T. 106/90

ਅਜੀਤ

TUESDAY 15 FEB 2005

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਮਿਲੇ

ਜਲੰਧਰ (ਸ਼ਾਹਕੋਟ), 14 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਬਾਂਸਲ)- ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਥਾਣਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਐਸ. ਪੀ. ਓ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਚੜੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਵ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਅਜੀਤ' ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਚੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਥਾਣਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਵਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 406-420 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਚੜੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਚਰਨ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਤਸਵੀਰ : ਅਰੋੜਾ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਚੜੇ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੰਨਮੈਨ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐਫ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਆਦਮਪੁਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜੀਤ

MON 14 FEB 2005

ਖਾਲੜਾ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਚੜਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਸਿੱਧੂ)-ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਚੜਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕੇਸ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਚੜਾ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੜਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਅਗਵਾ ਕੇਸ 'ਚ ਬਚੜਾ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਹੈ।

ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 100 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 50 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 50 ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਯੂਸੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੇਤੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਅਮੁੱਕ ਬਹਿਸ' ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਫਰਵਰੀ, (ਸਿੱਧੂ)-ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ:) ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ 'ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਡੀਬੇਟ ਆਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਜ਼' (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਅਮੁੱਕ ਬਹਿਸ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਸ 270 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ, ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ: ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। ਤਸਵੀਰ : ਨਿਰਮਲ ਸਟੂਡੀਓ

ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 24 JAN 2005

ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਟ ਬਾਗਾਂਵਾਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 9 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇਥੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨਜ ਰਾਈਟਸ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੈਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਜੀ., ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸਾਬਕਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਐਮ.ਏ., ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ. ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ,

ਬਾਕੀ ਸਫਾ 8 'ਤੇ

✡ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ✡ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਰੇਆਮ।

The Indian EXPRESS
CHANDIGARH ■ MONDAY ■ JANUARY 24, 2005

'False cases are being registered against them to prevent them from deposing in court'

Khalra case witnesses face 'intimidation'

EXPRESS NEWS SERVICE
CHANDIGARH, JANUARY 23

THE Khalra Mission Committee (KMC) today alleged that the witnesses in the Khalra "abduction and murder" case were being prevented from deposing before the court by registering of "false cases" against them. Releasing a copy of the letter written to the Prime Minister as well as the Chief Minister, human right activists demanded that the police officers accused of murdering Khalra should be removed from active duty till the hearings were completed.

Addressing a joint press conference here today, 15 human rights activists said this development has occurred in the past two months, ever since the High Court directed that the trial should be completed in six months.

Jaswant Singh Khalra, who had brought to light the case of illegal cremations in Amritsar was allegedly abducted and killed in September 1995 by nine police officers.

Narrating the sequence of [illegible] Singh Bains, said a star witness Kikker Singh was "neutralized" by registration of five criminal cases against him and his father. He spent two-and-a-half years in jail, and had turned hostile.

The second case involved Kirpal Singh Randhawa, who was arrested in a rape case. "The circumstances were far too telling which convinced the judge that it was a false case", the letter written to the PM says.

As and when his turn came for providing evidence, another case was registered against him. Kirpal has already complained that the IG of Patiala Range, Rajinder Singh was threatening him.

Rajiv Singh Randhawa, who had recognised some of the killers was booked in a dacoity case but had to be discharged due to public outrage. Senior journalist Dalbir Singh added that the FIR against Rajiv has already been declared as "false" by the Punjab State Human Rights Commission.

Advocate Rajwinder Singh Bains said the method of harassing witnesses has emerged only during the past two months, ever since the High Court directed that the trial should be completed within six months.

Besides Paramjit Kaur, wife of Jaswant Singh Khalra, those who addressed the press conference included Dr Gurdarshan Singh Dhillon, Inderjit Singh Jaijee and Baljit Kaur of MASR, Amar Singh Chahal of Lawyers for Human Rights, Maj Gen (retd.) Narinder Singh, Gurtej Singh, former IAS, Rajinder Singh of Khalsa Panchayat, Kanwarpal Singh Dhami of Gur Asra Trust, and Jaspal Singh Dhillon, human rights activist.

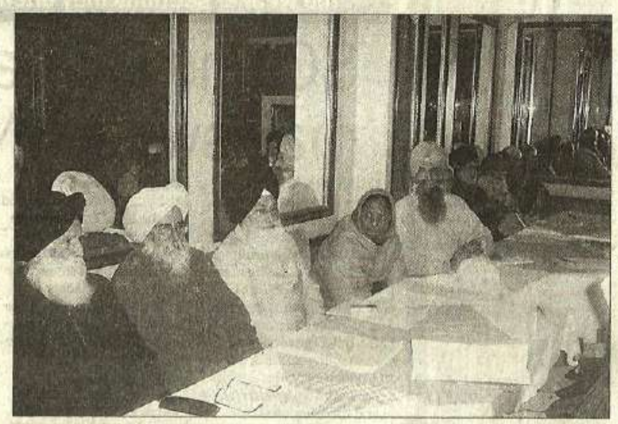

Human right activists holding a press conference in Chandigarh on Sunday. *Express photo*

Accused cops still posted in Amritsar

THOUGH the Supreme Court had ordered that the accused police officers should not be posted in Amritsar, Tarn Taran or in adjoining districts, they continue to be posted there. The KMC cited the names of Jaspal Singh, DSP, Phagwara, Rachpal Singh, SHO, Bhikhiwind and Jasbir Singh, SI at Jandiala Guru. Two of the accused, Ajit Singh Bains and Ashok Kumar have died during the pendency of the trial.

INDIAN EXPRESS.
24 JAN 2005

ਅਜੀਤ 24 JAN 2005
MONDAY

ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ)-ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਲਟਕ ਕੇ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸ: ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਨਾਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ : ਟੀ. ਐਸ. ਬੇਦੀ

(ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 13 ਕਾਲਮ 3)

ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ

(ਸਫ਼ਾ 1 ਦੀ ਬਾਕੀ)

ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਚਲਾਨ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ 90 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਗਵਾਹ ਹੀ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਥੇ ਸਰਦਾਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2004 ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਲਈ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਆਈ. ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ. ਜੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ: ਬੈਂਸ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਖਾਲਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ: ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਨਾਪਿੰਡ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾਅ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਅ ਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ 4 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਅ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਗਵਾਹ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ ਆਈ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ- ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਡਾ: ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਨਾਪਿੰਡ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਬਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ।

ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ

MON 24 JAN 2005

ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਖਾਲੜਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/23 ਜਨਵਰੀ/ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ

ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਖਾਲੜਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ), ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਖਾਲੜਾ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 12 ਗਵਾਹ ਭੁਗਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ

(ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 2 'ਤੇ)

ਸਬੰਧਤ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸ ਐਚ ਓ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਫਗਵਾੜਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਉਪਰ 5 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਢਾਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉੱਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ ਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।

ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੜਾ ਜਾਂਚ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੜਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1995 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ
24 JAN 2005

ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਠੁਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਬੈਂਸ

ਆਈ. ਜੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਏ. ਐੱਸ. ਪਰਾਸ਼ਰ)-ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਅਪਹਰਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਠੁਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ. ਜੀ. ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਦਾ ਇਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਹਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।

ਖਾਲੜਾ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਾਲੇ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 9 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 1996 ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਇੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਅਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਖ ਗਵਾਹ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਗਵਾਹ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਰਾਜੀਵ ਇਕ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2004 ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।

PUNJABI TRIBUNE 24 JAN 2005

ਆਈ.ਜੀ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)-ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਾਜੀਵ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ 'ਚ ਆਈ.ਜੀ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਹੂਮ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਤਿੰਨ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

'Police threatening witnesses'

Khalra Committee accuses govt of violating SC order by posting accused in Tarn Taran

HT Correspondent
Chandigarh January 23

THE KHALRA Committee today accused the Punjab Police of pressurizing witnesses in the Jaswant Singh Khalra murder case to turn hostile and said the state government had violated the Supreme Court orders by posting the accused officials in Tarn Taran police district before the verdict was delivered.

Addressing a press conference here, committee members, including Justice Ajit Singh Bains (retired) and Khalra's wife Paramjeet Kaur, alleged that the police had been registering false cases against the witnesses to mount pressure so that they turned hostile.

Paramjeet Kaur said that the state government had posted the accused police officials within Tarn Taran police district despite the apex court's orders that no officer could be posted in the district till the verdict was delivered. "Yet the government has posted two SHOs and a DSP there. These officers are now instrumental in registering cases against witnesses," she said.

Bains said while five cases had been registered at different police stations against Kikkar Singh, another prime witness in the case, Kirpal Singh, had been booked in a fake rape case. Similarly, he said, witness Rajiv Singh was being pressurised to turn hostile and a criminal case had been registered against him.

Bains said the cases were "purely and absolutely fake" and had fallen flat in the court. "This proves that the police had mala fide intentions. Kirpal Singh has been acquitted and the Punjab State Human Rights Commission has fined the police Rs 50,000," he said.

He said that Khalra had been picked up from his house by former Tarn Taran SSP A.S. Sandhu in September 1995 and was taken to a house at Manawal in Amritsar, where senior police officials met him before he was murdered. The case is pending with the CBI.

Hindustan Times
24 Jan 2005

THE TRIBUNE

24 JAN 2005

Khalra murder case: rights body writes to PM

TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, JANUARY 23

Accusing the state police of intimidating witnesses in the Jaswant Singh Khalra murder case, which was lodged against five police officers in 1995, human rights organisations here have written to Prime Minister Manmohan Singh and Punjab Chief Minister Amarinder Singh, demanding the immediate removal of IG (Patiala Range) Rajinder Singh for allegedly harassing and intimidating the witnesses in the case

Human rights activist Jaswant Singh Khalra was allegedly abducted on September 6, 1995, by policemen and and then killed. The accused in the case included the then SSP Ajit Singh Sandhu, who committed suicide about five years back, two DSPs, three SHOs and two low rank policemen. The case is presently being heard in the Patiala Sessions Court.

The letter has been signed by Khalra Mission Committee (KMC) Chairman, Harmandeep Singh, Punjab Human Rights Organisation (PHRO) Chairman Justice Ajit Singh Bains, and members of the Lawyers for Human Rights International (LHRI) and other rights bodies activists.

"No rule of law prevails as the state police is harassing the witnesses by not only lodging false cases against them, but also by verbally threatening them not to appear at the hearings of the case," Justice Bains told reporters at a press conference here today.

He also pointed out that the accused police officers had not been removed from Amritsar and Tarn Taran districts despite a Supreme Court order in this regard. The CBI had accused the seven policemen of abducting and killing Jaswant Singh. One of the key accused police officers, DSP Jaspal Singh, was still posted in Amritsar city, he added.

The letter alleged that one of the key witnesses, Kikkar Singh, was pressurised by the state police to be neutral in the court proceedings of the Khalra case as he and his father had been implicated in five false cases.

The letter also pointed out that the Punjab State Human Rights Commission (PSHRC) had already asked the state government to pay a compensation of Rs 50,000 to one of the witnesses, Rajiv Randhawa, against whom a false case was lodged by the Amritsar police.

Khalra's wife Paramjit Kaur, who was also present at the press conference, said it took the Patiala Sessions Court two and a half years to record her statements. "The witnesses in the case are facing tremendous physical and mental pressure from the Punjab police for not appearing in the court."

PUNJABI TRIBUNE 16 DEC 2006

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼

ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਦਸੰਬਰ

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਐਸ. ਭੱਲਾ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਭੱਲਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 2 ਜਨਵਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਤਿਵਾਦ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਭੱਲਾ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1245 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਭੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਭੱਲਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ 26 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਭੱਲਾ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ 45 ਹੋਰ ਕੇਸ ਸ੍ਰੀ ਭੱਲਾ ਕੋਲ ਮੰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

TIMES OF INDIA 16 DEC 2006

Commission holds first hearing on missing victims

TIMES NEWS NETWORK

Amritsar: The one-man commission formed to identify 814 victims of militancy, who were allegedly killed in police encounters during the heydays of militancy, held its first hearing here on Friday.

But the kin of some of the victims who had also come here to meet Justice K S Bhalla, retired judge of Punjab and Haryana High Court heading the commission, were seen a dejected lot as they could not narrate their tale of woes in front of him. Perhaps, they never knew that it was the first hearing of the commission and that the commissioner was supposed to meet activists of human rights organisations and other government authorities, but not the victims' kin.

Rattan Singh, whose son Balwant Singh alias Joga was allegedly killed in an encounter with police in 1988, had come here after reading the advertisement NHRC had placed in newspapers asking people to submit claims regarding their missing relatives. All that Rattan Singh wants is to restore the dignity of his son. He sees hope but the wait is proving too long.

NHRC had earlier invited claims from the relatives of 814 victims to fix their identities with the help of concerned authorities including petitioners so as to give them monetary relief. The report is to be submitted with NHRC by June 30, 2007. NHRC had earlier awarded Rs 1.75 lakh compensation each to the next of kin of 1,051 missing persons. The Commission had come to a conclusion that out of 2,097 missing persons, 194 deceased were admittedly either in the custody or deemed custody of police authorities immediately before their death and cremation. Believing that the police had failed in their duty to safeguard persons who were in custody of police, NHRC extended a compensation to Rs 2.5 lakh each in case of these 194 victims.

HINDUSTAN TIMES 15 DEC 2006

Justice Bhalla probe panel begins work

To hear families in Amritsar today

Kuldeep Mann
Amritsar, December 14

ILLEGAL CREMATIONS

IN WHAT is seen as the last hope for families of people illegitimately cremated by the Punjab Police during the days of terrorism, National Human Rights Commission (NHRC)-designated Commissioner Justice K.S. Bhalla (retd) has started his inquiry into the undisclosed cremation of 814 persons.

The NHRC in October this year had appointed Justice Bhalla as commissioner to identify the remaining 814 bodies of the 2,097 regarding which human rights activist Jaswant Singh Khalra had collected evidence of having been cremated without following lawful procedures. The matter has been hanging fire for a decade. Justice Bhalla would be camping in Amritsar on December 15 and 16 to hear complaints regarding abductions, fake killings and secret cremations by the police during the height of militancy.

Human rights activists, including Ram Narayan, Navkiran Singh and Khalra Mission Organisation (KMO) chief Bibi Paramjit Kaur, are expected to depose before the one-man commission.

Justice Bhalla is expected to take up inputs collected by Jaswant Singh Khalra, who after he gathered evidence on the

continued on page 7

Justice Bhalla probe panel begins work

continued from page 1

secret cremations was himself eliminated by the police. He had collected proof of at least 2,097 persons having been illegally cremated at two cremation grounds in Amritsar and one in Tarn Taran.

The victims had allegedly been killed by the police in fake encounters.

After Khalra, his wife Paramjit Kaur and other activists moved the NHRC, which referred the case to the CBI. However, the premier investigation agency uncovered little beyond what Jaswant Khalra had exposed. Of the 2,097 cases, 194 families have been awarded compensation of Rs 2.5 lakh each, while the NHRC has recommended relief of Rs 1.75 lakh each in 1,051 cases. In the remaining 814 cases, details like addresses and dates of FIR are not available, which Justice Bhalla is expected to work on.

Paramjit Kaur told Hindustan Times that all victims' families were in touch with them, and if required, they could be produced before the commission.

She added: "The NHRC-designated commission is restricting its investigations to the secret cremations carried out in only three cremation grounds. What about the fake encounters and illegal cremations that took place in the rest of Punjab? And what about the cases in which bodies were thrown into rivers and canals?" Claiming to have the support of global organisations like Amnesty International, Ensaaf and Asia Watch, Paramjit said they would do their best to see every cop guilty of fake encounters behind bars.

Ajit 2 FEB 2006

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਫਰਵਰੀ (ਲਾਂਬਾ)- ਖ਼ਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਸ: ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸ: ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਨਿਹਾਲਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਡਾ: ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਸ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।

HINDUSTAN TIMES 16 DEC 2006 (SATURDAY)

Justice Bhalla urged to expand scope

Rights activists want killings carried out to rehabilitate 'police cats' probed too

uldeep Mann
mritsar, December 15

VEN AS Justice K.S. Bhalla etd) — appointed Commission r by the National Human ights Commission (NHRC) to dentify 814 persons illegally remated by the Punjab Police — pened the hearings here today, uman rights activists urged im to also seek details from the unjab government regarding eople allegedly killed to reha ilitate more than 300 police in rmers.

Well-known human rights ac vist Ram Narayan Kumar said e inquiry would be incomplete l Justice Bhalla also procured tails on the killings allegedly rried out by the police to cov for former militants and in rmers under an undisclosed licy to protect them.

He raised the issue on the ba s of admissions made by Pun b DGP S.S. Virk — and subse ently endorsed by Chief Min ter Capt Amarinder Singh — garding the rehabilitation of ound 300 such informers, re rred to as "police cats".

Kumar, accompanied by Khal Mission Organisation chief ramjit Kaur and Lawyers for uman Rights general secretary avkiran Singh, also urged Jus ce Bhalla to expand the in iry to include the entire state reveal the actual number of illegal killings by the police.

Justice Bhalla, however, gave no assurances, stating that as per NHRC orders, his role was limited to collecting details on the as-yet unidentified 814 persons who were allegedly cremated at two cremation grounds in Amritsar and one in Tarn Taran. After hearing a number of people through the day, Justice Bhalla fixed January 2 as the next date for hearings. He also asked the police to provide him copies of the FIRs registered in all the 814 cases.

HT PHOTOS

Khalra Mission Organisation chief Paramjit Kaur and Lawyers for Human Rights general secretary Navkiran Singh after a hearing to identify illegally cremated persons and Justice J.S. Bhalla (right) stepping out of the court in Amritsar on Friday.

According to sources, even accomplishing the limited task assigned is not be likely to be easy for Justice Bhalla, as families of only 203 of the 814 victims have come forward so far, despite notices taken out by the NHRC in leading newspapers.

Meanwhile, after verifying the antecedents of some more missing persons, the state government has reportedly cleared the cases of another 45 victims, whose families would be considered eligible for the Rs 1.75 lakh compensation recently awarded by the NHRC for kin of illegally cremated persons.

Ram Narayan Kumar said it was unfortunate that the long legal battle fought by them with utmost commitment had been reduced to a mere struggle for collecting monetary compensation.

"All government agencies seem unanimous in their approach that revealing true information in this case would be detrimental to national interests. Even a statuary body like the NHRC is under pressure from government agencies, because of which it has failed to deliver in this case," he said, adding that even the CBI had done nothing to reveal the complete truth.

The human rights activists said they would formally present their case before Justice Bhalla through senior counsels.

'MHASI' LAND SCAM

ਅਜੀਤ (SAT) 16 DEC 2006

ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਦਸੰਬਰ (ਲਾਂਬਾ)- ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 814 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਸ. ਭੱਲਾ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਸਮੇਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ 814 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 2500 ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1051 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 1857 ਦੇ ਲਗਪਗ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1051 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 45 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 814 ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਲਈ ਮੁੜ ਉਪਰਾਲੇ ਅਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

HINDUSTAN TIMES 15 DEC 2006

Justice Bhalla probe panel begins work

To hear families in Amritsar today

Kuldeep Mann
Amritsar, December 14

ILLEGAL CREMATIONS

IN WHAT is seen as the last hope for families of people illegitimately cremated by the Punjab Police during the days of terrorism, National Human Rights Commission (NHRC)-designated Commissioner Justice K.S. Bhalla (retd) has started his inquiry into the undisclosed cremation of 814 persons.

The NHRC in October this year had appointed Justice Bhalla as commissioner to identify the remaining 814 bodies of the 2,097 regarding which human rights activist Jaswant Singh Khalra had collected evidence of having been cremated without following lawful procedures. The matter has been hanging fire for a decade. Justice Bhalla would be camping in Amritsar on December 15 and 16 to hear complaints regarding abductions, fake killings and secret cremations by the police during the height of militancy.

Human rights activists, including Ram Narayan, Navkiran Singh and Khalra Mission Organisation (KMO) chief Bibi Paramjit Kaur, are expected to depose before the one-man commission.

Justice Bhalla is expected to take up inputs collected by Jaswant Singh Khalra, who after he gathered evidence on the

continued on page 7

Justice Bhalla probe panel begins work

continued from page 1

secret cremations was himself eliminated by the police. He had collected proof of at least 2,097 persons having been illegally cremated at two cremation grounds in Amritsar and one in Tarn Taran.

The victims had allegedly been killed by the police in fake encounters.

After Khalra, his wife Paramjit Kaur and other activists moved the NHRC, which referred the case to the CBI. However, the premier investigation agency uncovered little beyond what Jaswant Khalra had exposed.Of the 2,097 cases, 194 families have been awarded compensation of Rs 2.5 lakh each, while the NHRC has recommended relief of Rs 1.75 lakh each in 1,051 cases. In the remaining 814 cases, details like addresses and dates of FIR are not available, which Justice Bhalla is expected to work on.

Paramjit Kaur told Hindustan Times that all victims' families were in touch with them, and if required, they could be produced before the commission.

She added: "The NHRC-designated commission is restricting its investigations to the secret cremations carried out in only three cremation grounds. What about the fake encounters and illegal cremations that took place in the rest of Punjab? And what about the cases in which bodies were thrown into rivers and canals?" Claiming to have the support of global organisations like Amnesty International, Ensaaf and Asia Watch, Paramjit said they would do their best to see every cop guilty of fake encounters behind bars.

ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ

21-27 Nov 2006

ਹੈ। ਬਾਣੀਆਂਵਾਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 'ਕੁੱਲਨਾਸ' ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ:

1. 'ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ', ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜਾਉਣ, ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੱਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕੌਣ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

2. ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

3. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਅਕ, ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

4. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

5. ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਪੱਖੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ' (ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ) ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

6. ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੁਲਿਸੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ: ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਲਾਸ਼ੋ:- ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ॥

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਓ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਓ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਖੋਹ ਕੇ ਨਰਦਈ ਲਫੰਗਿਆਂ, ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਅਣਪਛਾਤੇ' ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਚਮਚੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਝੂਠੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 1947 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਏਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਭਾਵ 'ਅਕਾਲ ਤਖਤ' ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਅੰਨੇ "ਧਾਰਮਕ" ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ-ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਟਕਸਾਲੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਰ "ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰੋ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਰਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋ ਅਤੇ ਮੀਰਮਨੂੰ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬਾਬਰ, ਅਬਦਾਲੀ ਆਦਿ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਘਲੂਘਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਨੇੜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। ਕੇਸਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਟੋਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਰਾਜਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ॥

- ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ

PUNJABI DUNIYA

CONT....

21-27 NOV 2006

ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੋਮੀ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਹੈ, ਜਿਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਾਹ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਿੱਖ 'ਕੁੱਲਨਾਸ' ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 2097 'ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ' ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾ ਲ ਲੱਭ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਦਸ ਸਾਲ ਮਗਰੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪਿਛੋਂ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲੜੇ ਦੀ ਢੂੰਢ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਖ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਲੱਖ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਪੌਣੇ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਸ਼, ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਸਾਈਪੁਣੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸੀ ? ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ? ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕਿਥੋਂ ਤਾਈ ਠੀਕ ਸਨ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸਯੋਗ ਸੰਸਥਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਉ ਤਾਂ ਸੱਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਤਲ, ਚੋਰ ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਿਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਾਮਰੇਡ ਅਤੇ ਬਾਦਲਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਜਸੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰਕਵਾਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲਨਾਸ ਦੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਹਦੀ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 1991-92 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ "ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ/ਅੱਤਵਾਦੀ" ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਤਮਗੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਹਜ਼ਾਰ 684 ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ 12. ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ 22 ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ 576 ਇਸਪੈਕਟਰ 1365 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 2875 ਏ.ਐਸ.ਆਈ, 8589 ਹੌਲਦਾਰ ਅਤੇ 28245 ਸਿਪਾਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਤਲ ਬਹੁਤੇ "ਸਿੱਖ" ਸਨ।

ਖਾਲੜਾ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਦਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੌਲਦਾਰ,ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁਣਸ਼ੀ ਪਾਸੋਂ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਆਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ, ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ, ਕਮਲ ਨਾਥ, ਅਰੁਨ ਸਿੰਘ, ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਆਦਿ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ, ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ, ਓ.ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਮਚਿਆ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਰੈਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਤੇ ਕੁਟਾਪੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ? ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚੁਆਤੀ ਲਾਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸਮੇਤ ਉਸੇ ਅਗਨ ਭੱਠੀ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਨੇਕ ਆਰਥਕ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੱਜ ਤਾਈ ਵੀ ਖੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾੜ੍ਹੀ, ਕੇਸਾਂ, ਪਗੜੀ ਤੇ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਰਵਰੀ 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਲਿਪਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ

ਵਲੂੰਧਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਓ!

ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ?

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 21-27 Nov 2006

ਜਦ 'ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ' (ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ) ਬਣੇ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ

ਚੰਗੇ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਅਣਖੀ ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਗਰਦਾਨ "ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ" ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ 'ਤੋਂ ਝੂਠ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪੈੜ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ, ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾ ਪਾਸੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ/ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦੀ ਹੋਈ, ਹਰ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ
ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ?

ਇਹ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਿੱਖ (ਮਰਦ, ਇਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ) ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 1984-94 ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਿੱਲੀ , ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 'ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ' ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਟੇਟ' ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰਕੂ

[illegible]

ਅਜੀਤ 5 FEB 2007

ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਆਪਣੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਐਸ. ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਸਵੀਰ : ਚਮਨ ਸਭਰਵਾਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤਕ 35 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਸਵ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਸ. ਭੱਲਾ (ਰਿਟਾ:) ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ: ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾਇਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਡਾ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ: ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਸ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 3 ਮਾਰਚ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ: ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ 'ਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Hindustan Times 9 Oct 2007

HC upholds 5 cops' conv

ASI acquitted of murder of human rights activist, who we

HT Correspondent
Chandigarh, October 8

THE PUNJAB and Haryana High Court today upheld the conviction of Deputy Superintendent of Police Jaspal Singh and four other cops in human rights activist Jaswant Singh Khalra murder case.

A Division Bench comprising Justice Mehtab Singh Gill and Justice A.N. Jindal, however, acquitted Assistant Sub-Inspector Amarjit Singh and directed that if in custody he should be released.

Along with Jaspal Singh, the cops whose conviction has been upheld are Satnam Singh, Surinder Pal Singh, Jasbir Singh and Prithipal Singh.

In a 25-page order, the Bench observed, "Taking the statement of witnesses in totality, we have no hesitation in coming to the conclusion that Jaswant Singh Khalra was picked up from his house at the instance of SSP Ajit Singh Sandhu by appellants Jaspal Singh, Satnam Singh, Surinder Pal Singh, Jasbir Singh and Prithipal Singh. He was tor-

File photo of Jaswant Singh Khalra's wife in front of her husband's portrait.

tured at Jhabal police station and shot dea there. Finally, his body was disposed of b them near the Harike Bridge on Sutlej river

Khalra had disappeared in 1995.

The Bench also observed that a number defence witnesses had been examine "Their testimony and veracity were gon into, but ultimately it comes out that the were untruthful witnesses, who were goin out of the way to help the appellants. Adv cate Gurjit Singh Kahlon went out of th way to procure a false affidavit under threa from prosecution witness Kuldeep Singh."

The Bench observed that the motive b hind the commission of the offence had bee spelt out not just by one, but a number of wi nesses, including retired Justice A.S. Bains

The Judges observed: "All these witnesse have stated that Khalra was a human right activist and was looking into the deaths of in nocent persons, who had been killed in fals encounters and their bodies cremated in th districts of Amritsar and Tarn Taran."

Referring to the importance of key wi ness Kuldeep Singh, a former Special Polic

THE TIMES OF INDIA 9 OCT 2007

High court upholds DSP's life term

SI Let Off, Punishment of 4 Increased

TIMES NEWS NETWORK

Chandigarh: The Punjab and Haryana High Court on Monday acquitted sub-inspector Amarjit Singh, upheld life term for DSP Jaspal Singh and enhanced the punishment of four others in the custodial death case of Amritsar-based human rights activist Jaswant Singh Khalra in 1995.

Division bench of justice Mehtab Singh Gill and AN Jindal, accepted the appeal of sub-inspector Amarjit Singh acquitting him of the charges of involvement in Khalra's custodial killing.

He was convicted and sentenced to life imprisonment by the special CBI court, Patiala, on the basis of investigation conducted by the CBI on the directions of the Supreme Court.

Dismissing the appeals of five other police officials, including DSP Jaspal Singh, the bench upheld the conviction and sentence of DSP Jaspal Singh, who is serving life imprisonment in Central Jail, Patiala.

Meanwhile, the court ordered to enhance punishment of rigorous imprisonment of seven years each awarded by the trial court in the case of four police officials — Satnam Singh, Jasbir Singh, Surinder Pal Singh and Prithipal Singh — and fixed the case for further hearing on Wednesday.

Two of the accused — Ajit Singh Sandhu the then superintendent of police, Tarn Taran, and Ashok Kumar, deputy superintendent of police — are no longer alive as Sandhu committed suicide while the other died a natural death.

Plea against Gill

The court referred an appeal filed by Paramjit Kaur Khalra, wife of human rights activist, for summoning and prosecuting former Punjab police chief KPS Gill, saying there was evidence against his role in the liquidation of her husband by the police. The latter issue will be heard by another bench as this bench hears appeals in criminal cases only. The matter would now stand referred to the chief justice, who would assign the same to another bench.

KHALRA CASE

ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ: ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਰੀ

(ਸਫਾ 1 ਦੀ ਬਾਕੀ)

ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ., ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 365 ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਧਾਰਾ 302, 120-ਬੀ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਜੀਤ
9 OCT 2007

ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ

(ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 2 ਕਾਲਮ 7)

ROZANA SPOKESMAN

11 DEC 2007

'.ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ'

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਲੋਟ-ਮੁਕਤਸਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਧਰਨਾ

ਮਲੋਟ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ) : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ ਨੇੜੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੜਕ ਉਪਰ ਹੀ ਦਿਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਾਲੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ

ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 2 'ਤੇ

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ। (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ)

'.ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ'

ਖ਼ਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਗ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਮੁਕਤਸਰ-ਮਲੋਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਫ਼ੋਟੋ : *ਖ਼ਾਲਸਾ*

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਚੋਂ ਜਦ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੁਪਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਪੀੜਤ ਧਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤਕ ਦਿਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੋਰ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਏਵਾਲ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਪੁਰੀਆ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ, ਚਿਮਨ ਲਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ 9 OCT, 2007

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ

ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਮੇਸ਼ ਕਪਿਲਾ) : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ 1995 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਏ.ਐਨ. ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਅੱਜ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੀਐਸਪੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ।

ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ

TIMES OF INDIA

MONDAY SEPT. 10, 2007

'Extortion is a terror hangover'

Sanjay Sharma | TNN

Policing rogues

According to the figures provided by Punjab police, in the last three months alone Punjab police has slapped as many as 87 cases against its 115 rogue policemen for their involvement in criminal activities. The wolves in khaki have been charged with drug peddling, assault, threat and graft. As if stealing was not enough, Punjab cops have graduated to bank robberies and dacoities.

Chandigarh: Leading human rights lawyer Amar Singh Chahal moved the Punjab and Haryana High Court seeking action against tainted police officers and urged CBI, Central Vigilance Commission and anti-corruption wing in the prime minister's office to crack down on such officers.

Chahal says since the setting up of Punjab State Human Rights Commission, 90% complaints have been against police officers who extort money from the people. Extortion is a hangover of terrorism days, he adds.

Paramjit Kaur Khalra of Khalra Mission, a human rights body fighting for justice to around 2,000 missing people in Punjab, says they have a list of 150 officers who made money and indulged in killings during militancy. Instances of police extorting money during the black days of militancy were plenty. Organisation's patron Dalbir Singh adds one of his relatives was killed for his failure to deliver money to the police.

Rajwinder Singh Bains, a leading criminal lawyer, says corruption corroded the Punjab police as it had powers of intelligence agencies. Sadly, the situation has not changed.

Bains says his client Narain Singh Chaura, who was an accused in the jailbreak case, gave him a list of 20 people who were shown killed and were living under changed identities. They are still active and their controllers are retired officers. These people like Sukhi, whose house was raided on Sunday, are operating for these officers to circumvent the law and amass property for them. They should have been deactivated and the officers who handled militancy should have gone through a scrutiny before they are given a peacetime posting, adds the lawyer.

Prof SL Sharma, course director of Chandigarh-based Institute for Correctional Administration that reforms police forces, says militancy provided the most conducive environment to the corrupt. The malaise can only be curbed by enlarging the scope of the Supreme Court judgment against candidates in elections. Every officer should declare his assets — first at the time of joining duty and then every subsequent year. The officers who played a major role during militancy should be asked to go through an additional scrutiny before a specially set-up commission, he adds.

Police officers opposed to the heroes of militancy say militancy fighters have a network of property dealers who are closest to them.

ROZANA SPOKESMAN 2 SEPT 2007

ਸ.ਫ਼ਾ ਇ

ਹਾਂ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ

ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਜੜ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦਿਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਤਮ ਪਲਾਂ ਤਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ।

ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੁੱਝ ਆਧਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਸੰਪਰਕ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ। ਛੇ ਜੂਨ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ (ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ) ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਰਲਿਨ ਰੇਡੀਉ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਮੀਮਾ ਕਢਿਆ। ਬਰਲਿਨ ਰੇਡੀਉ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਤਦ ਵਿਖਾਈ ਦਿਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਿਛੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਥੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਕਾਲੀਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸ.ਪੀ. (ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.), ਸਿਟੀ, ਸਨ। ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੌਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ (ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ) ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਪਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਸੁਖਦੇਵ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਪੰਡਤ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਲੈ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਫ਼ੋਟੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਲੈਕ-ਵਾਈਟ ਫ਼ੋਟੋ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਲੱਤ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥ ਪਥ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਡੌਲੇ ਕੋਲ ਕੁੜਤੇ ਉਪਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ੋਟੋ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨੂੜ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਟੋ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢੇ 'ਡਿਗਨਿਟੀ' ਨਾਂ ਦੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਲੇਖ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਛਾਪਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਇਹ ਸੀ: "ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਕਤਲ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਤਾ।

ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤੱਥ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਫ਼ੌਜ, ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਪਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇ ਐਮ.ਕੇ. ਧਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, "ਓਪਨ ਸੀਕਰਿਟਸ" ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ "ਦਿੱਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ" ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿ
ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਰ
ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁਰ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫਿੱਕ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇ
ਆਧਾਰ ਰਹਿਤ ਹਨ
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ
ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਸਥਿ
ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਾਂਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ
ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿ
ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ
ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣ
ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ

ROZANA SPOKESMAN

29th Aug 2007

ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ

ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ!

ਜਲੰਧਰ, 28 ਅਗੱਸਤ (ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ) : "ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ 'ਸਰਚਿੰਗ ਆਈ' ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਖ਼ਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। (ਡੋਗਰਾ)

ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਾਟਕ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਿਆ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਤੀਜੀ ਏਜੰਸੀ' ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਸੂਰੀਆ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਤੰਬਰ 1984 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀਅਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ 'ਖਾਲੜਾ ਦਿਵਸ' ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ

ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 13 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਇਕ ਲੇਖ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ 'ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼' ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਤਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਖਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਥਰਡ ਏਜੰਸੀ' (ਤੀਜੀ ਏਜੰਸੀ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਸੂਰੀਆ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਡੀ. ਕੇ. ਜੈਨ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਗਰੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ 'ਦੀ ਸਰਚਿੰਗ ਆਈ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਿਰੁਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ 18 May 2007

ਜਲੰਧਰ, 17 ਮਈ (ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਲੰਦ) : ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਬੁਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੇ ਐਮ ਓ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਲੀ ਵਿਚ 3000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਰਾਏ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ 5000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 25000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਂਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਰਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

'ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਯਾਦਗਾਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ'

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ 25,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਮੁਨਾ ਕੰਢੇ ਬਣੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟ ਸਾਹਮਣੇ 61 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫ਼ੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿੱਟਾ ਇਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰੇ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਨਿਆਲਾ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਲੀ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਆਦਿ ਨੇ ਹਿਸਾ ਲਿਆ।

ਅਜੀਤ

13 MAY 2007

ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 16 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਮਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਭੱਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 16 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਸ: ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ: ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ 22 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ

(ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 15 ਕਾਲਮ 7)

ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ...

(ਸਫਾ 1 ਦੀ ਬਾਕੀ)

ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਐੱਸ. ਸੂਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ 4 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਸਕਾਰੇ ਜਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੁੜੀਵਲਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਣਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਲੇਵਾਲ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੋਹਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਠੱਠੀ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜਵੰਦੇ ਕਲਾਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੱਦ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਭੂਰਾ ਕੋਹਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਜੋਹਲ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸਭਰਾ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਨਾਰਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ 2097 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 1051 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ 232 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 814 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਸ. ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 41 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ

SAT. 12 MAY 2007

ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ : ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਜਲੰਧਰ, 11 ਮਈ (ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਧਵਨ)-ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ।...(ਫੋਟੋ ਠਾਕੁਰ)

ਪਲਾਸੌਰ ਅਤੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਕ ਪਾਸੜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1200 ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੜੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਵਰਗੇ 300 ਕੈਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਟਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

Sat., 12 MAY, 2007

ROZANA SPOKESMAN

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ : ਖਾਲੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਜਲੰਧਰ, 11 ਮਈ (ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਲੰਦ) : ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਨੇਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 'ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਟੇਟ' ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਸੀਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸ. ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ, ਅਖੌਤੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲਨਾਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੁਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ 12 ਦਸੰਬਰ 1996 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਇਕ ਜੱਜ ਪਾਸੋਂ ਝੂਠੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਵਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਖਾਲੜਾ ਹੁਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀਂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1200 ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀ ਮੀਸਾ, ਨਾਸਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੈਕੜੇ ਕੈਂਟਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।

ਖ਼ਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਫ਼ੋਟੋ : ਭੰਗਰਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 12 ਮਈ 2007

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜਲੰਧਰ, 11 ਮਈ

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਕੈਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਅਤੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ 2097 ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1200 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ 12 ਦਸੰਬਰ 1996 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ !

ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਮਈ (ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਸ. ਭੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੂਨ 2007 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 814 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਆਖ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ 1991-92 'ਚ 41,684 ਅਤੇ 93-94 'ਚ 56,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕੰਮ 'ਚ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 12 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ., 22 ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ., 576 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 1365 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 2875 ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ., 8589 ਹਵਲਦਾਰ ਅਤੇ 28,245 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿਵਾਈਆਂ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪਤੀ ਮਰਹੂਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1995 'ਚ ਤਿੰਨ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 25,000 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ 2095 ਕੇਸ ਇਕੱਲੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ 814 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਸ. ਭੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ 8 May 2007

Rozana Spokesman 4 May 2007

ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਹੈਲੀਫ਼ੈਕਸ (ਕੈਨੇਡਾ) 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਮਈ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੁੰਡਾਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਖਾੜਕੂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕਰਨਲ ਗੁਰਬੀਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਲੀਫ਼ੈਕਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਉ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ ਹੈਲੀਫ਼ੈਕਸ 'ਚ ਸਿਰ-ਮੂੰਹ ਮੁਨਵਾ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਭੇਸ 'ਚ ਗੁਮਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੱਸਮਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹਨ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਰਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖ਼ਬਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰੂਪੋਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਉ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਪ੍ਰੋ: ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ... ਜਾਂ ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ... ਲਾਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰ... ਬੇਪਛਾਣ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀ... ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੰਸ਼ 'ਚੋਂ ਪਹੁਵਿੰ... ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ 1982 ... ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕ... ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ 1962, 6... ਤੇ 1971 ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰ... ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰ... ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 197... ਦੇ ਜੰਗੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾ... ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰੁਲਣ ... ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਪਿਛ... ਸਮੇਂ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਨਿਹੰਗ ਆ... ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ ਦੇ ਵਿਰੁ... ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ... ਸਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿ... ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

> ਸਿਰ-ਮੂੰਹ ਮੁਨਵਾ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਭੇਸ 'ਚ ਗੁਮਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ : ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਕਈ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ (ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ): ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਰਥਾਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਔਲਖ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਰਦੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖਾੜਕੂ ਜਿਸ ... 1993 ਨੂੰ ਇਕ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੜਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ।

ਭੱਟੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੁੰਡਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਸੀ.ਐਫ਼. ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟਾ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਖਾੜਕੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁੰਡਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 1993 'ਚ ਰੋਪੜ 'ਚ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ

Rozana Spokesman
11 April 2007

ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਜ) : ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ, ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਧ ਸੁਖੀ ਨਾਂ ਦੇ ਕੈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਮਗਲ ਕਰ ਘਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ 70 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀਉਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਕੈਟ ਵਲੋਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁਕਣ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਘਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ.ਐਮ.ਓ. ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਣਪਛਾਤੀਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ.ਐਮ.ਓ. ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

HINDUSTAN TIMES
TUESDAY, APRIL 10, 2007

Police 'cat' smells a rat

Tari claims crime-cop nexus; govt told to report

Amit Sharma
Ludhiana, April 9

TAKING COGNISANCE of a letter sent by Punjab Police "cat" Avtar Singh Tari, the Union Home Ministry has asked the Punjab government to look into his accusations against certain top cops of "using" him for "stage-managing" encounters, terror attacks and kidnappings to win gallantry awards.

Offering to expose the "police-criminal" nexus, Tari, lodged in Ludhiana Central Jail in connection with a 2001 opium smuggling case, has named some IPS officers as being among the "beneficiaries of fake operations" masterminded by him.

He has written about how the officers allegedly gave him Punjab Police identity cards, weapons, official vehicles and authority letters to facilitate his operations.

Sources said acting on Tari's letter, Y.P. Dhingra, an Under Secretary with the Union Ministry of Home Affairs, wrote to the Punjab government to look into the allegations.

Following the MHA's directions, the Punjab DGP has been asked to submit a report, said sources.

Tari, listed as a "hardcore criminal" in Punjab Police records, asserted that he feared a threat to his life since he had spoken out against some IPS officers.

In his letter, a copy of which is with *Hindustan Times*, Tari said during anti-terrorist operations he teamed up with several police officers, resulting in the arrest of "dreaded terrorists". "In turn, while cops won accolades, I was allowed free movement. But once the days of terrorism were over, the cops started utilising my services and links with anti-social elements perhaps to win laurels and gallantry medals," he said.

Claiming to have got proof of how police officers had been "masquerading" him as a Punjab Police officer to send him to the Indo-Pak border to smuggle arms and drugs, he also sent a number of DO letters, police identity cards and details of security cover, which he alleged, were provided to him by officers to smuggle arms and ammunition from militant outfits in Jammu and Kashmir.

"The smuggled weapons were later shown as recoveries from notorious gangs operating in Punjab," he alleged.

Tari also produced authority letters issued by two top police officials describing him as the "most loyal" and "trustworthy" person.

One of these letters issued by an SSP in 2004 stated that Tari was being sent on a "secret mission" to J&K and no one should harass or stop him.

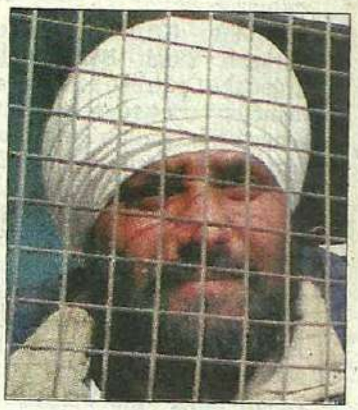

'Cat' system

The "cat" system, developed during the days of Punjab militancy, involved the use of specially recruited infiltrators and captured terrorists as intelligence assets for tracking down listed terrorists

Back to Sukhi

Tari said the previous government's "open patronisation of Sukhwinder Sukhi", a terrorist-turned-cat declared dead on papers, made him take the "extreme step of exposing the cops". Talking to *HT* during his appearance in a local court, he said, "Sukhi was one among us who facilitated killings and arrests of terrorists, but today, while we're treated as criminals, he is given red carpet treatment. This perturbed me and I decided to expose the cops."

ROZANA SPOKESMAN 3 APRIL 2007

ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਗੜੁਪ

ਹੇਡਿਆਇਆ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ): ਅਰਮੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 2097 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 25000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1997 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 11 'ਤੇ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਗੜੁਪ

ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਸੈੱਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਖ਼ੂਨੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਸਟਾਰ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੂਹੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਫਹੇ ਨਾ ਰਖੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 12-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੜਨ ਦੇ ਭਰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

DAINIK BHASKAR
13 MARCH 2007

इंसाफ की जंग चलती रहेगी

शम्मी सरीन, अमृतसर

वक्त के थपेड़ों ने 50 वर्षीय परमजीत कौर खालड़ा के दिल और दिमाग को इस कदर सख्त बना दिया है कि अब कोई धमकी, दबाव और लालच का उन पर असर नहीं होता। पति जसवंत सिंह खालड़ा की कथित हत्या के बाद इस दिलेर महिला ने पुलिस पीड़ित परिवारों की मदद को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया।

स्थानीय कबीर पार्क स्थित उनकी साधारण सी रिहायश पर हर रोज कई महिलाएं अपनी व्यथा सुनाने आती हैं और वे अपने बुलंद इरादों से उनके बुझे मन को फिर से रौशन करने का यत्न करती हैं। वह कहती हैं, जुल्म के खिलाफ चुप रहना, जीते जी मरने जैसा है। इसलिए मैने ताउम्र इंसाफ की लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। परमजीत कौर अपनी संस्था खालड़ा मिशन कमेटी की सहायता से आतंकवाद के दौरान कथित फर्जी मुठभेड़ों के दौरान मारे गए 1300 युवकों के परिवारों को ढाई लाख रुपए तक का मुआवजा दिला चुकी हैं। ऐसे ही करीब 800 परिवारों को सरकारी सहायता दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा ने जून 1995 में अमृतसर, तरनतारन और मजीठा के श्मशामघाटों में 1984-1994 के दौरान लावारिस बताकर जला दिए गए 2097 युवकों की सूची कैनेडा की पार्लियामेंट में पेश करके पंजाब पुलिस, प्रशासन और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। 27 जून 1995 को खालड़ा वापस देश लौट आए। 31 अगस्त 1995 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को चंडीगढ़ में बम से उड़ा दिया गया। इस केस में 6 सितंबर 1995 को पुलिस खालड़ा को घर से उठा ले गई। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चल सका। इस बीच झब्बाल पुलिस स्टेशन में तैनात एक एसपीओ कुलदीप सिंह ने रहस्योद्घाटन किया कि पुलिस ने खालड़ा को मार कर उसकी लाश को दरिया में बहा दिया। जसवंत सिंह खालड़ा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ परमजीत कौर को 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने के आदेश दिए, बल्कि एक डीएसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को सात साल से लेकर उम्रकैद की सजा

परमजीत कौर खालड़ा (50 वर्षीय)। -भास्कर

सुनाई। परमजीत कौर का कहना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उनके पति की सूची को आधार बनाकर सीबीआई को सारे मामले की जांच के आदेश दिए। सीबीबाई ने अपनी जांच के दौरान 582 शवों की पूर्ण, 278 की आंशिक और 1237 शवों को अज्ञात करार दिया। इस मामले में खालड़ा मिशन कमेटी ने अपनी मेहनत से लगभग 400 शवों की और पहचान कराई। यह कार्य अभी जारी है और लगता है कि सबूतों और हालात के मद्देनजर धीरे-धीरे सभी शवों की पहचान कर ली जाएगी। पंजाब सरकार ने इस 31 मार्च तक पहचान कर लिए सभी शवों के वारिसों को मुआवजा राशि अदा करने का वादा किया है। इससे पीड़ित परिवारों को उनके खोए प्रियजन तो नहीं मिलेंगे, मगर उनके जख्मों पर मरहम जरूर लग जाएगी।

HINDUSTAN TIMES
MARCH 4, 2007

FIRs supplied by police 'doctored'

Kuldeep Mann
Amritsar, March 3

THE JUSTICE K.S. Bhalla Commission, set up to identify people killed in alleged fake encounters in the state, today said the Punjab Police had submitted "doctored extracts" of FIRs demanded in this regard.

During the fourth hearing in the mass cremations case, Justice Bhalla (retd) noted that the police had provided incomplete information taken from 219 FIRs, which was not adequate to establish the identities of the missing persons.

In defence, counsel for the police said the majority of officials had been busy with the election process and had thus not been able to process the information.

Justice Bhalla subsequently directed the police to come out with full information to facilitate the identification.

HT PHOTO
Justice K.S. Bhalla in Amritsar on Saturday.

ILLEGAL CREMATIONS

The National Human Rights Commission (NHRC) has designated Justice Bhalla to establish the identities of 814 out of 2,097 missing persons so that the compensation of Rs 1.75 lakh to be paid by the government in each case could be handed over to the families.

However, the extracts of the FIRs were submitted by the police directly to the NHRC. The police had also submitted a list of 54 names, claiming they had identified those persons.

Meanwhile, a human rights organisation, the Committee for Information and Initiative on Punjab (CIIP), has filed a petition with the NHRC, saying the genuineness of the 54 identities submitted by the police was suspect.

The petition alleges the police have made certain bogus entries in the list. CIIP counsel Trideep Pais, deposing before the NHRC recently during a hearing in connection with the missing persons case, demanded an inquiry into the names.

Speaking to *HT*, Pais claimed the NHRC had taken serious view of his plea agreed to look into the mater.

A US-based human rights organisation, Insaaf, also pursuing the matter, had recently claimed that during a random check of five of the 54 cases, it had found that the claim regarding one — Mohan Singh of Bainka in Tarn Taran district — was bogus.

Insaaf activist Sukhman Singh, who is camping in India to monitor the case, personally visited Bainka to crosscheck the police list, and allegedly found that Mohan Singh had died of natural causes.

Sukhman Singh alleges that while the police have claimed that all 54 persons were killed in encounters, his visits to the families of three have revealed that they were first "picked up" by the police and killed subsequently.

kuldeepht@gmail.com

ਅਜੀਤ 5 FEB 2007

ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਆਪਣੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਐਸ. ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਸਵੀਰ : ਚਮਨ ਸਭਰਵਾਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤਕ 35 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸ਼ਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਸਵ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਸ. ਭੱਲਾ (ਰਿਟਾ:) ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ: ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾਇਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਡਾ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ: ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਸ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 3 ਮਾਰਚ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ: ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ 'ਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Police out with 'doctored' FIRs

Withhold names of officials involved in fake encounters

Kuldeep Mann
Amritsar, February 3

THE PUNJAB Police today came out with extracts of 219 FIRs of the 2,097 cases of illegal cremations during the hearing before the National Human Rights Commission-designated Justice K.S. Bhalla Commission here today. The police, however, withheld the names of officials involved in the infamous encounters during the period of militancy in the state.

The counsel of human rights organisations objected to the police providing "doctored information in the FIRs", but they were told that revealing full information, including names of police officials involved in encounters, could endanger their lives.

Members of the Committee for Information and Initiative on Punjab (CIIP), Punjab Human Rights Organisation (PHRO) and Lawyers for Human Rights International (LHRI) were shocked to find that in some cases, the police had killed people without even showing the recovery of weapons. CIIP convener Ram Narayan Kumar and human rights activist Jaswant Singh Khalra's wife Paramjit Kaur were among those present.

MUNISH BYALA/HT

Human rights researcher Ram Narayan Kumar, advocate R.S. Bains and other members of victim families during their appearance in front of NHRC Justice K.S. Bhalla (retd) at Amritsar on Saturday.

Justice Bhalla, however, turned down the plea of the rights activists to expand the scope of his inquiry from two crematoria in Amritsar and Tarn Taran to the whole of Punjab. He also rejected the plea of asking the state to furnish details of fake encounters to rehabilitate more than 300 police informers.

During the last two hearings, rights activists, including Sukhman Singh from US-based Insaaf, urged Justice Bhalla to provide them copies of the FIRs so that they could help the commission collect information about 814 missing persons.

While awarding compensation to 1,857 people to the tune of Rs 1.75 lakh each, the NHRC had recently appointed the Justice Bhalla Commission to ascertain information of the remaining 814 people within six months.

Advertisements were carried in newspapers to provide information to the commission so that all cases deemed fit for compensation could benefit. However, not much information on the missing persons could be gathered in the past two hearings.

The human rights groups, including the Association of Families of the Disappeared in Punjab, were not satisfied with Justice Bhalla's methodology in gathering information. Ram Narayan Kumar of the CIIP and Advocate R.S. Bains of the PHRO alleged that Justice Bhalla was "not adopting a foolproof strategy of gathering information so that only genuine people can get compensation".

"I am returning with a heavy heart," Kumar said, adding he would move the Supreme Court shortly in this regard.

HINDUSTAN Times
FEB 4, 2007

PUNJABI TRIBUNE SUN, 4 FEB 2007

ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤਰੀਕ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 219 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪੱਟੀ 'ਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

Rozana Spokesman 11 July 2008

ਖ਼ਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਰਮੇਸ਼ ਕਪਿਲਾ): ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਬੀਨਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ. ਗਿੱਲ

ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 11 'ਤੇ

ਖ਼ਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹ/ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹ/ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿੱਲ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

TRIBUNE 10 MARCH 2008

Khalra Murder

KMC tried to eliminate me: Prime witness

SANJAY BUMBROO
TRIBUNE NEWS SERVICE

AMRITSAR, MARCH 9
In a startling revelation a prime witness in the Jaswant Singh Khalra murder case today alleged that members of the Khalra Mission Committee (KMC) had tried to eliminate him by forcibly giving mercury a year ago.

SPO Kuldeep Singh Bachre, prime witness, alleged that KMC members had admitted him in a private hospital for treatment.

He said it was there that they, in connivance with some staff of the hospital, had tried to kill him by giving mercury. He said KMC men had taken this step as he had developed differences with the committee on certain issues.

However, Surinder Singh Ghariala, patron, KMC, refuted the allegation of Bachre stating that he (Bachre) had great expectations from them to get him reward from the Sikh community for his courage to speak out against the Punjab police.

He said Bachre had become a drug addict as earlier the police had provided him drugs so as to prevent him from speaking against them and had lost his patience and hence annoyed with leaders of the KMC.

Meanwhile Jabir Singh Padri, chairman, KMC, talking to Tthe Tribune on the phone said that Bachri had lost his mental balance and was now getting treatment from at mental hospital in Amritsar.

HINDUSTAN TIMES 13 FEB 2008

Gill not involved in Khalra murder: CBI

HT Correspondent
Chandigarh, February 12

PUNJAB'S FORMER Director General of Police K.P.S. Gill had no involvement in the murder of human rights activist Jaswant Singh Khalra, the Central Bureau of Investigation told the Punjab and Haryana High Court today.

Gill (top) and late Jaswant Singh Khalra

The reply was filed in response to a petition by Khalra's widow Paramjit Kaur, who had sought directions to the CBI to investigate the alleged involvement of Gill in the abduction and murder of her husband in 1995.

The CBI maintained: "There is no evidence to point out that Gill was involved in the case."

Paramjit Kaur had asserted that "hard evidence" had come on trial court records about Gill's involvement and had sought orders to the Continued on Page 9

A LOOK BACK AT CASE

- Khalra, who was collecting evidence about fake encounters and illegal cremation of bodies, was picked up by Amritsar police on September 6, 1995. He was kept in illegal custody and killed
- His widow Paramjit Kaur moved court, demanding a CBI inquiry. SC ordered it in 1996
- In 2005, Patiala sessions court indicted seven accused, two of whom had died
- After the appeal, in October 2007 the court sentenced surviving five to life imprisonment
- Through supplementary petition in 1996, Paramjit Kaur had also sought action against K.P.S. Gill

Gill not involved in Khalra murder: CBI

Continued from Page 1

CBI to investigate the conspiracy angle and his involvement in abducting, illegally detaining, torturing and murdering Khalra.

She had claimed that Gill was let off because of partial and incomplete investigation.

She contended that at least two representations were forwarded to the CBI director for completion of investigation in the murder case so Gill could be held accountable.

A Division Bench of the High Court, while convicting the cops involved, had held that Khalra was "abducted so his life could be extinguished". The court had held that Khalra was picked up from his house, tortured at Jhabal police station before being shot. Finally, his body was disposed of near the Harike bridge.

ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ 2008 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲੋਂ (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 2 ਕਾਲਮ 7)

ਅਜੀਤ 11 ਜੁਲਾਈ 2008

ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

(ਸਫ਼ਾ 1 ਦੀ ਬਾਕੀ)

ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

H. T. 11 July 2008.

KHALRA KILLING

HC notice to K.P.S. Gill

HT Correspondent
Chandigarh, July 10

THE DIVISION Bench of Justice M.M. Kumar and Justice Sabina of the Punjab and Haryana High Court today issued notice for September 9 to former Punjab Director General of Police K.P.S. Gill in a case pertaining to the alleged kidnapping and custodial death of Amritsar-based human rights activist Jaswant Singh Khalra.

Khalra had disappeared after he was allegedly picked up by the police in 1995.

The Bench issued the notice during the resumed hearing of the petition of wife of the deceased Paramjit Kaur Khalra, who had pleaded for registration of a criminal case and investigation by the CBI against Gill.

She had alleged that Gill was behind the conspiracy leading to the custodial death of her husband.

In order to bolster her argument, Kaur referred to the deposition made by witnesses during the trial of the case before the Special CBI Judge at Patiala.

In the post-Bluestar period, the deceased was instrumental in bringing to fore the issue of secret cremation of a large number of unidentified bodies by the police.

The CBI has time and again submitted before the High Court that during its investigation into the Khalra custodial killing, it did not come across any evidence linking Gill with this incident.

TRIBUNE 10 MARCH 2008

Khalra Murder

KMC tried to eliminate me: Prime witness

SANJAY BUMBROO
TRIBUNE NEWS SERVICE

AMRITSAR, MARCH 9
In a startling revelation a prime witness in the Jaswant Singh Khalra murder case today alleged that members of the Khalra Mission Committee (KMC) had tried to eliminate him by forcibly giving mercury a year ago.

SPO Kuldeep Singh Bachre, prime witness, alleged that KMC members had admitted him in a private hospital for treatment.

He said it was there that they, in connivance with some staff of the hospital, had tried to kill him by giving mercury. He said KMC men had taken this step as he had developed differences with the committee on certain issues.

However, Surinder Singh Ghariala, patron, KMC, refuted the allegation of Bachre stating that he (Bachre) had great expectations from them to get him reward from the Sikh community for his courage to speak out against the Punjab police.

He said Bachre had become a drug addict as earlier the police had provided him drugs so as to prevent him from speaking against them and had lost his patience and hence annoyed with leaders of the KMC.

Meanwhile Jabir Singh Padri, chairman, KMC, talking to Tthe Tribune on the phone said that Bachri had lost his mental balance and was now getting treatment from at mental hospital in Amritsar.

HINDUSTAN TIMES 13 FEB 2008

Gill not involved in Khalra murder: CBI

HT Correspondent
Chandigarh, February 12

PUNJAB'S FORMER Director General of Police K.P.S. Gill had no involvement in the murder of human rights activist Jaswant Singh Khalra, the Central Bureau of Investigation told the Punjab and Haryana High Court today.

Gill (top) and late Jaswant Singh Khalra

The reply was filed in response to a petition by Khalra's widow Paramjit Kaur, who had sought directions to the CBI to investigate the alleged involvement of Gill in the abduction and murder of her husband in 1995.

The CBI maintained: "There is no evidence to point out that Gill was involved in the case."

Paramjit Kaur had asserted that "hard evidence" had come on trial court records about Gill's involvement and had sought orders to the

Continued on Page 9

A LOOK BACK AT CASE

- Khalra, who was collecting evidence about fake encounters and illegal cremation of bodies, was picked up by Amritsar police on September 6, 1995. He was kept in illegal custody and killed
- His widow Paramjit Kaur moved court, demanding a CBI inquiry. SC ordered it in 1996
- In 2005, Patiala sessions court indicted seven accused, two of whom had died
- After the appeal, in October 2007 the court sentenced surviving five to life imprisonment
- Through supplementary petition in 1996, Paramjit Kaur had also sought action against K.P.S. Gill

Gill not involved in Khalra murder: CBI

Continued from Page I

CBI to investigate the conspiracy angle and his involvement in abducting, illegally detaining, torturing and murdering Khalra.

She had claimed that Gill was let off because of partial and incomplete investigation.

She contended that at least two representations were forwarded to the CBI director for completion of investigation in the murder case so Gill could be held accountable.

A Division Bench of the High Court, while convicting the cops involved, had held that Khalra was "abducted so his life could be extinguished". The court had held that Khalra was picked up from his house, tortured at Jhabal police station before being shot. Finally, his body was disposed of near the Harike bridge.